

प्रोफिशियन्सीका बोम ।
०—

भारतीय शासनपद्धति



प्रथम भाग ।

पंडित अमरुप्रसाद वाजपेयीद्वारा

संपादित और तन्पादित ।

— १२११२१ —

प्रकाशक

द्वि इण्डियन नेशनल पब्लिशर्स, लिमिटेड,

१० १५९ श्री मधुआबाजार स्ट्रीट

कलकत्ता ।



कलकत्ता, १६५ सी० मछुआवाजार स्ट्रीट,
इण्डियन नेशनल प्रेसमें
अम्बिकाप्रसाद वाजपेयीद्वारा मुद्रित ।

प्रथम संस्करणकी भूमिका ।



इस पुस्तकमें लेखकों मौलिक विचारोंका अभाव है, तथापि यह सग्रह मौलिक है और इसमें जो बातें लिखी गयी हैं, उनमें नवीनताकी न्यूनता नहीं है और न वे उपेक्षा करने योग्य ही हैं। किस रीतिसे भारतका शासन होता है और किस अधिकारीको कितने और कैसे अधिकार प्राप्त हैं यही इसमें बताया गया है। नियमोंका कहातक पालन होता है और इस पद्धतिमें कैसे और कितने सुधारोंका प्रयोजन है इसपर कुछ भी नहीं कहा गया है।

यह पुस्तक विशेषकर उन पाठकोंके लिये ही लिखी गयी है, जो समाचारपत्र पढ़ते हैं, पर इससे विद्यार्थी भी लाभ उठा सकते हैं और जो भारतकी शासनपद्धतिके विषयमें कुछ भी नहीं जानते, वे भी उसका बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिपिमें सर कोर्टने इलस्ट्रेटड "गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया", श्रीयुक्त रंगस्वामी आयरकरके "इण्डियन कांस्टिट्यूशन" और अज्ञापक कालेके "इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेशन" ग्रन्थसे विशेष सहायता ली गयी है। इनके सिवा अन्य पुस्तकोंका भी यत्किञ्चित् उपयोग किया गया है। इन सबके लेखकोंका मैं कृतज्ञ हूँ।

कलकत्ता,
मि० ज्येष्ठ शु० ५ स० १९७२



अविरामप्रसाद वाजपेयी ।

द्वितीय संस्करणकी भूमिका ।

—१७७४—

आठ वर्षमें संसारमें बड़े उलट पुलट हो गये और भारतकी शासनपद्धति भी उससे बचने नहीं पायी । १९१६ के गवर्न-मेंट आब इण्डिया ऐक्टके अनुसार यहांकी शासनपद्धतिमें जो परिवर्तन हुए हैं, उनका यथास्थान इस पुस्तकमें उल्लेख किया गया है । परन्तु प्रथम भागमें ऐसी बातें बहुत कम हैं, तो भी उनकी उपेक्षा नहीं की गयी है और पुस्तकको सामयिक बनानेकी ओर विशेष ध्यान रखा गया है ।

कलकत्ता
शुद्ध ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी
संवत् १९८० वि०

}
}
}

अबिकाप्रसाद बाजपेयी ।

विषयसूची

प्रथम अध्याय ।

पृष्ठ

उपोद्घात—भारतमें विदेशी, ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी स्थापना, भारतमें कम्पनीकी कोठिया, चटगाव छीननेकी चेष्टा, फरासीयोंसे झगडा और उच्चाभिलाष, दो कम्पनियोंका झगडा, भारतकी राजनीतिक दशा, अङ्गरेजों और फरासी-सीयोंकी लडाई, प्लासीकी लडाई, साम्राज्यकी नींव पड़ी, बङ्गालपर कम्पनीकी प्रभुता, पानी पतकी लडाई और मराठोंका पतन, हिन्दुस्थानमें गदर, कम्पनीको कौन प्रदेश कर मिला, कम्पनीकी प्रभुताका अन्त और भारतके राजनीतिक विभाग ।

१—२५

द्वितीय अध्याय ।

इंग्लैंडमें भारत शासनन्यूनस्था—कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स, भारतके राज्यका अधिकारी कौन ? रेगुलेटिंग ऐक्ट, बोर्ड आफ

कंट्रोल, बोर्ड के अधिकार, बोर्ड की निरीक्षणपद्धति, प्रति २० वर्ष पर पूरी जांच, भारत का शासक कौन है, भारत सचिव और कौन्सिल, इण्डिया कौन्सिल और उसका संघटन, हाई कमिशनर, कौन्सिल के अधिवेशन और मेटिंगों का अधिकार, कौन्सिल की कमिटियाँ और उनका कार्य, इण्डिया आफिस, इण्डिया आफिस का कार्यविभाग, पार्लमेंट और भारत सरकार।

२६—४६

तृतीय अध्याय ।

भारत सरकार—भारत सरकार की परिभाषा, गवर्नर जनरल के पहले की व्यवस्था, गवर्नर जनरल और कौन्सिल के अधिकार, भारत के सुशासन का उत्तरदाता कौन है ? प्रदेशों की शासन व्यवस्था, कौन्सिल संघटन का इतिहास, भारत सरकार के अधिकार, भारत सरकार का कार्य, विभागों की व्यवस्था, विभागों के काम, सरकार की शासन व्यवस्था और गवर्नर जनरल के अधिकार।

५०—७३

चतुर्थ अध्याय ।

प्रादेशिक सरकारें—प्रादेशिक सरकारें और उनका नियन्त्रण, प्रादेशों का इतिहास, शासन-

पद्धतियोंमें भेद, प्रेसिडेन्सियोंकी विशेषता, प्रादेशिक सरकारोंकी अवस्था, चीफ कमिशनर, रेगुलेशन और नान रेगुलेशन प्रदेश और प्रादेशिक सरकारोंके अधिकार ।

७३-६७

पंचम अध्याय ।

जिलेकी शासनव्यवस्था—कलेक्टरका महत्व, जिला और जिलेका हाकिम, कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट, सब डिवीजन और तहसीलें, कमिशनर और रेवेन्यू बोर्ड जिलोंका कार्यविभाग और सिविल सर्विस और सिविलियन ।

६७—१००

षष्ठ अध्याय ।

न्यायालयोंके कार्य और अधिकार—मेयर्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, चीफ कोर्ट और जुडिशल कमिशनर, दीवानी अदालतें, फौजदारी अदालतें, यूरोपियन ब्रिटिश सग्जेक्टका विचार, कानून, अपील करनेका अधिकार और सरकारके कानूनी सलाही ।

१०१—११४

सप्तम अध्याय ।

पुलिस और जेल—पुलिस और जेलका प्रयोजन, बङ्गाल पुलिसका पहला सघटन, अन्य

प्रदेशोंकी पुलिसका संघटन, पुलिस कमीशन,
 पुलिसका संघटन, सशस्त्र और अशस्त्र पुलिस,
 पुलिसके अधिकार और व्यय, जेलोंकी व्यवस्था,
 तीन प्रकारकी जेलें, कैदियोंका काम, लडके
 कैदियोंका प्रबन्ध, कालेपानीकी व्यवस्था और
 राजनीतिक कैदी ।

११५—१३६



भारतीय शासन-पद्धति ।



प्रथम अध्याय ।



उपोद्घात ।

हमारे देशमें यूरोपियनोंका पहले पहल आना व्यापार वाणिज्यके कारण ही हुआ था । कई भारतमें विदेशी । हजार वर्ष पहले अरबवाले हमारे देशकी चीजें यूरोप ले जाते थे । हिन्दुस्थानके व्यापारसे मालामाल होनेके लिये सिकन्दरने इस देशपर आक्रमण किया था । अरबोंसे भी पहले टायर और साइडनके फिनिशियन लोगोंके और उनके बाद यूरोपके जेनोआ, वेनिस आदि राज्योंके हाथमें यूरोपको भारतीय वस्तुएँ पहुँचानेका काम रहा । पोर्चुगालवालोंके उद्यमके बृहस्पति आये, तो चास्को डी गामाने सन् १४९८ में अफ्रिकाके गुडहोप नामके अन्तरीपकी परिक्रमा करके भारत आनेका मार्ग ढूँढ़ निकाला । पोर्चुगालका सितारा जल्दी ही डूबा और स्पेनवालोंकी बढ़ती हुई । पर १५९८से स्पेनका साम्प्रदायिक भगड़ा छिड़ा,

जिससे समस्त यूरोप प्रोटेस्टैंट और कैथोलिक सम्प्रदायोंमें बंट गया । स्पेनने इङ्ग्लैण्डपर आक्रमण करनेको अपना जहाजी बेड़ा भेजा, पर सन् १५८८में इङ्ग्लैण्डने इसका तहसनहस कर डाला । १६ वीं ईसवी शताब्दीमें हालैण्ड भी स्पेनकी पराधीनताको घेड़ी तोड़ चुका था । इससे स्पेनके हाथसे पूर्वका व्यापार छीननेके लिये वह इङ्ग्लैण्डका साथी हुआ । इसपर स्पेन और हालैण्डकी घमासान लड़ाइयां हुईं, जिनमें स्पेनको नीचा देखना पड़ा । अङ्गरेज व्यापारियोंने भारतमें व्यापार करनेके लिये इसी समयसे उद्योग प्रारम्भ किया, पर वे सफलमनोरथ न हुए ।

सन् १५८३ में सीरिया (शाम) और ईरानकी राहसे चार अङ्गरेज ईस्ट इण्डिया हिन्दुस्थान आये थे । इनमें एक तो साधू हो गया, दूसरा मर गया और तीसरेने अफसर बादशाहकी नौकरी कर ली थी । पर फिच नामक चौथा अङ्गरेज १५९१ में इङ्ग्लैण्ड पहुँचा और इसने अपने प्रवासके विषयमें एक पुस्तक लिखी । स्टीवेन्स नामक अङ्गरेज पोर्चुगालियोंके साथ लिसबनसे गोआ आया और इसने अपना जो भ्रमणवृत्तान्त लिखा, वह थड़े धावसे पढ़ा गया । अब अङ्गरेजोंकी भारत आनेकी इच्छा अधिक बलवती हुई । पर इन्होंने सोचा कि थोड़ी पूँजी लेकर जाना और अपने धनजनकी रक्षाका प्रयत्न न करना बड़ी भारी भूल है । इसलिये इङ्ग्लैण्डके कुछ धनी महाजनोंने

अपनी रानी एलिजाबेथसे प्रार्थना की कि हमें हिन्दु-स्थानसे व्यापार करनेका इजारा देकर उत्तेजन दीजिये । अङ्गरेज इस प्रकार अगर मगरमें पड़े ही थे कि डच लोगोंने साहस-पूर्वक, गुडहोप अन्तरीपके मार्गसे एक जहाज, हिन्दुस्थान भेज दिया । इधर सन् १६०० के ३१ दिसम्बरको उस प्रार्थनाके अनुसार, २१५ व्यापारियों और कम्बरलैण्डके थर्लको "गवर्नर पेण्ड कम्पनी आच वि मर्चेण्ट्स ट्रेडिंग टु दि ईस्ट इण्डीज" नामपर फर्मान दिया । यह कम्पनी चाहे जितनी जमीन खरीद सकती थी और एक गवर्नर और २४, मेम्बरोंकी कमिटीको इसकी ओरसे कारगर करनेका अधिकार दिया गया । इसे प्रति वर्ष छ अच्छे जहाज भेज करने अधिकार मिला । चार वर्षतक इसके लाये मालपर चुनी माफ रही । यह अपने एक जहाजपर ३० हजार पीण्ड या इन्नेका सोना चादी ले जा सकती थी । अब क्या था, डच और अङ्गरेज दोनों जानियोंने स्पेनियोंकी जड़ फाटनी प्रारम्भ की । सर टामस नाइट कम्पनीके पहले गवर्नर नियुक्त हुए थे । इस कम्पनीका मूल धन ७२,००० पीण्ड और एक शेयर ५० पीण्डका था ।

डच लोगोंने मसालोंके टापुओंपर अधिकार जमा लिया और वे यूरोपमें मनमाने भावपर मसाले भारतमें कम्पनीकी बेचने लगे । १६०२ की २३री मईको कोठिया । अङ्गरेज व्यापारियोंका वेड, इङ्गलैण्डस चला और सुमत्रा, जावा और अम्बोयना टापुओंसे रेशमी

कपड़े, मलमल, नील, लौंग आदि लादकर लौट गया । १६०८ में घटम और मलक्के के अङ्गरेज कर्मचारियोंने अपनी कम्पनीकी लिप्ता कि इन टापुओंमें हिन्दुस्थानके कपड़ोंकी बड़ी खपत है, इसलिये सूरत और एम्भातमें कोठिया खोलनी चाहिये । इसपर १६०६ में एक बड़ा हिन्दुस्थानको रवाना किया गया, जिसे अदन और मोचाके बीच तुकों ने पकड़ लिया और कतान सहित ७० आदमी कैद कर लिये । अङ्गरेज व्यापारी इससे भी न घबराये और १६११ में पोर्चुगालियोंको हराकर 'उन्होंने' सूरतमें कोठी खोली । ३॥ सैकड़े चुंगी देकर व्यापार करने और सूरत, अहमदाबाद, एम्भात और गोएमें कोठियां खोलनेकी आज्ञा तो जहांगीर बादशाहने पहले ही दे दी थी, पर ११ जनवरी १६१३ को फर्मान भी दे दिया । १६१५ में इङ्ग्लैण्डके बादशाह जेम्सका भेजा हुआ दूत सर टामस मनरो जहांगीर बादशाहके दरबारमें आया और कम्पनीके व्यापारके लिये और भी सुभीते करा गया । १६१६ में कालीकट और मछलीपट्टनमें अङ्गरेजी कम्पनीकी कोठियां खुलीं । १६२४ में कम्पनीको अपने नौकरोंका न्याय करनेका भी अधिकार मिल गया । अंगरेज डा० वाटनने बादशाह शाहजहाको लडकीको आराम कर दिया था, इसलिये अंगरेजी कम्पनीको बिना चुंगी दिये व्यापार करनेकी आज्ञा भी मिल गयी । बगालके नवाबने अंगरेज मात्रको बिना चुंगी दिये व्यापार करनेका अधिकार दे दिया, इसलिये कम्पनीके सूरतवाले गुमाश्तोंने हुगलीमें कोठी

खोली । १६३६ में मद्रासके किले फोर्ट सेंट जार्जकी नींव पड़ी । -

इस बीचमें स्पेन तो सर्वथा परास्त हो गया और पूर्वी
 चटगाव छीननेकी देशोंके व्यापारसे मालामाल होनेकी
 यासना उसे त्यागनी पड़ी । पोर्चु-
 गेला । गाल भी डचों और अंगरेजोंकी मार

न सह सका और उसके अधिष्ठित अनेक स्थान डच ईस्ट इण्डिया
 कम्पनी दबा बैठे । जब मैदानमें कोई प्रतिस्पर्द्धा न रहा, तब
 डच और अंगरेज आपसमें लड़ने लगे । पोर्चुगालसे दहेजमें
 बादशाह दूसरे चार्ल्सको चम्पई टापू मिला और १६६२में वह
 अंगरेजी कम्पनीके हाथ आ गया । अब अंगरेजी कम्पनीकी
 प्रतिपत्ति बढ़ने लगी । पर इससे उसका साहस भी बढ़ा,
 जिससे वह हाथ बढ़ाने लगी । कई वर्ष बाद कम्पनीके कर्म-
 चारियोंके अनुचित और असभ्य व्यवहारके कारण औरंगजेब
 बादशाहने सूरतसे कम्पनीके कारिन्दोंको मार भगाया, चम्पई
 घेर लिया और विजगापट्टन तथा दूसरे स्थानोंकी कोठिया छीन
 लीं । इस समय अंगरेज चतुर हो गये थे, इस लिये हाथ पैर
 पकड़ नजर न्याज दे उन्होंने अपना पीछा छुड़ाया । पर
 अंगरेज यह अपमान सह न सके और इसका बदला उन्होंने
 दूसरे ढंगसे लिया । १६८५-८६ में कप्तान निकलसनकी
 अध्यक्षतामें १२ से ७० तोपवाले दस जहाज और पैदलोंकी
 ६ कम्पनियां बिना कप्तानोंके, जिनकी जगह बट्टाल कौन्सिलके

मेम्बर भर्ती हुए, यह आशा देकर इंग्लैंडसे भेजी गयीं कि चटगांव छीनकर किला बना लो। इस काममें अंगरेजोंको सफलता न हुई और हानि उठाकर उन्हें भागना पड़ा।

अंगरेजों और डचोंको मालामाल होते देख फरासीसियोंके

फरासीसियोंसे झगडा मनमें भी हिन्दुस्थानके व्यापारसे लाभ उठानेकी धुन समायी और १६६४ में और उच्चाभिलाष । फ्रेञ्च ईस्ट इण्डिया कम्पनी स्थापित

हुई। उधर डचो और अंगरेजोमें मारकाट मचनेसे फ्रांसकी घन आयी। अब लडाकोने देखा कि हमारी लडाईसे और लोग माल मारे लिये जाते हैं। उधर लडाईसे दोनों राष्ट्र निर्बल भी हो गये थे, इससे वे फरासीसियोंकी ओर झुक पड़े। यूरोपमें डचों और फरासीसियोंकी लडाइया छिड़ जानेसे हिन्दुस्थानमें अंगरेजोंकी घन आयी और इन्होंने अच्छी तरह यहा अपना व्यापार जमा लिया। कलकत्ते, बम्बई और मद्रासमें ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी कोठियां स्थापित हुईं।

उधर कम्पनी तो कुठ और ही सोच रही थी, उधर उसके

कार धारकी पोल खुलनेका समय आने दो वपनियोंका झगडा। लगा। १६६५ में पार्लमेंटको एवर-

लगी कि कम्पनीका प्रबन्ध ठीक नहीं है और किसी समय इसका दिवाला हो जायगा, क्योंकि इंग्लैंडमें उसका खर्च १,२०० पौण्डसे ६०,००० पौण्ड बढ़ गया था। इससे कम्पनीके गवर्नर सर टामस कुकको डरानेके

लिये पार्लमेंटमें एक बिल (बिल ऑफ पेन्स ऐण्ड पेनल्टीज) पेश किया गया, जिसके पास हो जानेपर उन्हें शारीरिक और आर्थिक दण्ड दिया जाता, क्योंकि उनकी ही आज्ञासे कम्पनी चर्च करती थी । इसी समय मालूम हुआ कि इससे १०,००० पौण्ड तो स्वयं महाराज तृतीय विलियमने और ५,००० पौण्ड लीड्सके ड्यूकने घूसमें लिये हैं । ड्यूकपर मामला चला, पर यादशाह विलियमने जाच न होने दी, और इस घूसखोरीका पूरा भेद न प्रकट हो सका । इधर इससे किसी प्रकार पीछा छूटा, तो उधर कम्पनीकी प्रभुता देख कुछ अगरेज व्यापारियोंने उसका इजारा छिनचा लेनेकी चेष्टा आरम्भ की । १६६८ में इन्होंने महाराज विलियमकी रानी मेरीके दिये हुए १६६४ के फर्मानको पार्लमेंटमें ला उपस्थित किया और कहा कि हम ८) सैकड़ों व्याजपर २० लाख पौण्ड सरकारको ऋण देनेको तैयार हैं, यदि हमें पूर्वी देशोंके व्यापारका इजारा दे दिया जाय । कम्पनी ७ लाख पौण्ड ४) सैकड़ोंपर देती थी, इस लिये नयी कम्पनीकी जीत हुई और उसके पक्षमें बिल पास हो गया । अब दो ईस्ट इण्डिया कम्पनियां हो गयीं । सन् १७०० में दोनों कम्पनियोंने पार्लमेंटके हाउस ऑफ कामन्सको अपनी ओर करनेकी चेष्टा प्रारम्भ की । एक कम्पनी मेम्बरोंको घूस देने लगी, दूसरी मतदाताओंको । अन्तमें दोनों "यूनाइटेड ईस्ट इण्डिया कम्पनी" नामसे मिल गयीं ।

शाहजहाँ के तत्तसे उतरते ही मानों मुगल साम्राज्यपर भारतकी राजनीतिक साहसाती शनिधर आ गये । औरङ्गजेब दिल्लीके तख्तपर बैठते ही हिन्दुओंके दशा ।

नाकों दम करने लगा । दक्षिणमें

शिवाजी महाराज गोलकुण्डे और बीजापुरकी रियासतोंपर अपना क्राय जमा ही चुके थे । इससे औरङ्गजेबने इनके दमनका उद्योग आरम्भ किया, पर सब प्रकारसे उसे नीचा देपता पडा । हिन्दुओंका जोर मराठोंके कारण दक्षिणमें और सिक्खोंके कारण उत्तरमें बढा, जिससे मुगल साम्राज्यके नाशका सूत्रपात हुआ । औरङ्गजेब कुछ राजपूत-राजाओंको मिलाये रहता था इससे उसने मरते दम तक मुगल साम्राज्यका नाश न होने दिया, पर १७०७ में उसके मरते ही मानों मुगल साम्राज्यका आधारस्तम्भ टूटकर गिर पडा । उत्तराधिकारीमें न तो शूरता थी और न राजनीतिज्ञता, इससे धीरे धीरे तीन बड़े प्रदेशोंके सूबेदार नाम मात्रकी अधीनता स्वीकार कर सर्वथा स्वतंत्र हो गये । अवधके नवाब बजीर, हैदराबादके नवाब निजाम और बङ्गालके नवाब कहनेको तो नवाब थे, पर बादशाही करते थे । रुहेलखण्डमें रुहेले अफगान राज करते थे और दक्षिणमें कर्नाटक, अर्कट तंजावर, मैसूर आदि अनेक छोटे मोटे राज्य थे । इनका कोई सिरधर न होनेसे इनमें जब कभी राज्यके लिये लड़ाई छिड़ती, तो उसकी मध्यस्थता अंगरेजों या फरासीसियोंको ही करनी पडती थी ।

अंगरेजों और फरासीसियोंका सैकड़ों वर्षों का वैर था, इस अंगरेजों और फरासी- लिये अंगरेजोंकी समृद्धि फ्रांसको बहुत सटकती थी । हिन्दुस्थानके व्यापारके सियोंकी लड़ाई । मैदानमें ये दो ही जातियाँ रह गयी

थीं, क्योंकि स्पेनिये और पोर्चुगालिये तो पहले ही अस्त हो चुके थे, और डच लोगोंने सिङ्गल, जावा और मसालेके टापुओं- पर ही सन्तोष करना उचित समझ लिया था । इधर पुरानी शत्रुता होनेके कारण यदि इङ्ग्लैण्ड और फ्रांसकी लड़ाई यूरोपमें होती, तो हिन्दुस्थानमें भी छिड़ जाती । दोनोंमें हिन्दुस्थानमें अपना साम्राज्य स्थापित करनेकी होड़सी लगी थी । जब किसी देगी राज्यका राजा मरता और गद्दीके लिये दो दावादार पड़े होते, तो एकको अंगरेज और दूसरेको फरासीसी मदद देने लगते । जब यूरोपमें शान्ति होती, तो यहाकी लड़ाई भी बन्द हो जाती । १७४५ के लगभग यूरोपमें अंगरेजों और फरासीसियोंकी लड़ाई छिड़ी । हिन्दुस्थानमें भी उक्त कम्प नियोंने लड़ना प्रारम्भ किया । पहली लड़ाई धूमधामसे कर्नाटकमें हुई । एजलाशेपेलकी सन्धिसे दोनों राष्ट्रोंका युद्ध तो बन्द हुआ, पर फ्रांसको विशेष आर्थिक हानि उठानी पड़ी, जिसका फल यह हुआ कि हिन्दुस्थानके फ्रीड्रिक् गवर्नर डूप्लेको यथेष्ट सहायता न मिली, पर तो भी वह हिम्मत न हारा और उसने कुछ ही दिन बाद हैदराबादके भावी निजाम और कर्नाटकके एक भावी नवाबको राज्य दिलानेकी चेष्टा प्रारम्भ

की। पहले तो इसमें उसे कुछ सफलता प्राप्त हुई, पर अंगरेजोंसे यूरोपमें हारने और फिर अमेरिकामें उन्हींके साथ ७ वर्षकी लड़ाई छिड़ जानेसे फरासीसियोंकी दाल यहां न गली। १७५४ में अंगरेज और फ्रेञ्च कम्पनियोंमें सन्धि हो गयी कि हिन्दुस्थानी राजघाटोंके भूगडोंमें कोई न पड़े और दोनों यहां प्रभुता करनेकी वासना त्याग दें। फरासीसियोंको लड़ाईमें जीते ४ जिले भी इस सन्धिके कारण लौटा देने पड़े। पर अंगरेजी कम्पनीको मुहम्मदअलीने इसके बाद ही आधी लूटका लालच दिगा, इससे उसने सन्धि तोड़ डाली। फ्रेञ्च कम्पनीने सन्धिकी बहुत दुहाई दी, परन्तु किसीने एक न सुनी।

अंगरेजी कम्पनीने कलकत्ता आदि कई गांव तो पहले ही

खरीद लिये थे, पर किला विला नहीं

फरासीकी लड़ाई। बनाया था। १७५६ में उसे किला

बनानेकी सुझी। बङ्गालके नवाब

सिराजुद्दौलाने मना किया, पर अब कम्पनीके कारिन्दे अपनेको

शेर समझने लगे थे। उन्होंने बन्दरघुडकी समझ नवाबके

हुकमकी तामील न की। सिराजुद्दौलाका खून नया था, वह

पहुत जल्द गर्म हो उठा। वह कलकत्तेपर चढ़ गया। सब

अंगरेज पकड़कर उसके सामने लाये गये, पर उसने किला न

बनानेकी प्रतिज्ञा कराके सबकी हथकड़ियां खुलवा दीं।

कम्पनीके एक नौकर हालवेलने सोचा कि इसकी शक्ति ही

कितनी है। इसके आदमियोंको फोड़ लेनेसे ही हम बङ्गालके

मालिक यन घैठेंगे । इससे उसने यह गौंगा उडोया कि सिराजु-
 हीलाने १४६ अंगरेजोंको जूनके महीनेमें एक पेम्बी छोटी
 कोठरीमें बन्द कर दिया जिसमें हवाकी पहुच न थी और इस
 लिये १२३ तो मुर्दा और बाकी २३ कुँड जिन्दा निकले ; पर
 उनकी हालत ऐसी हो गयी थी कि उनकी मा भी उन्हें न
 पहचान सकती । यह घटना इतिहासमें “ज्लैकहोल” वा
 कालकोठरीकी दुर्घटनाके नामसे प्रसिद्ध है । यस, सिराजु-
 हीलापर चढ़ाई करनेका यह कारण बताकर उसने घाटसन और
 झाइयको मद्राससे बुलाया । सिराजुहीलाके सिपहसालार
 मीरजाफर और सेठ अमीचन्द्र आदिको अपनी ओर मिठा
 झाइय आदि सिराजुहीलापर चढ गये । प्लासीमें दोनो
 ओरकी सेनाएँ एकट्ठी हुई । सिराजुहीलाकी सेनामें ५० हजार
 पैदल, १८,००० सवार और ५० तोपें थी । पर झाइयने सीक्रेट
 कमिटीको जो चिट्ठी लिपी थी, उसमें सिराजुहीलाकी सेनामें
 ३५ हजार पैदल, १५ हजार सवार और ४० तोपें बतायी थीं ।
 झाइयकी सेनामें ६०० गोरें थे, जिनमें १०० गोलन्दाज और ५०
 मल्लाह थे, १०० तोपची और २१०० सिपाही थे । इस लड़ाईमें
 २० यूरोपियन हताहत हुए तथा १६ सिपाही मरे और ७६
 घायल हुए । इनका कम रक्तपात क्यों हुआ, झाइयने इसके दो
 मुख्य कारण बताये हैं । पहला यह कि अंगरेजी सेना ऐसे
 ऊँचे टीलेके पीछे थी कि शत्रुकी तोपोंसे उसकी बहुत हानि न
 हो सकी । दूसरा कारण यह है कि न सिराजुहीलाका अपनी

सेनापर विश्वास था और न, सेनाका उसपर विश्वास था, इस लिये सेनाने उस अवसरपर अपना कर्त्तव्य पालन नहीं किया ।

इस प्रकार प्लासीकी लड़ाईमें अंगरेजी कम्पनीके जीत जानेसे बङ्गालमें उसकी तूती धोलने साम्राज्यकी नींव पड़ी । लगी । पूर्व निश्चयके अनुसार मीरजा-फर बङ्गालका नवाब बनाया गया ।

अब क्या था ? कम्पनीके नौकर चाकर मनमानी घरजानी कर रुपयोंसे अपनी जेबे भरने लगे । कम्पनीका खर्च बेतरह बढ़ा हुआ था । रुपयेकी तंगी चारों ओरसे थी । बङ्गालसे भी असंख्य रुपये मिलनेकी आशा न थी, क्योंकि मीरजाफरके नवाबी पाते ही उसके यारोंने उसे ऐसा दूहा कि उसका पजाना बिल्कुल पाली हो गया । अब जब उससे कम्पनीके कर्मचारी कहते कि रुपये दो, तो वह कहता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है । पर ये क्यों मानने लगते ? अन्तमें इन्होंने सोचा कि मीरजाफरको गद्दीसे उतारे बिना अब कुछ हाथ न लगेगा । इससे १७६० में हालवेल आदि कितने ही कर्म-चारियोंने मीरजाफरके विरुद्ध पड़्यत्र रचा । उसपर अभियोग लगाया कि उसने कई आदमियोंके सिर काटे कटवाये और कितने ही निरपराधियोंको कैद कर रखा है । इसी आशयका पत्र हालवेलने कम्पनीके डाइरेक्टरोंको लिखा और उसमें यह भी उन्हें सूचित कर दिया कि मीरजाफरको हमने गद्दीसे

उतार दिया है और उसके दामाद मीरकासिमको नवाब बनाया है। मीरकासिमने नवाबी पानेके लिये चटगांव, मेदिनीपुर और बर्धमान ये तीन जिले कम्पनीको दिये थे, इससे डाइरेक्टर भी कुछ न बोले और मीरजाफर रोता कलपता गद्दीसे राउत मीर। कासिमको कम्पनीके कर्मचारियोंने मीरजाफरसे भी गया बीता समझ लिया था, पर इसने उनके हाथकी पुतली बननेसे इनकार किया। अन्तको दोनोंका झगडा हुआ। मीरकासिम मुर्शिदाबाद छोडकर मुगेरमें रहने लगा। मामला पहातक बढ़ा कि मीरकासिम और अंगरेजोंकी लड़ाई बक्सरमें हुई। इस लड़ाईमें अवधके नवाब बजीरने मीरकासिमकी मदद की, पर अंगरेजोंकी जीत हुई। अवधके नवाबसे कम्पनीकी सन्धि हुई और फिर मीरजाफर गद्दीपर बैठाया गया।

बक्सरकी लड़ाईसे अंगरेजी कम्पनीका साहस और प्रभुत्व और भी बढ़ा। कम्पनीका जो दरबार बंगालपर कम्पनीकी विहारतक था, वह बनारस और प्रयाग तक हो गया। इसके साथ ही सन्

१७६५ में क्लाइवने दिल्लीके पानाबदोश बादशाह शाहआलमसे बङ्गाल, बिहार और उड़ीसेकी दीवानी कम्पनीके नाम लिखा ली और इस तरह सारा माली बन्दोबस्त कम्पनीके हाथ आ गया। साथ ही उत्तरी सरकारका वह प्रदेश भी इनाममे माग लिया, जो आजकल मद्रास प्रदेशके अन्तर्गत है। इस प्रकार अंगरेज बङ्गालमें जम गये और आगे बढ़नेका विचारे

करने लगे। कम्पनीको दीवानी मिलनेसे बङ्गालकी एक म्यानमें दो तलवारें हो गयीं। माली बन्दोबस्त कम्पनी करने लगी और दीवानी फौजदारी मामले मुकद्दमे नवाबके दरबारसे फैसल होने लगे। फौज भर्तों करनेका काम भी कम्पनीने अपने हाथमें ले लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद जब देखा गया कि यह प्रबन्ध ठीक नहीं है, तब मीरजाफरके लडके मीरनकी सालाना पेनशन कर दी गयी और कम्पनी बङ्गालमें “प्रभुमेवाद्वितीय” हो गयी।

महाराष्ट्रमें छत्रपति शिवाजी महाराजने भारतमें हिन्दू पानीपतकी लड़ाई साम्राज्यकी नींव डाली थी, पर उनके पुत्र शम्भूजीमें पिताकीसी योग्यता न थी, इसलिये हिन्दू साम्राज्य स्थापनका प्रयत्न उनके ब्राह्मण मन्त्रियोंको करना पड़ा। नाम मात्रके मराठे राजाओंके पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्टने समस्त राजकाज धरने हाथोंमें ले लिया और मराठोंके सिरधर बन गये। शिवाजीकी नीति बहुत कुछ बदल गयी और हिन्दू साम्राज्यके बड़े मराठोंके भिन्न भिन्न दलोंने कई प्रदेशोंपर अधिकार कर लिया और पेशवा, गायकवाड, शिन्दे (सेंधिया), भोंसले, और होलकरका एक सघ बना। किसी समय इस मराठा सघसे बहुत कुछ आशा थी, क्योंकि शिवाजी महाराजने ही दक्षिणात्यके कई प्रदेशोंपर अधिकार करके इसका मार्ग बहुत कुछ परिष्कृत कर दिया था। पर

महङ्गार और आपसकी फूटने, इसे कुछ विशेष करने न दिया। जो हो, पहले बाजीराव और गालाजी बाजीराव पेशवोंके समय मराठोंका प्रभाव दिल्लीतक हो गया था और ये जिसको चाहते थे, दिल्लीका बादशाह बना देते थे। इस प्रकार मराठोंका राज्य बहुत बढ गया था। उग्र दाक्षिणात्यमें भी हैदराबादके निजाम, और १७६० में मैसूरके यादवोंकी गद्दी छीननेवाले हैदरअलीके सिवा मराठोंकी गति रोकनेवाला कोई न था। शाहआलमको दिल्लीके तख्तपर बैठानेसे जब अंगरेजी कम्पनी और लखनऊके नवाबने इनकार कर दिया, तब ग्वालियरके राजा महदजी शिन्देने शाहआलमको साथ ले १७७१ में दिल्लीमें प्रवेश किया। रूहेलखण्ड लूट लिया। दिल्ली उनके अधिकारमें चली जानेसे मुसलमान तो मराठोंसे असन्तुष्ट थे ही, इससे अहमदशाह अन्धालीके आनेकी खबर सुनते ही हिन्दुस्थानके मुसलमान भी रुहेले अफगान नजीगुद्दीलाकी अधीनतामें मराठोंसे मोर्चा लेनेको तैयार हुए। १७७१ में पानीपतके मैदानमें सदाशिवराव भाऊकी अधीनतामें मराठोंकी अहमदशाहसे लड़ाई हुई और मराठे हारे। सदाशिवराव समझते थे कि अहमदशाहको हराना बड़ी बात नहीं है; जन चाहेंगे, हरा देगे। यस, ये तो इस ध्यानमें थे, उग्र अफगानोंने छापा मारा। मराठोंकी फौजपर एकाएक धावा हो जानेसे घब्रघबरा गयी। सदाशिवराव भाऊने जय देखा, कि अब हमारी हार हो गयी, तब हाथीसे उग्र पडे और न

जाने-कहा गायब हो गये । इस प्रकार हिन्दू साम्राज्यके स्थापनका विचार नष्ट हुआ । परन्तु मराठोंने जो राज्य बढा लिया था, वह कम नहीं हुआ । प्रभाव भी कुछ बना ही रहा । पर पूनेमें नारायणराव पेशवाकी हत्या सुनकर महदजी पूने आये और इसी हत्यासे मराठोंका प्रताप अस्त होने लगा । निजाम और हैदरअली तथा अंगरेजोंसे बार बार लड़नेके कारण मराठोंकी शक्ति बहुतकम हो गयी । अन्तिम पेशवा दूसरे याजीरावको पेंशन देकर कम्पनीने त्रिभूर भेज दिया । कुछ दिनों बाद नागपुरके भोंसलोंका-राज्य छीन लिया, क्योंकि अन्तिम राजा राघोजी भोंसलेके लडका न था । गायकवाड, होलकर और शिन्देसे कम्पनीकी सन्धि हो जानेसे ये तीन राज्य बच गये ।

दक्षिणमें मराठों और उत्तरमें सिक्खोंके सिवा कुछ समयके लिये भी अंगरेजोंकी गति रोकनेमें

हिन्दुस्थानमें गदर । कोई जाति समर्थ नहीं हुई थी ।

यद्यपि प्रारम्भमें गुरु नानकने सिक्ख सम्प्रदाय धार्मिक सुधारोंके लिये स्थापित किया था, तथापि मुसलमानोंके अत्याचारोंके कारण गुरु तेगबहादुर और उनके बाद गुरु गोविन्दसिंहने सिक्ख सम्प्रदायको राजनीतिक स्वरूप दिया और मुसलमानोंसे लड़नेके लिये सिक्ख सेना तैयार की । गुरु गोविन्दसिंहके बाद उनके शिष्य बन्दा बंशीदासने खालसेकी ओरसे मुसलमानोंके नाकों दम कर दिया

और क्रमशः दिल्लो और उसके आसपासके कुछ स्थानोंको छोड़ सारा पञ्जाब सिक्खोंके हाथ चला गया । रनजीतसिंहके समयतक सिक्खोंकी तूती चोलती रहो । पर उनकी मृत्युके बाद फूट और घैरकी जट मजबूत हुई और अङ्गरेजोंसे उनकी पहली लड़ाई हुई । इसमें सिक्खोंने वीरतासे लोहा लिया और अङ्गरेजोंको भी मालूम हो गया कि यह लड़ाई मामूली नहीं है । इस लड़ाईके बाद कुछ ही दिनोंतक शान्ति रही और दूसरी लड़ाई होते ही लार्ड डलहौसीने पञ्जाब ले लिया और महाराज दिलीपसिंहको पेंशन देकर इङ्ग्लैंड भेज दिया । इस प्रकार अटकसे लेकर कटकतक और कुमायूँसे लेकर कुमारिका अन्तरीपतक समस्त देशपर अङ्गरेजोंकी धाक जम गयी । १८५७ में अङ्गरेजी सेनाके सिपाहियोंने गदर मचाया । इसका प्रत्यक्ष कारण यह था कि जो फारतूस दातसे काटकर बन्दूकमें भरनेकी उन्हें आशा मिली थी, उनमें चर्चो लगी हुई थी । गदरका कारण कुछ लोगोंका पड़्यत्र और फारतूसोंकी चर्चोंके सिवा लार्ड डलहौसीकी राज्य हड़पनेवाली नीति भी थी । अवध, झाँसी, नागपुर और सितारेके राज्य इसके शिकार हुए थे । इस गदरसे अङ्गरेजोंकी जड हिल गयी थी, पर प्रजाकी सहायतासे अङ्गरेजी कम्पनी इस विद्रोहका दमन करनेमें समर्थ हुई और उस समयसे देशमें किसी प्रकारका क्रान्तिकारक उपद्रव नहीं हुआ ।

हमारे 'इम उपोद्घातका उद्देश्य सक्षेपसे इस देशपर कम्पनीको कौन प्रदेश अङ्गरेजोंके प्रभुत्वके इतिहासके माथ ही उस समयके भारतकी राजनीतिक वन मिला । अस्याका दिग्दर्शन कराना मात्र है ।

इस लिये अब यहा यही बताना बस होगा कि किस समय भारतके किस भागपर अङ्गरेजोंका अधिकार हुआ । किस प्रकार कौन प्रदेश अङ्गरेजोंके हाथ आया, यह बताना न तो इसका उद्देश्य है और न इनने अल्प स्थानमें यह सम्भव ही है । १७५५ में बङ्गाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी सरकार प्रदेशोंपर अङ्गरेजोंका अधिकार हुआ । १७७१ में राजा चैनसिंहसे चारन हेस्टिङ्गजने बनारस ले लिया । मैसूरके हैदरअली और टीपू सुल्तानसे लड़ने बाद १७६२ और १७६६ में बटुतसा प्रदेश और १७६६ में मैसूर का तजावरके राजाको पेंशन दे दी गयी और इस वर्ष तंजावरका राज्य, १८०० में निजामसे मिले हुए कुछ जिले और १८०१ में कर्नाटकके नवाबके भी पेंशन लेनेपर वह राज्य अङ्गरेजी कम्पनीको मिल गया । सारांश सन् १८०१ तक प्रायः समस्त मद्रास प्रदेशपर अङ्गरेजी कम्पनीका अधिकार हो गया । दसो वर्ष अवधके नवाब बजीरने कम्पनीको हलाहाबाद दे दिया और १८०३ में कम्पनीने आगरा, मथुरा, दिल्ली और वर्तमान उड़ीसा मराठोंसे जीत लिया । ये सब जिले बङ्गाल प्रेसिडेन्सीके अधीन हुए । १८०० और १८०५ के बीचमें मुरारके नवाब और गायकवाडसे सूरत, भडोच और खेडा

जिले मिले और बम्बई प्रेसिडेन्सीके अधीन किये गये । १८१५ में नेपाल युद्धके बाद देहरादून, कुमायूँ, गढ़वाल और शिमला कम्पनीके हाथ आये और बंगालमें मिलाये गये । इस वर्ष प्रायः समस्त पश्चिमोत्तर प्रदेश अङ्गरेजी कम्पनीको मिल गया । १८०२ से १७ के भीतर गायकवाडसे अहमदाबाद मिला और १८१८ में मराठोंसे लड़कर कम्पनीने महाराष्ट्रका बहुत बड़ा भाग और उत्तमान मध्यप्रदेशके कुछ जिले पाये । इसी वर्ष अजमेर मेरवाड़ेके जिले शिन्देसे मिले । १८१६ २७ के बीच निजाम और कोल्हापुरके महाराजसे अग्रशिष्ट महाराष्ट्र मिला । इस प्रकार सिन्धको छोड़ समस्त बम्बई प्रेसिडेन्सी १८१७ तक कम्पनीको मिल गयी । बर्माकी पहली लड़ाईके बाद १८२६ में आसाम, अराकान और टेनासरिमपर अङ्गरेजीने प्रभुत्व जमाया । आसाम और अराकान बंगालके साथ किये गये और टेनासरिम चीफ कमिश्नरके अधीन किया गया । इसी वर्ष वर्तमान बिहारके पश्चिमके मगध जिले बंगालसे अलग कर दिये गये और पश्चिमोत्तर प्रदेशके नामसे प्रसिद्ध हुए । एक लेफ्टिनेण्ट गवर्नरको इस प्रदेशका शासनभार दिया गया । १८३३ में छोटे नागपुरकी जंगली जातियोंने गदर मचाया, इससे इस प्रदेशको भी अङ्गरेजीने ले लिया और एस० डब्ल्यू० फ्राटियर एजेन्सीके अधीन कर दिया । पर १८५४ में यह भी बंगालमें मिला दिया गया । १८३४ में कुर्ग और १८२६ ३५ तक शिलांग तथा आसामके और भी कई पहाड़ी जिले

अंगरेजी राज्यमें मिलाये गये । कुर्गकी शासनव्यवस्था मैसूरके रेजिडेण्ट करने लगे और शिलांग आदि बंगाल प्रेसिडेन्सीमें मिलाये गये । १८३७में सितारेके राजा प्रतापसिंह गद्दीसे उतारे गये और उनका राज्य बम्बई प्रेसिडेन्सीके अन्तर्गत कर दिया । १८४०से भासी, जालौन और ललितपुर जिले पश्चिमोत्तर प्रदेशमें मिलाये जाने लगे । १८४३में सिन्ध, बहाके अमीरसे लेकर, बम्बईमें मिलाया गया । पहली सिक्ख लड़ाईके बाद १८४६में जालन्धरकी कमिशनरी अंगरेजोंके हाथ लगी । १८४६में पञ्जाब अंगरेजी राज्यमें मिला लिया गया । पहले तो पञ्जाबके शासनका भार एक (Board of Administration) शासकमण्डलको दिया गया, पर शीघ्र ही चीफ कमिशनरके और १८५६ में दिल्ली आदि कुछ जिलोंको मिलाकर लेफ्टिनेण्ट गवर्नरके अधीन कर दिया गया । बर्माधी दूसरी लड़ाईके बाद १८५२ में अराकान बंगालसे अलग किया गया और पेगू, टेनासरिम और अराकान तीनों जिले अलग अलग कमिशनरोंके अधीन किये गये और भारत-सरकारसे इनका साक्षात् सम्बन्ध रहा । १८५४ में नागपुरके भोंसलोका राज्य जब्त कर लिया गया और पहले पेगू आदिकी तरह कमिशनरके और बाद, पश्चिमोत्तर प्रदेशके दो जिले लेकर, १८६१ में मध्यप्रदेश नामसे चीफ कमिशनरके अधीन किया गया । १८५८ में पोर्ट ब्लेयर कालेपानीके कैदियोंको रखनेकी जगह बनायी गयी और इसीके, सुपरिण्टेण्डेण्टके

अधीन ऐण्डमन और निकोबारके टापू कर दिये गये। १८५६ में अवधके नयाव वाजिदअली शाह गद्दीसे उतार दिये गये और अवध चीफ कमिशनरके अधीन किया गया। १८६० में दार्जिलिंग और जलपाइगुड़ी जिले भूटानसे मिले और बंगाल प्रेसिडेन्सीमें मिला दिये गये। १८३५ और ६० की सन्धियोंके अनुसार निजामने कम्पनीको बरारके जिले दे दिये, पर बरार अङ्गरेजी भरतपण्डका प्रदेश नहीं बना। १८६१ में शिन्देने पञ्चमहालका जिला दिया और वह बम्बई प्रदेशके अन्तर्गत किया गया। १८६२ में लोअर बर्माका शासन चीफ कमिशनरको सौंपा गया। इस प्रकार बङ्गालके कुछ जिले देकर आसामकी भी चीफ कमिशनरी बनी। १८७४ में पश्चिमोत्तर प्रदेशके लेफ्टिनेण्ट गवर्नर अवधके चीफ कमिशनर भी कहाने लगे। १८८६ में अपर बर्मा अङ्गरेजी राज्यमें मिला लिया गया और लोअर बर्माके चीफ कमिशनरके अधीन किया गया। पर १८९७ में समस्त बर्मा लेफ्टिनेण्ट गवर्नरके शासनाधीन हुआ। १८८७ में ब्रिटिश बलूचिस्थानके लिये एक चीफ कमिशनर नियुक्त हुआ। १९०१ में पञ्जाबसे कुछ जिले निकाल लिये गये और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश बनाकर चीफ कमिशनरके अधीन किये गये। १९०३ में निजामने सदाके लिये अङ्गरेज सरकारको बरारका लीस (पट्टा) लिख दिया। १९०५ के अक्तूबरमें बङ्गालके कई जिले आसाममें मिला दिये गये और पूर्ण चंग और आसामका नया प्रदेश बनाया गया। १९१२ के अप्रैलसे बङ्गाल

और आसामका बटवारा हुआ । आसाम पहलेकी तरह चीफ कमिशनरके अधीन किया गया और बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर तीनों प्रदेश कौन्सिल सहित लेफ्टिनेण्ट गवर्नरके और पास बङ्गाल गवर्नरके अधीन हुआ । इसी वर्ष दिल्ली जिला और इधर उधरके कुछ गांव लेकर दिल्ली प्रदेश बना और चीफ कमिशनरके अधीन किया गया, पर घास्तवमें भारत-सरकारके अधीन रहा । १६२१में बिहार उड़ीसा, युक्तप्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश और आसाम भी गवर्नरके प्रदेश बनाये गये और इनमें भी शासन सभा स्थापित हुई । १६२२में चर्मा भी गवर्नरका प्रदेश बनाया गया । भिन्न भिन्न प्रदेशोंके अगरेजोंके अधीन होने और उनके बटवारेके समयका यह संक्षिप्त इतिहास है ।

१८५७ के गदरके बाद पार्लमेण्टकी सम्मतिसे इंग्लैण्डकी

कम्पनीकी प्रभुताका महारानी विक्टोरियाने कम्पनीसे राज ले लिया और १८५८ के १ नवम्बरको

अन्त ।

घोषणा द्वारा भारतवासियोंको अभयके

साथ ही अपनी अन्य प्रजाके समान अधिकार देनेकी प्रतिज्ञा की । ईस्ट इण्डिया कम्पनीको अन्तिम अधिकार पत्र देते समय ही १८५४ में कह दिया गया था कि पार्लमेण्ट जब चाहेगी, तब तुमसे भारतका राज्य ले लेगी । इस लिये “कोर्ट आव डाइरेक्टर्स” और “बोर्ड आव कण्डोल” उठा दिये गये और इनके बदले “सेक्रेटरी आव स्टेट फार इण्डिया” (भारतसचिव) और उनकी कौन्सिलकी, जो साधारणत इण्डिया कौन्सिल

कहाता है, खाए हुई। ये ही भारतसचिव अपनी कौन्सिलकी सहायतासे सम्राट् के नामपर भारतका शासन करते हैं। मन्त्रिमण्डलके सदस्य होनेके कारण अपने और भारतके अन्यान्य अधिकारियोंके कार्योंके लिये पार्लमेण्टके सामने उत्तरदाता समझे जाते हैं। इस विषयकी सब बातें यथास्थान लिखी जायगी, इसलिये यहाँ इतना ही लिखना घम है।

भारतपर अंगरेजोंका प्रभुत्व होनेपर भी समस्त देश उनके भारतके राजनीतिक शासनाधीन नहीं है। राजनीतिक दृष्टिसे उसके चार भाग होते हैं। अंग-
विभाग ।
रेजी भारत, देशी राज्य, स्वतन्त्र राज्य और अन्य यूरोपियनोंके राज्य। अंगरेजी भारतवर्षके १५ विभाग हैं, उसका क्षेत्रफल १०,६७,६०१ वर्गमील है और १६२१ को मनुष्यगणनाके अनुसार उसमें २४,७१,३८,३६६ मनुष्य बस्ते हैं। समस्त भारतके एकतिहाईसे अधिक भागपर देशी राजाओंका आधिपत्य है। देशके आन्तरिक शासनमें ये बहुत कुछ स्वतन्त्र हैं। सब मिलाकर १७५ बड़े और प्रायः ५०० छोटे राज्य हैं। बड़े राज्योंका साक्षात् सम्बन्ध भारतसरकार और छोटोंका प्रादेशिक सरकारोंसे है। बड़े राज्योंमें सरकारका रेजिडेण्ट या पोलिटिकल एजेण्ट रहता है, पर छोटे राज्योंके एजेण्टका काम किसी जिलेके मैजिस्ट्रेट या डिवीजनके कमिशनरको सौंप दिया जाता है। देशों राज्योंकी जनसंख्या समस्त

भारतकी प्राय चौथाई है। जिन राज्योंसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी को जैसी सन्धि हुई है, उनको वैसी ही स्वतन्त्रता प्राप्त है। साधारणतः ये राज्य अपनी प्रजासे कर लेते, उसके फौजदारी मामले फैसल करने, कुछ राज्य अपने यहां आनेवाले मालपर चुंगी लगाते, सब थोड़ी बहुत सीपी फौज रखते, पर दूसरे राज्यों या विदेशी राज्योंसे न तो किसी तरहकी सन्धि कर सकते और न राजनीतिक सम्बन्ध ही रख सकते हैं। बड़े बड़े राज्योंके जिस नगरमें रेजिडेण्ट या एजेण्ट रहता है, उसमें प्राय अंगरेज सरकारकी छावनी होती और कुछ फौज रहती है। भारतके उत्तर भागमें दो स्वतन्त्र राज्य हैं, एक नेपाल दूसरा भूटान। इन राज्योंकी सीमापर अंगरेज सरकारका रेजिडेण्ट रहता है, पर इसे राजकाजमें हस्तक्षेप करनेका कुछ भी अधिकार नहीं है। पोर्चुगाल और फ्रान्सने प्रारम्भमें भारतपर अधिकार जमानेका प्रयत्न किया था और इन दोनों राष्ट्रोंने कुछ स्थान भी हस्तगत कर लिये थे। उनमें सन्धि द्वारा जो स्थान इन देशोंको मिल गये थे, वे ही अब वैदेशिक राज्य कहाते हैं। इस समय पोर्चुगालके पास गोवा, डायमन आर ड्यू तथा फ्रान्सके पास कारिकल, माही, चन्द्रनगर और पाडिचेरी हैं।

नीचे ब्रिटिश भारतके प्रदेश, उनके जिलोंकी संख्या, वर्ग-मीलोंमें उनका क्षेत्रफल और सन् १९०१की मनुष्य गणनाके अनुसार उनकी जनसंख्या दी जाती है।

प्रदेश	जिले	क्षेत्रफल	जनसंख्या
घट्टाल	२८	७८,४१२	४,६६,५३,१३७
बम्बई (प्रेसिडेन्सी)	३२	१,२३,०६४	१,६३,३८,५८६
बयई	२६	७१,६१८	१,६०,०५,१७०
सिन्ध	६	४७,०६६	३२,७८,४६३
अदन		८०	५४,६२३
मद्रास	२४	१,४१,७२६	४,२३,२२,२७०
बिहार उडीसा	२१	८३,२०५	३,२६,८८,७७८
आगरे-अजमेरे युक्त प्रदेश	४८	१,०७,१६४	४,५५,६०,६०६
आगरा प्रदेश	३६	८३,१६८	३,३४,२०,६३८
अवध प्रदेश	१२	२३,६६६	१,२१,७०,३०८
पंजाब	२६	६७,२०६	२,०६,७८,३६३
बर्मा या ब्रह्मदेश	४१	२३६,७३८	१,३२,०५,५६४
मध्य प्रदेश और बरार	२२	१,००,३४५	१,३६,०८,५१४
आसाम	१२	५०,६५६	७१,६८,८६१
दिल्ली			४,८६,७४१
पश्चिमीतर सीमा प्रदेश	५	१६,४६६	२०,४७,१६६
बलूचिस्तान	६	४५,८०४	४०१,६७६
अजमेर-मेरवाडा	२	२,७११	४,६५,८६६
बुर्ग	१	१,५८०	१,६४,४५६
पेडमन और निकोबार टापू		३,१४३	२६,८३३
कुल जोड़	२६७	१०,६७,६०१	२४,७१,२८,३६६

द्वितीय अध्याय ।

— ❦ —

इंग्लैण्डमें भारत-शासन-व्यवस्था ।

यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि महारानी चिकटोरियाके भारत शासनदण्ड ग्रहण करनेके कोर्ट आन प्रोप्राइटर्स । पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस देशका शासन करती थी । इंग्लैण्डकी महारानी एलिजाबेथने कैसे इसे भारत तथा पूर्वी देशोंमें व्यापार करनेका इजारा दे दिया था, पर कालान्तरमें इसने कैसे अंगरेजी साम्राज्यकी नींव डाली यह इतिहासका विषय है । हमारा प्रयोजन कम्पनीकी भारत शासनपद्धतिसे है । ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत शासनके साथ ही व्यापार भी करती थी और मुख्यतः व्यापार करनेके लिये बंद लगी हुई थी । उसका पूंजी ७२,००० पाँड थी और एक शेयर ५० पाँडका था । कम्पनीके हिस्सेदारोंकी संख्या जेतरण "कोर्ट आन प्रोप्राइटर्स" कहानी थी । ५०० पाँडका हिस्सेदारतक इस कोर्टमें बैठ सकता था । उसे मत देनेका अधिकार नहीं होता था, पर वह वादानुवाद कर सकता था अर्थात् उसका मत मत नहीं समझा जाता था । जो १,००० पाँडके शेयर लेता था,

घर एक घोट दे सकता, इसी प्रकार ३,००० पाँडका शेयर-होल्डर दो, ६,००० का तीन और १०,००० से एक लाख पाँड या अधिकका शेयरहोल्डर चार घोट दे सकता था। सन् १८३२ में कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्समें ३,५७६ सदस्य थे। प्रति वर्ष चार बार मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बरमें कोर्ट बैठता था। मत देनेकी योग्यता रखनेवाले ६ प्रोप्राइटर चेयरमैनको स्पेशल कोर्ट करनेको लिए सकते थे और यदि चेयरमैन कोर्ट न करें तो उक्त ६ प्रोप्राइटरोंको स्पेशल कोर्ट करनेका अधिकार था। इस समय कम्पनीकी पूंजी ६० लाख पाँड थी। कोर्टका काम डाइरेक्टर निर्वाचित करना, बदलना या हट कराना, २०० पाँडसे अधिक वेतन और ६०० पाँडसे अधिक पुरस्कार देने न देनेका निश्चय करना और २५० पाँड या अधिक वेतनवाले पदोंकी सृष्टि करना।

कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्सकी कार्यकारिणी समिति को “कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स” कहने थे। भारतमें कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स। कम्पनीकी नीजरी करने याद जोद वर्ष इंग्लैंडमें रह सकता था, २००० पाँडका शेयरहोल्डर होता था और अपने या अन्य किसीके डाइरेक्टर निर्वाचनके लिये प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपसे मत सत्रह करनेकी चेष्टा न करता था, यह डाइरेक्टर निर्वाचित होता था। ऐसे २४ डाइरेक्टरोंसे कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स सघटित होता था। कमसे कम सप्ताहमें एक बार डाइरेक्टरोंकी मीटिंग

होती थी। यदि किसी विषयपर दोनों ओर मतसंख्ये
समान होती थी, तो ट्रेजरेर चिट्ठी डाल लिया करते थे।
प्रति वर्ष चारों चारोंसे छ डाइरेक्टर अलग-होते थे, पर जिस
शासनकी सुगमता रहे, इससे वे ही पुन निर्वाचित हो जा
करते थे। कोर्ट आफ डाइरेक्टर्सका चेयरमैन ही कोर्ट आफ
प्रोप्राइटर्समें भी अध्यक्षता आसन ग्रहण करता था। का
सञ्चालनकी सुविधाके लिये कोर्ट आफ डाइरेक्टर्सकी १४
कमिटिया थी। प्रत्येकमें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और सीक्रे
टरी डाइरेक्टर ये तीन अवश्य होते थे। इन १४ कमिटियों
एक सीक्रेट कमिटी भी थी, जो सन्धि, विग्रह, विदेशों
लिखापट्टी और लण्डनमें कम्पनीके नाजुक मामलोंके बारेमें
बोर्डके भेजे पत्रोंपर हस्ताक्षर करती थी। इन पत्रोंके लिखनेके
उत्तरदायित्व और अधिकार कोर्टको रहता था। मेम्बरों तथा
पत्र लेखकोंको विषय गुप्त रखनेकी शपथ करनी पड़ती थी।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी देशशासन करनेके लिये नहीं बनी

भारतके राज्यका थी, उसका उद्देश्य व्यापार करना

अधिकारी कौन ? था। पर अनायास जब भारतके भिन्न

भिन्न स्थान उसकी अधीनता स्वीकार

करने लगे, तब उसे भी शासन करनेकी सुझी। इधर कम्पनीके

नौकर मालामाल होकर हिन्दुस्थानसे स्वदेश पहुचने लगे

वहा लोगोंने देखा कि कम्पनीसे राष्ट्रका भी कुछ लाभ होना

चाहिये। इसके लिये आन्दोलन होने लगे। कम्पनीके शासनक

निन्दा भी हुई। १७६५में कम्पनीके यद्दाल, मिहार, और उडीमेकी दीवान्नी लेनेसे लोगोंकी विशेष दृष्टि उसपर रही। अन्तको मन् १७६७में पार्लमेंटको हस्तक्षेप करना पड़ा। इस वर्ष कानून बनाया गया कि कम्पनीके अधिकारमें भारतके जो स्थान आ गये हैं, उनका वह शासन करे और दो वर्षतक राजस्व लेती रहे; साथ ही प्रति वर्ष ४ लाख पाँड सरकारको दिया करे। यद्युत से लोग इसे अन्याय समझेंगे, पर लार्ड चैथमका मत था कि पार्लमेंटको ऐसा करनेका अधिकार है। उनका कहना था कि कोई प्रजा किसी देशका राज्याधिकार अपने लिये नहीं, पर जिस राष्ट्रकी वह प्रजा है उसीके लिये, प्राप्त कर सकती है। अर्थात् कम्पनीने जो राज्य पाया है, वह उसका नहीं, बल्कि इङ्ग्लैंडका है, क्योंकि वह इंग्लैण्डकी प्रजा है और किसी देशका राज्याधिकार नहीं प्राप्त कर सकती। इसी समय राउर्ट क्लाइवने भी कहा था कि इंग्लैण्डके महाराज कम्पनीका राज्य अपने अधीन कर लें और लार्ड चैथमने यह कहकर उसे स्वीकार भी कर लिया था कि यह महाराजका अधिकार और कर्त्तव्य है कि स्वयं भारतका शासन करें। पर १८५८ के पहलेतक कम्पनी ही भारतका शासन करती रही।

सरकारसे इस प्रकार अप्रत्यक्ष उत्साह पाकर कम्पनीके डाइरेक्टरोंने घर फूक तमाशा देपना, 'रेगुलैटिंग ऐक्ट' प्रारम्भ किया। आय व्ययका हिसाब लगाये बिना ही वे अपने हिस्सेदारोंको धूँ ७

लगे, जिससे अन्तमें कम्पनीको रुपयेकी घड़ी तंगी हुई । अ
 उसे ब्रिटिश सरकारसे ऋण मागना पड़ा । कम्पनीके शास
 निन्दासे सरकार उकता गयी थी, इस लिये, उसने रिना
 भाति शासनव्यवस्था किये ऋण देना उचित नहीं सम
 पार्लमेंटमें कम्पनीका मामला पेश हुआ । कम्पनीको ऋण
 मिल गया, पर उसे आज्ञा हुई कि जयतरु आर्थिक
 न सुधरे, तबतक हिस्सेदारोंको वेहिस्ताव मुनाफा न
 इसके साथ ही भारतवर्षमें कम्पनीके कर्मचारियोंके विष
 नियम बने, जिनका यथास्थान उल्लेख किया जायगा
 यह ऐक्ट सन् १७०२ का रेगुलेशन ऐक्ट कहाता है ।
 समयसे कम्पनीकी शासनपद्धतिमें और पार्लमेंटका हस्त
 बढ़ता ही गया और जैसा आगे चलकर आप देखेंगे
 कम्पनीको कोई वास्तविक अधिकार न रहा । सन् १७८५
 में ऐक्ट बना जिसके अनुसार कम्पनीके कोर्ट आ

राज्यका कोई एक मुख्य मन्त्री जो आशा है, फोर्ट उसे माननेके लिये बाध्य किया गया ।

सन् १७८४ में विलियम पिटने पार्लमेंटमें एक इंडिया बिल पेश किया । यह पास हो गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल । कम्पनीको नियंत्रित रखनेके लिये "बोर्ड ऑफ कंट्रोल" नामकी संस्थाकी सृष्टि हुई । इस संस्थाका दूसरा नाम "कमिशनर्स फार दि ऐफेयर्स ऑफ इण्डिया" * है । इसने भारतशासनके विषयमें कम्पनीके हाथ पैर बंधाए जकट दिये । प्रिवी कौन्सिलके अधिकने अधिक छ सदस्योंका यह बोर्ड बना । इनमें राज्यके एक मुख्य मन्त्री और । अर्थसचिव या राजस्वसचिवका रहना आवश्यक कर दिया गया । इन्हीं ऐक्टने 'सीक्रेटकमिटी' या गुप्त समिति स्थापनकी व्यवस्था की थी । इस कमिटीमें फोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्सके अधिकसे अधिक तीन मेम्बर रहते थे । अन्य डाइरेक्टर्सको बिना उताये आज्ञापत्र भान्त भेजना इस कमिटीका काम था । १७६३ में जो ऐक्ट बना, उससे इस बोर्डकी रचनामें भी परिवर्तन हुआ । राज्यके दो मुख्य मन्त्री, अर्थ-सचिव और दो अन्य सज्जनोंका बोर्डमें रहना आवश्यक कर दिया गया । साथ ही प्रिवी कौन्सिलरोंकी संख्या निर्दिष्ट नहीं रही । १८३३ के चार्टर ऐक्टमें महारानीको अधिकार

* Commissioners for the Affairs of India † Chancellor of the Exchequer

दिया गया कि, वे चाहे जितने सज्जनोंको कमिशनर अथवा बोर्ड के मेम्बर बना दें, यह आवश्यक नहीं है कि वे प्रिन्सिपल के मेम्बर ही हों। परन्तु यह भी नियम हुआ कि कौन्सिल के लार्ड प्रेसिडेंट, लार्ड प्रिवी सील, फर्स्ट लार्ड आव दि ट्रेजरी (प्रधान मन्त्री), राज्य के मुख्य मन्त्री और अर्थसचिव अपने पदों के कारण इस बोर्ड के मेम्बर रहेंगे। कुछ समय उपरान्त बोर्ड में मेम्बर न रहे, केवल अध्यक्ष ही उसके नामपर सब काम करते थे। १७६३ तक बोर्ड के व्यय के लिये कोई व्यवस्था न थी, पर इसके बाद से भारत के राजस्व से बोर्ड के मेम्बरों और कर्मचारियों को अच्छी तलबें मिलने लगीं।

१८३३ के चार्टर ऐक्ट के धन जाने से भारतशासन के

सम्बन्ध में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सब

बोर्ड के अधिकार अधिकार छिन गये। उसका विलायती

खजाना बोर्ड आव कण्ट्रोल को दे

दिया गया तथा नियम बना कि "सब आह्वाप, पत्र या सार्वजनिक विषय के कागज पत्र डाइरेक्टर लोग तत्तक भारत न भेजें, जबतक बोर्ड उन्हें पसन्द न कर ले।" केवल कर्मचारियों को नियुक्त करने और हटाने का कार्य कम्पनी के डाइरेक्टरों के अधीन रहा। इसमें बोर्ड को हस्तक्षेप करने का

स्वीकृति उन्हें बोर्डसे लेनी पड़ती थी । इस प्रकार कम्पनीके डाइरेक्टरोंका महत्त्व बहुत घट गया और कोर्ट आव डाइरेक्टर्स या सञ्चालकसमिति केवल प्रस्तावकारिणी सस्था रह गयी, उसके प्रस्तावोंको स्वीकार अथवा अस्वीकार करना बोर्डके अधीन था ।

बोर्ड कम्पनीके कार्योंकी कैसे देखभाल करता था इसका
बोर्डकी वर्णन १८५३ में पार्लमेण्टकी कमिटीके
निरीक्षणपद्धति । सामने उसके सीनियर क्लर्क मि० चाटर-फील्डने इस प्रकार किया था ;—

“बोर्डके आफिसका काम छ विभागोंमें बंटा हुआ था (१) रेवन्यू (राजस्व) (२) फाइनेन्स ऐण्ड ऐकाउण्टस् (अर्थ तथा हिसाब किताब), (३) मिलिटरी (फौजी), (४) मैरीन, एल्किसियेस्टिकल, पब्लिक ऐण्ड मिसेलेनियस (जल सेना, पादरियों, सर्वसाधारण तथा विविध सम्बन्धी), (५) पोलिटिकल (राजनीतिक) और (६) जुडिशल ऐण्ड लेजिस्लेटिव (न्याय तथा व्यवस्था सम्बन्धी) इनके सिवा एक सीक्रेट डिपार्टमेण्ट या गुप्त विभाग था, जो बोर्डके अध्यक्षके अधीन था । इसके खरीते वे आप तैयार करते थे । बाकी सत्र विभागोंके खरीते इण्डिया हाउसमें तैयार होते थे । खरीते भेजनेका नियम ऐसा था कि डाइरेक्टरोंकी समितिमें उपस्थित करनेके पहले कम्पनीके अध्यक्ष प्रस्तावित खरीतेके विषयमें अपने विचार बोर्डके अध्यक्षको लिख भेजते थे ।

यह "प्रिवियस कम्प्यूनिकेशन" कहा जाता था। इसके साथ इसके सम्बन्धके सब कागजपत्र भी भेजे जाते थे। इस प्रकार इन कागजपत्रोंका बड़ा भारी पोथा हो जाता था। एक पोथीमें १६, २६३ पृष्ठ तक रह चुके हैं। प्रिवियस कम्प्यूनिकेशन या पूर्व सूचना और उसपर की हुई टीकाटिप्पणों पढ़ते और फिर निर्णय करते हैं। कम्पनीके अध्यक्ष इस निर्णयपर फिर विचार करते हैं और कभी इसको पसन्द और कभी नापसन्द करते हैं। पर इसके अनुकूल ही उसकी नकल की जाती है और उसपर डाइरेक्टर्सकी मीटिंगमें विचार होता है। डाइरेक्टर उसमें कुछ परिवर्तन आदि करते हैं और फिर पहलेकी तरह कागजपत्रोंकी मिसिलके साथ वह बोर्डमें भेजा जाता है। इस समय यह ड्राफ्ट या मसविदा कहा जाता है। जिस विभागसे इनका सम्बन्ध हुआ उसमें यह मसविदा बोर्डके अध्यक्षकी निर्णोत पूर्व सूचनासे मिलाया जाता है। यदि दोनोंमें कुछ अन्तर न हुआ और सीनियर क्लर्कने ऐसी ही रिपोर्ट दे दी, तो यह स्वीकृत हो गया। यदि अन्तर हुआ, तो अन्तर बता दिया गया। आवश्यकता जान पड़ी, तो फिर सारा पोथा पढ़ा गया और उसपर टीकाटिप्पणों हुई। अध्यक्षको फिर कागजपत्र पढ़ने पड़े। कुछ विचारके उपरान्त वे निश्चय करते हैं, कि अमुक अरा बदला जाय या रहने दिया जाय। यदि बदलनेकी ठहरी, तो उसके कारणोंका उल्लेख कर एक पत्र डाइरेक्टर्सको लिख दिया गया। यदि उन्हें कारण नहीं लिख भेजे जाते, तो

वे उस कार्यका विरोध करके पत्र लिखते हैं और तब इस पत्र पर विचार करके उत्तर देना ही पड़ता है। अन्तको बोर्डको पत्रकी प्रतिलिपि भेज दी जाती है। बोर्डके अध्यक्ष सरकारके प्रत्येक विभागसे प्राइवेट पत्रव्यवहार रखते हैं और भारतके गवर्नर-जेनरल तथा अन्य उच्च अधिकारियोंसे बराबर लिखापढी करते रहते हैं। १८११से मन्त्रिमण्डलके एक सदस्य ही बोर्डके अध्यक्षके पदपर हैं।

कम्पनीके कारोबार और शासनव्यवस्थाकी जाच प्रति २० वर्षपर पार्लमेण्टकी कमिटिया करती थीं और इसी समय उनका चार्टर या फर्मान बदला जाता था। इसके

लिये एक ऐक्ट बनता था और शासनप्रबन्ध तथा व्यापार व्यवस्थामें जाचके बाद जो विषय संशोधन योग्य दिखते थे, उनके संशोधन वा परिवर्तनके नियम इस ऐक्टमें रख दिये जाते थे। १७७३से १८५३ तक बराबर पार्लमेण्टने कम्पनीके कारोबार और शासनव्यवस्थाकी जाच की। १७७३में रेगुलेटिंग ऐक्ट बना, १७८३में बोर्ड आफ फट्रोलके सघटनमें परिवर्तन हुआ, १८१३में व्यापार करनेका कम्पनीका इजारा छीन लिया गया और १८३३ में उसका विलायती पजाना सरकारने ले लिया और १८५३में जो फर्मान कम्पनीको दिया गया, उसमें यह साफ साफ लिख दिया गया कि राज्य महारानीका है, पर जबतक पार्लमेंट न

यह "प्रिवियस कम्प्यूनिकेशन" कहा जाता था । इसके साथ इसके सम्बन्धके सब कागजपत्र भी भेजे जाते थे । इस प्रकार इन कागजपत्रोंका बड़ा भारी पोथा हो जाता था । एक पोथीमें १६,२६३ पृष्ठ तक रह चुके हैं । प्रिवियस कम्प्यूनिकेशन या पूर्व सूचना और उसपर की हुई टीकाटिप्पणों पढ़ते और फिर निर्णय करते हैं । कम्पनीके अध्यक्ष इस निर्णयपर फिर विचार करते हैं और कभी इसको पसन्द और कभी नापसन्द करते हैं । पर इसके अनुकूल ही उसकी नकल की जाती है और उसपर डाइरेक्टरोंकी मीटिंगमें विचार होता है । डाइरेक्टर उसमें कुछ परिवर्तन आदि करते हैं और फिर पहलेकी तरह कागजपत्रोंकी मिसिलके साथ वह बोर्डमें भेजा जाता है । इस समय यह ड्रफ्ट या मसविदा कहा जाता है । जिम्न विभागसे इसका सम्बन्ध हुआ उसमें यह मसविदा बोर्डके अध्यक्षकी निर्णोक्त पूर्व सूचनासे मिलाया जाता है । यदि दोनोंमें कुछ अन्तर न हुआ और सीनियर क्लर्कने ऐसी ही रिपोर्ट दे दी, तो यह स्वीकृत हो गया । यदि अन्तर हुआ, तो अन्तर बता दिया गया । आवश्यकता जान पड़ी, तो फिर सारा पोथा पढ़ा गया और उसपर टीकाटिप्पणी हुई । अध्यक्षको फिर कागजपत्र पढ़ने पड़े । कुछ विचारके उपरान्त वे निश्चय करते हैं, कि अमुक अश खूला जाय या रहने दिया जाय । यदि बदलनेकी ठहरी, तो उसके कारणोंका उल्लेख कर एक पत्र डाइरेक्टरोंको लिख दिया गया । यदि उन्हें कारण नहीं लिख भेजे जाते, तो

ये उम कायेंका विरोध करके पत्र लिखते हैं और तब इस पत्र पर विचार करके उत्तर देना ही पड़ता है। अन्तको बोर्डको पत्रकी प्रतिलिपि भेज दी जाती है। बोर्डके अध्यक्ष सरकारके प्रत्येक विभागसे प्राइवेट पत्रव्यवहार रखते हैं और भारतके गवर्नर-जेनरल तथा अन्य उच्च अधिकारियोंसे बराबर लिखापेंदी करते रहते हैं। १८११से मन्त्रिमण्डलके एक सदस्य ही बोर्डके अध्यक्षके पदपर हैं।”

कम्पनीके कारोबार और शासनव्यवस्थाकी जाच प्रति २०

प्रति २० वर्षपर वर्षपर पार्लमेण्टकी कमिटिया करती थीं और इसी समय उसका चार्टर पूरा जाच । या फर्मान बदला जाता था। इसके

लिये एक ऐक्ट बनता था और शासनप्रबन्ध तथा व्यापार व्यवस्थामें जाचके बाद जो विषय संशोधन योग्य दिखते थे, उनके संशोधन वा परिवर्तनके नियम इस ऐक्टमें रख दिये जाते थे। १७७३से १८५३ तक बराबर पार्लमेण्टने कम्पनीके कारोबार और शासनव्यवस्थाकी जाच की। १७७३में रेगुलेटिंग ऐक्ट बना, १७६३में बोर्ड आय फद्रोलके मघटनमें परिवर्तन हुआ, १८१३में व्यापार करनेका कम्पनीका इजारा छीन लिया गया और १८३३ में उसका विलायती खजाना सरकारने ले लिया और १८५३में जो फर्मान कम्पनीको दिया गया, उसमें यह साफ साफ लिख दिया गया कि राज्य महारानीका है, पर जतक पार्लमेंट न

यह "प्रिवियस कम्प्यूनिकेशन" कहा जाता था । इसके साथ इसके सम्बन्धके सभ कागजपत्र भी भेजे जाते थे । इस प्रकार इन कागजपत्रोंका बड़ा भारी पोथा हो जाता था । एक पोथीमें १६, २६३ पृष्ठ तक रह चुके हैं । प्रिवियस कम्प्यूनिकेशन या पूर्व सूचना और उसपर की हुई टीकाटिप्पणों पढ़ते और फिर निर्णय करते हैं । कम्पनीके अध्यक्ष इस निर्णयपर फिर विचार करते हैं और कभी इसको पसन्द और कभी नापसन्द करते हैं । पर इसके अनुकूल ही उसकी नकल की जाती है और उसपर डाइरेक्टरोंकी मीटिंगमें विचार होता है । डाइरेक्टर उसमें कुछ परिवर्तन आदि करते हैं और फिर पहलेकी तरह कागजपत्रोंकी मिसिलके साथ वह बोर्डमें भेजा जाता है । इस समय यह ड्राफ्ट या मसविदा कहा जाता है । जिस विभागसे इसका सम्बन्ध हुआ उसमें यह मसविदा बोर्डके अध्यक्षकी निर्णोक्त पूर्व सूचनासे मिलाया जाता है । यदि दोनोंमें कुछ अन्तर न हुआ और सीनियर क्लर्कने ऐसी ही रिपोर्ट दे दी, तो यह स्वीकृत हो गया । यदि अन्तर हुआ, तो अन्तर बता दिया गया । आवश्यकता जान पड़ी, तो फिर सारा पोथा पढ़ा गया और उसपर टीकाटिप्पणी हुई । अध्यक्षको फिर कागजपत्र पढ़ने पड़े । कुछ विचारके उपरान्त वे निश्चय करते हैं, कि अमुक अश चढ़ला जाय या रहने दिया जाय । यदि बदलनेकी ठहरी, तो उसके कारणोंका उल्लेख कर एक पत्र डाइरेक्टरोंको लिख दिया गया । यदि उन्हें कारण नहीं लिख भेजे जाते, तो

चे उस फायेंका विरोध करके पत्र लिखते हैं और तब इस पत्र पर विचार करके उत्तर देना ही पड़ता है। अन्तको बोर्डको पत्रकी प्रतिलिपि भेज दी जाती है। बोर्डके अध्यक्ष सरकारके प्रत्येक विभागसे प्राइवेट पत्रव्यवहार रखते हैं और भारतके गवर्नरजेनरल तथा अन्य उच्च अधिकारियोंसे बराबर लिखापट्टी करने रहते हैं। १८११से मन्निमण्डलके एक सदस्य ही बोर्डके अध्यक्षके पदपर हैं।”

कम्पनीके कारोबार और शासनव्यवस्थाकी जाच प्रति २० प्रति २० वर्षपर वर्षपर पार्लमेण्टकी कमिटिया करनी थीं और इसी समय उसका चार्टर पूरा जाच । या फर्मान बदला जाता था। इसके

लिये एक पेक्ट बना था और शासनप्रबन्ध तथा व्यापार व्यवस्थामें जाचके बाद जो विषय संशोधन योग्य दिखते थे, उनके संशोधन वा परिवर्तनके नियम इस पेक्टमें रख दिये जाते थे। १७७३से १८५३ तक बरानर पार्लमेण्टने कम्पनीके कारोबार और शासनव्यवस्थाकी जाच की। १७७३में रेगुलेटिंग पेक्ट बना, १७६३में बोर्ड आय कंट्रोलके सघटनमें परिवर्तन हुआ, १८१३में व्यापार करनेका कम्पनीका इजाजा छीन लिया गया और १८३३ में उसका विलायती राजाना सरकारने ले लिया और १८५३में जो फर्मान कम्पनीको दिया गया, उसमें यह साफ साफ लिख दिया गया कि राज्य महारानीका है, पर जबतक पार्लमेंट न

चाहेगी कि सरकार उसका शासन करे तबतक कम्पनीके हाथमें रहेगा । यही मानो कम्पनीके लिये यमराजका वारंट था । सन् १८५८ की पहली नवम्बरको पार्लमेंटकी दोनों सभाओंकी इच्छासे महारानीने अपना प्रसिद्ध घोषणापत्र प्रचारित कर भारतका शासनवण्ड स्वयं ग्रहण किया ।

श्रीमान् सम्राट्के नामपर भारतका शासन होता है ।

भारतका शासक

कौन है ।

इङ्ग्लैण्डमें भारतके शासनसम्बन्धका कार्य भारतसचिव और उनकी कौन्सिल द्वारा होता है । कम्पनीके समयमें

कोर्ट आब डाइरेक्टर्स और बोर्ड आब कंट्रोलको जो अधिकार प्राप्त थे, वे सब १८५८के गवर्नमेंट आब इण्डिया ऐक्टके अनुसार, भारतसचिव और उनकी कौन्सिलको मिल गये । भारतसचिव प्रिवी कौन्सिलर होते हैं और इस प्रकार नियमानुसार वे श्रीमान् सम्राट्के परामर्शदाता हैं । इनके परामर्शके अनुसार ही सब कार्य होते हैं । जो पत्र भारत आते हैं, उनपर भारतसचिवके ही हस्ताक्षर होते हैं और भारतसे जो लण्डन जाते हैं, वे भारतसचिवके नाम जाते हैं । भारतसचिव भारतके प्रत्येक कर्मचारी यहातक कि गवर्नर जनरलको भी आज्ञा दे सकते हैं ।

भारतसचिवके पदकी सृष्टि होनेके पहले महारानी विक्टो

भारतसचिव और रियाके चार ही मुख्य मन्त्री थे । इनका कौन्सिल । सम्बन्ध स्वराष्ट्र, परराष्ट्र, उपनिवेश

मार युद्धविभागसे था । पर जब महारानीने भारत-

शासन भार लिया, तब पाचवें मन्त्री भारतसचिवकी आवश्यकता हुई। इनका तथा इनकी कौन्सिलके सदस्यों और दफ्तरके कर्मचारियोंका वेतन भारतसे देनेका नियम भी बन गया। अन्य मन्त्रियोंसे इनमें अन्तर भी था। आयरिश वा स्कॉटिश अथवा औपनिवेशिक मन्त्रियोंको अपनी नीति यतानी पड़ती थी, पर ब्रिटिश कोषसे भारतसचिवको वेतन न मिलनेके कारण ये अपनी नीति यतानेको बाध्य नहीं किये जा सकते थे। इससे सिवा अन्य मन्त्रियोंपर मामला नहीं चल सकता। मंत्रीके कार्यसे जिसे कष्ट या दुःख पहुँचे, वह महाराजकी सेवामें प्रार्थनापत्र भेज सकता है। पर भारत सचिवपर नालिश हो सकती है और ये भी लोगोंपर नालिश कर सकते हैं। भारतसचिवकी आज्ञासे ही कौन्सिल काम करती है। ये अपनी कौन्सिलके अध्यक्ष हैं और इन्हें मत देनेका अधिकार है। ये किसी सदस्यको कौन्सिलका उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। कौन्सिलमें मेम्बर नियुक्त करना भी इनके ही अधीन है। सन्धि विग्रह करने अथवा दूसरे राज्यों तथा देशी रजवाड़ोंके विषयमें भारत सरकारको जो पत्रादि भेजे जाते हैं, वे अपनी कौन्सिलके मेम्बरोंको दिखाये बिना भारतसचिव उसी प्रकार भेज देते हैं, जिस प्रकार कोर्ट आफ डाइरेक्टर्सकी सीक्रेट कमिटी भेजती थी। इनका अभिप्राय भी मेम्बरोंको कामोक्तान नहीं मालूम होने पाता और इनपर "सीक्रेट" शब्द लिख दिया जाता है।

राज्योंसे सम्बन्ध रखे हुए सज्जन हैं। १९०७में एक हिन्दू और एक मुसलमान सज्जन भी कौन्सिलके मेम्बर बनाये गये थे। १९१६ में फिर गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्ट पास हुआ और आजकल इसीके अनुसार काम हो रहा है।

अन्तिम गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्टके अनुसार भारत सचिवके हाथमें कद्राक्ट देने और ऐसे हाई कमिशनर। ही अन्य काय नहीं रहे, जो वे भारत सरकारकी ओरसे लण्डनमें करते थे और इनके लिये हाई कमिशनरकी सृष्टि हुई है। १ अक्तूबर १९०० को सर विलियम मेयर हाई कमिशनर नियुक्त हुए थे और इनके अग्रेज इण्डिया आफिसका स्टोर्स डिपार्टमेंट और इसीके सम्बन्धकी एकाउण्टस् शाखा और भारतीय विद्यार्थियोंकी शाखा और लण्डनमें इण्डियन ट्रेड कमिशनरके कार्यके निरीक्षण का काम किया गया था। ज्यों ज्यों भारत सरकार और भारतसचिवके सम्बन्धमें परिवर्तन होते जायगे, त्यो त्यो हाई कमिशनरके अधिकार बढ़ते बढ़ते स्वराज्यप्राप्त उपनिवेशोंके हाई कमिशनरके समान हो जायगे। अब बम्बईके प्रसिद्ध पारसी श्रीयुक्त दादीरा मेरवानजी दलाल हाई कमिशनर नियुक्त हुए हैं। इस समय इनके आफिसके जेनरल डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट इण्डियन स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट एकाउण्टस् डिपार्टमेंट ट्रप, सर्विस और इण्डियन ट्रेड कमिशनर हैं। हाई कमिशनरका वार्षिक वेतन ३,००० पाँड है। इनके अधीन

कोई ४५ बड़े कर्मचारी हैं, जिनमें इनके सेक्रेटरी, स्टोर डिपार्टमेंटके डाइरेक्टर जनरल, स्टोर डिप्टमेंटके सुपरिण्टेण्डेंट, शिपिंग डाइरेक्टर, ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरलके एजेंट और इण्डियन ट्रेड कमिशनर मुख्य हैं ।

कौन्सिलके मेम्बरोंको स्वतन्त्र कोई अधिकार नहीं है ।

कौंसिलोंके अधिवेशन भारतसचिवके आग्रानुसार वे लंडनमें

और मेम्बरोंका भारतसम्वन्धीय सब कार्य करते हैं

अधिकार । और जिन विषयोंपर भारतसचिव

उनकी सम्मति पूछते हैं, उनपर सम्मति देते हैं । पहले

सप्ताहमें साधारणतः एक बार भारतसचिवकी आशासे

कौन्सिलका अधिवेशन होता था । अब महीनेमें एक बार होता

है । यदि भारतसचिव अधिवेशनमें उपस्थित होते हैं तो

अध्यक्षका आसन ग्रहण करते हैं । उनकी अनुपस्थितिमें

उपाध्याक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होनेपर उस समयके लिये

कोई मेम्बर अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जाता है । पांच

मेम्बरोंकी उपस्थितिमें कार्य आरम्भ होता है । जिस अधि-

वेशनमें भारतसचिव हों और किसी मेम्बरके निर्वाचनका प्रश्न

न उपस्थित हो और विचारणीय विषयके लिये कौन्सिलके

ग्रहणमतका प्रयोजन न हो, तो भारतसचिवके निर्णयके अनुसार

कार्य होता है । निर्णीत विषयपर मतभेद होनेपर भारतसचिव

कार्यविचरणीमें अपनी सम्मतिके कारण लिखा देते हैं और

यदि कोई मेम्बर भी अपनी सम्मतिके कारण लिखना चाहे तो

यह भी लिखा सकता है । भारतसचिवकी अनुपस्थितिमें कौन्सिल जो निश्चय करती है, उसे कार्यमें परिणत करनेके पहले भारतसचिवकी लिखित अनुमति प्राप्त कर लेनी पड़ती है । कौन्सिलके मेम्बरोंको पार्लमेण्टमें बैठनेका अधिकार नहीं है ।

कार्यकी सुगमताके लिये भारतसचिव अपनी कौन्सिलको कौन्सिलकी कमिटियाँ चार चार पांच पांच मेम्बरोंकी कमिटियोंमें बांट देते हैं । प्रत्येक मेम्बर और उनका कार्य । दो कमिटियोंका कार्य करता है । इन कमिटियोंके अधीन कुछ विभाग होते हैं । प्रत्येक विभागका एक स्थायी सेक्रेटरी होता है । जब कोई पत्र भारत भेजना होता है, तब जिस विभागसे उसका सम्बन्ध होता है, उसका सेक्रेटरी भारतसचिवकी आज्ञा लेता है और परीतिका मसविदा तैयार करता है और कमिटीमें उपस्थित करता है । मेम्बर इसमें कुछ परिवर्तन करा वा आपत्तियाँ कर सकते हैं । परिवर्तनों और आपत्तियोंके अनुसार संशोधित हो यह भारतसचिवको भेजा जाता है । यदि वे स्वीकार कर लेते हैं तो और मेम्बरोंको यह देखनेको मिलता है । अनन्तर कौन्सिलमें विचार करके पास कर दिया जाता है । आजकल छ कमिटियाँ हैं, यथा फाइनेन्स (अर्थ), पोलिटिकल ऐण्ड सीक्रेट (राजनीतिक और गुप्त) मिलिटरी (फौजी), रेवेन्यू ऐण्ड स्टेटिस्टिक्स (राजस्व और दशा सम्बन्धी) पब्लिक ऐण्ड

जुडीशाल (सर्वमाधारण और न्याय सम्बन्धी), और पब्लिक वर्क्स (रेल, नहर, डाक, तार, सरकारी इमारतें आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली) ।

ईस्ट इण्डिया कम्पनीका दफ्तर इण्डिया हाउस कहाता था और भारतसचिवका दफ्तर इण्डिया इण्डिया आफिस । आफिस कहाता है । यह लंडनके ग्राइन्हालमें है । पहले इण्डिया आफिस-

का कुल पर्व पहले हिन्दुस्थानके राजानेसे दिया जाता था । यह वार्षिक व्यय ३,५७,००० पौण्ड या ५३,५५,०००) है । इसमें भारतसचिवसे लेकर इण्डिया आफिसमें भाड़ देनेवाली मेह-तरानी तकका घेतन सम्मिलित था , १९१६ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्टके अनुसार अब टाई कमिशनर और उनके आफिस का पर्व छोड़ बाका सब पर्व ब्रिटिश राजानेसे दिया जाना चाहिये । परन्तु वहासे अभी १३६,५०० पौण्ड ही मिलने हैं । इसमें ४००,०० पौण्ड तो बेलजी कमिशनके प्रस्तावानुसार ब्रिटिश सरकार देनी आती है और बाकीमें भारतसचिव और उनके सहकारी तथा अन्य कर्मचारियोंका घेतन है । इस लिये हिन्दुस्थानको अब भी २,२०,५०० पौण्ड देने पडते हैं । भारतसचिवके दो सहायक होते हैं, एक परमानेंट अडर सेक्रेटरी और दूसरा पार्लमेंटरी अडर सेक्रेटरी कहाता है । परमानेंट अडर सेक्रेटरी स्थायी कर्मचारी होता है, पर पार्लमेंटरी अडर सेक्रेटरी मन्त्रिमण्डलके परिवर्तन

वा अन्य कारणोंसे बदला करता है। इनसे इण्डिया आफिसके सब मुख्य करके परमानेंट अंडर सेक्रेटरी या स्थायी सहकारी भागनसचिवके हाथमें रहते हैं। इण्डिया आफिसके मुख्य अधिकारियोंकी सूची इस प्रकार है —

अधिकारी ।	वार्षिक वेतन ।
भारतसचिव	५,००० पौण्ड
उनके प्राइवेट सेक्रेटरी	३०० „
„ पेसिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी	१५० „
„ पोलिटिकल एडीकाग	८०० „
स्थायी सहकारी भारतसचिव	३,००० „
उनके प्राइवेट सेक्रेटरी	१५० „
डिप्टी सह० भारतसचिव	२,२०० „
पार्लमेंटरी सह० भारतसचिव	१,५०० „
उनके प्राइवेट सेक्रेटरी	१५० „
पेसिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी	१५०० „
कंट्रोलर आफ फाइनेन्स	२,४०० „
कौन्सिलके १० सदस्य (प्रत्येक)	१,००० „

१८५८ के गवर्नमेंट भाव इण्डिया ऐक्टके अनुसार महारानी

इंडिया आफिसका विक्टोरियाकी प्रिवी कौन्सिलके एक
कार्यविभाग । आर्डरसे इण्डिया आफिसके स्थायी
कर्मचारियोंकी संख्या आदि निर्दिष्ट

हुई थी। इण्डिया आफिस कई विभागोंमें विभक्त है और

प्रत्येक विभाग एक स्थायी सेक्रेटरीके अधीन है। कौन्सिलर कमिष्ट्रियोंके नामोंके अनुसार विभागोंके नाम भी रखे गये हैं। सेक्रेटरीका वार्षिक वेतन १,२०० पाँड और सहकारीका १,००० पाँड होता है, पर सेना विभागके सहकारीका १,१०० पाँड है। इनके सिवा कई सीनियर जूनियर और स्टाफ क्लर्क हैं, जो ३५० से ८०० पाँडतक वेतन पाते हैं। ये विभाग कारेस्पाडेन्स डिपार्टमेंट कहते हैं। इण्डो-यूरोपियन टेलिग्राफ पब्लिक वर्कस् डिपार्टमेंटके डाइरेक्टर इन चीफ भी कारेस्पाडेन्स डिपार्टमेंटमें काम करते हैं और इन्हें १,१०० पाँड वार्षिक वेतन मिलता है। अन्य विभागोंके नाम एकाउण्टेण्ट जेनरल्स डिपार्टमेंट और रेजिस्ट्री ऑफ रेकार्डस् डिपार्टमेंट हैं। एकाउण्टेण्ट जेनरल ही अपने विभागके मुखिया हैं। इनका वेतन भी १,२०० पाँड वार्षिक है। सीनियर जूनियर और स्टाफ क्लर्कों के सिवा इनके एक डिप्टी और एक ऐसिस्टेंट भी हैं, जो क्रमशः १,००० और ६५० पाँड पाते हैं। स्टोर विभागके मुखिया डाइरेक्टर जेनरल कहते हैं। इनका, इनके सहकारी तथा क्लर्कों के वेतन कारेस्पाडेन्स विभागके सेक्रेटरियों, उनके सहकारियों तथा क्लर्कों के समान ही हैं। इस विभागकी एक शाखा स्टोर डिपो सुपेरिण्डेण्टके अधीन है, जो ८०० से १,००० पाँड वेतन पाते हैं। डिपो डिप्टी और ऐसिस्टेंट सुपेरिण्डेण्टोंके अतिरिक्त सुपरवाइजर मशिनरी और साइण्टिफिक सप्लाइजके (यन्त्रादि तथा

निक सामग्रियोंके) इन्स्पेक्टर, मेडिकल स्टोर्स (डाक्टरी सामान) और सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट्स एगजामिनर (चिकित्सा सम्बन्धी अस्त्रोंके परीक्षक) हैं। स्टोर्स डिपार्टमेंट, जैसा ऊपर बताया चुके है, हाई कमिशनरके अधीन है। रेजिस्ट्री और रेकार्ड्स विभाग रेकार्ड्सके रेजिस्ट्रारके अधीन है। इनका वेतन १,००० पाँड है। इनके एक पेसिस्टेंट और स्टाफ क्लर्क हैं। उल्लिखित अधिकारियोंके सिवा भिन्न भिन्न विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले और भी कितने ही कर्मचारी नियुक्त हैं, जिनके पदोंकी सूची यह है,—गवर्नमेंट डाइरेक्टर आव रेलवेज़, लाइब्रेरियन (पुस्तकाध्यक्ष), इन्स्पेक्टर आव मिलिटरी इक्विपमेंट ऐण्ड क्लोथिंग (फौजी साज सामान और वस्त्रोंके इन्स्पेक्टर), अफसरोंकी डाक्टरीके लिये मेडिकल बोर्डके प्रेसिडेण्ट और मेम्बर, भारतसचिवके सलिसिटर और कानूनी सलाह देनेवाले, सर्वेयर ऐण्ड क्लर्क आव चर्क्स (अमीन और इमारतोंके क्लर्क), आर्डनेन्स कन्सल्टिंग अफसर (गोले वारुदके मामलोंमें सलाह देनेवाले अफसर), कन्सल्टिंग एड्जिनियर और आडिटर। इनको ४०० से १,२०० पाँडनक वार्षिक वेतन मिलता है। उक्त अफसरोंमें कईके पेसिस्टेंट या सहकारी भी हैं।

भारतके सुशासनके लिये भारतसचिव पार्लमेंटके सामने पार्लमेंट और उत्तरदाता हैं। पार्लमेंटकी कामन्स

समामें भारतके किसी कर्मचारीके भारत सरकार । कुशासन दुर्न्यवहार अथवा कर्त्तव्य

परामुखताके विषयमें जो प्रश्न किये जाते हैं, भारतसचिव वा

उनके पार्लमेंटरी सहकारी उनका उत्तर देते हैं। प्रति वर्ष १ मईके बाद चौदह दिनके भीतर भारतसचिवको भारतके आय-व्ययका लेखा पार्लमेंटमें उपस्थित करना पड़ता है। इसके साथ ही वे ब्रिटिश भारतकी मानसिक और आर्थिक उन्नतिका वर्णन करते हैं। १९१६ से भारत सरकार स्वयं एक रिपोर्ट तैयार कराती है और यही पार्लमेंटमें पेश की जाती है। कामन्स सभाकी कमिटी इसपर विचार करता है और भारतसचिव या उनके प्रतिनिधि मेम्बरोंको इसे समझानेके लिये व्याख्यान देते हैं। इस समय पार्लमेंटके जो सदस्य चाहते हैं, भारतकी राज-नीतिक या साम्प्रतिक अवस्थाकी समालोचना करते और शासनसम्वन्धीय अन्य बातोंपर टीका टिप्पणी करते हैं। इसपर जो वादानुवाद हो जाता है, वही "बजेटकी बहस" कहाता है। वर्षभरमें इसी दिन भारतशासनकी समालोचना होती है। भारतसचिव और उनकी कौन्सिलके नामसे बैंक आव इङ्ग्लैण्डमें भारतका खाता है। भारतसचिव और उनकी फान्सिलका हिसाब फिताय जाचनेके लिये स्वतन्त्र आडिटर नियुक्त हैं। यद्यपि इनका तथा इनके अधीन कर्मचारियोंका वेतन भारतके खजानेसे दिया जाता है, तथापि इनकी नियुक्ति रायल साइन मैन्युएलके अनुसार भीमान् सम्राट्के चारट् अर्थात् हस्ताक्षरयुक्त आज्ञा पत्रसे होती है और इसपर मर्यसचिवके भी हस्ताक्षर होते हैं।

तृतीय अध्याय ।

— ❧ —

भारत-सरकार ।

भारतसरकारके अधिकार और उत्तरदायित्व समझनेके पहले

भारतसरकारकी यह जान लेना आवश्यक है कि भारत सरकार किसे कहते हैं। बहुतसे लोग परिभाषा । जानते हैं कि जो अङ्गरेजीमें “गवर्न

मेण्ट आव इण्डिया” है, वही हिन्दीमें “भारतसरकार” हैं। परन्तु इतना जान लेनेपर भी वे भारतसरकार बड़े लाट-या गवर्नर जेनरलका पर्यायवाची पद ही समझते हैं। यह सर्वथा भ्रम है, क्योंकि यद्यपि भारतसरकारके नामपर उन्हें बहुतसे कार्य करनेका अधिकार है, तथापि बड़े लाट भारतसरकारके अङ्गविशेष और सभसे महत्वपूर्ण अङ्ग मात्र हैं, भारतसरकार नहीं। मनुष्यका मिर ही जिस प्रकार उसका शरीर नहीं है, उसी प्रकार बड़े लाट ही भारतसरकार नहीं हैं। भारत सरकारका अर्थ है “गवर्नर जेनरल इन-कौन्सिल” अर्थात् गवर्नर जेनरल और उनकी कौन्सिल जब दोनों मिल जाते हैं, तब भारतसरकार कहाने हैं। पर कौन्सिलके विषयमें भी एक बात याद रखनी चाहिये। पहले गवर्नर-जेनरलकी दो कौन्सिलें थीं,

एक एग्जिश्यूटिव कौन्सिल या शासनकारिणी सभा दूसरी लेजिस्लेटिव कौन्सिल या व्यवस्थापिका सभा । परन्तु जब भारतसरकार या “गवर्नर जेनरल-इन-कौन्सिल” कहते थे, तब वहा कौन्सिलका अर्थ शासनकारिणी सभा ही होता था, व्यवस्थापिका सभा नहीं । इसका कारण यह है कि गवर्नर-जेनरलके साथ कौन्सिल शब्दका प्रयोग व्यवस्थापिका सभा स्थापित होनेके घोरियों वर्ष पहलेसे होता आता है ।

भारतसरकारका इतिहास जाननेके लिये हमें १७७३ का

गवर्नर जेनरलके रेगुलेशन ऐक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि

इसके पहले गवर्नर-जेनरल और
पहलेकी व्यवस्था । कौन्सिलका अस्तित्व न था, कल

कत्ते, बम्बई और मद्रासमें कम्पनीके व्यापार, किलों और कोठियो तथा शासनाधीन देशकी व्यवस्था करनेके लिये गवर्नर या प्रेसिडेंट और उनकी कौन्सिल थी । इन स्थानोंमें प्रेसिडेंट रहनेके कारण ये “प्रेसिडेन्सी” नामसे प्रख्यात हुए और कौन्सिल द्वारा इनका प्रबन्ध होनेसे इनकी शासनपद्धति “कौन्सिल गवर्नमेंट” कहायी । इन कौन्सिलोंमें प्राय १० से १६ मेम्बर तक होते थे । कलकत्तेमें कम्पनीका किला “फोर्ट विलियम” और मद्रासमें “फोर्ट सेंट जार्ज” कहाता था, और कम्पनीके कागजपत्रोंमें इन नगरोंके बदले किलोंके नाम ही लिखे जाते थे । हिन्दुस्थानमें कम्पनीकी तीनो प्रेसिडेन्सिया परम स्वतन्त्र थीं और सबपर “कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स” की

प्रभुता थी । इससे, जिस प्रेसिडेन्सीके मनमें जो भाता था वह वही कर उठाती थी और इस प्रकार, काममें घड़ी गड़बड़ होती थी । इसे दूर करनेके अभिप्रायसे रेगुलेटिंग बना और फोर्ट विलियमके गवर्नर वारेन हेस्टिंग्ज् गवर्नर जेनरल बनाये गये तथा इनकी सहायताके लिये चार सभासदोंकी कौन्सिल या शासनकारिणी सभा बनी । लेफ्टेनेंट जेनरल जान क्लैवरिंग, जार्ज मान्सन, सर फिलिप फ्रांसिस और रिचार्ड वारवेल चारो मेम्बरोंके नाम ऐक्टमें लिखे हैं । पहले तीन तो इंग्लैंडसे आये और चौथा मेम्बर यही था । गवर्नर-जेनरलका वार्षिक वेतन २५,००० पाँड और मेम्बरोंका १०।१० हजार पाँड ऐक्टमें लिखा गया और पाचो ५।५ वर्षके लिये नियुक्त हुए ।

इस ऐक्टने ही वर्तमान भारतसरकारकी नींव डाली थी । गवर्नर जेनरल और इसके पास होनेसे बम्बई और मद्रास कौन्सिलके अधिकार । प्रेसिडेन्सियोंपर बङ्गालका प्राधान्य हो गया, क्योंकि गवर्नर-जेनरल और कौन्सिलको उनके शासन तथा प्रबन्धकी देय मालका अधिकार दिया गया । इस समयसे भारतीय नरपतियोंसे सन्धि विग्रह करनेका उनका अधिकार छिन गया और कोर्ट आफ डाइरेक्ट्स या गवर्नर-जेनरल और कौन्सिलकी आज्ञा लिये बिना वे यह काम नहीं कर सकती थीं । गवर्नर जेनरलके लिये अपनी कौन्सिलके बहुमतसे ही कार्य करनेका नियम बना और किसी विषयपर दो मत और

नो ओर मतसंख्या समान होनेपर उन्हें एकमत अधिक
 का अधिकार मिला था । १७८४ के ऐक्टसे गवर्नर-
 जनरलकी कौन्सिलके चार मेम्बरोंके बदले भारतमें कम्पनीकी
 कमांडर इन चीफ या प्रधान सेनापति समेत तीन ही
 रखे गये । गवर्नर जनरलके बाद प्रधान सेनापतिकी
 पदगौरव रहा । इसी ऐक्टमें गवर्नर जनरलको अधिकार
 मिला कि जिस मनुष्यपर किसी भारतीय नरपति वा अधि-
 कारसम्पन्न व्यक्तिके नियमविरुद्ध पत्र व्यवहार करनेका सन्देह
 हो, उसे कैद करनेके लिये आप चार्टर निकाल सकते हैं ।
 १७८६ में जनरल लार्ड कार्नवालिसको बंगालकी गवर्नर-जनरली
 मिलने लगी, तब उन्होंने कहा कि मेरे अधिकार बढ़ाइये तो मैं
 से स्वीकार करू । इसपर गवर्नर-जनरल ही प्रधान सेना-
 पति बना दिया गया, पर लार्ड कार्नवालिस इससे भी सन्तुष्ट
 हुए और अधिक अधिकार मागने लगे । इस लिये १७८१
 में विशेष ऐक्ट पास हुआ जिससे विशेष अवसरोंपर गवर्नर-
 जनरलको अपनी कौन्सिलका बहुमत अस्वीकार करने और
 अपने उत्तरदायित्वपर काम करनेका अधिकार दिया गया । साथ
 ही लार्ड कार्नवालिसकी आशाएँ भी नियमानुसूल ठीक ठहरायी
 गयीं । १७८३ के चार्टर ऐक्टमें यह नियम किया गया कि
 कमांडर इन चीफ तबतक कौन्सिलके मेम्बर नहीं हो सकते,
 तबतक डाइरेक्टरोंकी ओरसे वे मेम्बर न नियुक्त किये
 जायें ।

यद्यपि गवर्नर-जेनरल और उनकी कौन्सिलको कम्पनीके अधीन भारतवर्षके शासन और प्रबन्धके निरीक्षणका अधिकार था, तथापि वे उत्तरदाता कौन हैं ? बङ्गालके ही गवर्नर-जेनरल कहाते थे । पर १८३३ का चार्टर ऐक्ट बननेसे समस्त ब्रिटिश भारतपर गवर्नर-जेनरल और उनकी कौन्सिलका प्राधान्य पूर्ण तथा स्पष्ट रूपसे हो गया और वे भारतके गवर्नर-जेनरल बनाये गये । इसी ऐक्टमें चम्पई और मद्रास प्रेसिडेन्सियोंके लिये नियम बना कि वे सब विषयोंमें कौन्सिल सहित गवर्नर-जेनरलकी आज्ञाका पालन करें । इस ऐक्टकी ३६ वीं धारामें गवर्नर जेनरल और कौन्सिलको अधिकार मिला कि वे भारत शासनसे सम्बन्ध रखनेवाले मुल्की और जमीं मामलों तथा भारतीय राजस्वका “निरीक्षण, नियन्त्रण और निर्देश” करें । कोर्ट आफ डाइरेक्टर्सने ऐक्टकी प्रतिलिपिके साथ जो पत्रीता भारत भेजा था, उसमें ३६ वीं धाराके विषयमें लिखा था, कि “सेना तथा देश सम्बन्धीय समस्त भारतीय शासन आपके हाथमें है और उसकी भलाई बुराईकी नेकनामी बदनामी आपकी होगी ।” जर्थात् इसी समयसे गवर्नर-जेनरल और उनकी कौन्सिलपर भारतशासनका उत्तरदायित्व हो गया ।

१८३३ के चार्टरने ऐक्ट भारतशासन व्यवस्थामें और भी प्रदेशोंकी सुधार किये । इस समयतक बङ्गाल, चम्पई और मद्रास ये तीन ही प्रेसिडेन्सिया थीं । बङ्गाल प्रेसिडेन्सीके गवर्नर जेनरल और कौन्सिलके अधीन शेष दोनो प्रेसिडेन्सिया

थी। १७७३ से १८३३ तक ६० वर्षके बीच पञ्जाबको छोड़ समस्त उत्तर भारत कम्पनीके अधीन हो गया था और बङ्गाल प्रेसिडेन्सीमें मिला दिया गया था। इतनी बड़ी प्रेसिडेन्सीका शासन और अन्य दो प्रेसिडेन्सियोंका निरीक्षण करना गवर्नर जनरल और कौन्सिलके लिये असम्भवसा हो रहा था। इस लिये इस ऐक्टमें यह व्यवस्था की गयी कि बङ्गाल प्रेसिडेन्सीके दो भाग कर दिये जाय और एक फोर्ट विलियम प्रेसिडेन्सी तथा दूसरा आगरा प्रेसिडेन्सी कहावे। पर इसके अनुसार कार्य न हुआ और दो वर्ष बाद १८३५ में एक और ऐक्ट पास हुआ, जिससे पश्चिमोत्तर प्रदेशके लिये एक लेफ्टिनेण्ट गवर्नर नियुक्त हुआ। बङ्गाल प्रेसिडेन्सी गवर्नर जनरल और कौन्सिलके शासनाधीन रही। पर जब गवर्नर जनरल और कौन्सिलके लिये इतना भी कार्य बहुत समझा गया, तो १८५३ के चार्टर ऐक्टमें बङ्गालके लिये स्वतन्त्र गवर्नर नियुक्त करना निश्चित हुआ। पर पार्लमेंटकी इच्छाके अनुसार कार्य न हुआ और पश्चिमोत्तर प्रदेशकी तरह बङ्गालके लिये भी १८५४ में लेफ्टिनेण्ट गवर्नर नियुक्त हुआ। १८७४ में बङ्गालसे ११ जिले निकालकर चीफ कमिशनरके अधीन कर दिये गये और इस प्रकार आसाम स्वतन्त्र प्रदेश बना। १९०५ में लार्ड कर्जनने बङ्गालके दो टुकड़े करके पूर्व बंगको आसामसे मिलाकर नया प्रदेश बना दिया था। पर १९१२ के १ अप्रैलसे आसाम फिर चीफ कमिशनरके अधीन कर दिया।

गया । बंगालके दोनो टुकड़े जोड़ दिये गये और बिहार, उड़ीसा और छोटानागपुर बंगालमें लेकर अलग प्रदेशमें परिणत किये गये तथा नये प्रदेशका शासन लेफ्टेनेंट गवर्नर और ३ मेम्बरोंकी कौन्सिलको सौंपा गया । भारत सरकार बंगालकोसे दिल्ली चला गयी और बंगालका शासन गवर्नर और उसकी कौन्सिलको सौंपा गया । १९१६ के गवर्नमेंट आक्ट इण्डिया ऐक्टके अनुसार युक्तप्रदेश, बिहार उड़ीसा, पंजाब मध्यप्रदेश और गरार तथा आसाम गवर्नरके प्रदेश बनाये गये और इनके गवर्नरोंकी सहायताके लिये शासन सभा और मंत्री नियुक्त किये गये ।

रेगुलेटिंग ऐक्टके बादसे अबतक गवर्नर-जनरलकी कौन्सिलके सचटनमें बहुत संशोधन हुआ है । रेगुलेटिंग ऐक्टने चार मेम्बरोंकी व्यवस्था की थी, पर १९८४ के ऐक्टसे मेम्बरोंकी संख्या तीन हो गयी और कमांडर-इन-चीफ अर्थात् प्रधान सेनापति भी इन तीनमें एक मेम्बर बनाये गये । इस प्रकार प्रधान सेनापतिको छोड़ मेम्बरोंकी संख्या दो ही रह गयी । १९६३ के चार्टर ऐक्टमें यह नियम बना कि यदि विशेष रूपसे प्रधान सेनापति कौन्सिलके मेम्बर न नियुक्त किये जाय, तो वे मेम्बर नहीं हो सकते । इस व्यवस्थासे प्रधान सेनापतिको छोड़कर तीन मेम्बर हो गये । परन्तु १९३३ के चार्टर ऐक्टसे मेम्बरोंकी संख्या फिर चार हो

गयी। चौथे मेम्बरके लिये यह नियम हुआ कि वह कम्पनीका
 नौकर न होया तथा उसका काम कानून बनानेमें सलाह
 देनाभर होगा। नासन सम्बन्धीय प्रश्नोंपर उससे न तो
 सम्मति ली जाती थी और न वह कौन्सिलमें बैठता ही था।
 इसी समयसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेन्सियोंका कानून
 बनानेका अधिकार भी छिन गया और ये सर्वथा पतत्र हो
 गयी। गवर्नर-जनरलकी कौन्सिल ही समस्त ब्रिटिश भारतके
 लिये कानून बनाने लगी थी। इसी ऐक्टमें यह भी नियम रखा
 गया कि अभीनक तीनो मेम्बर सिविलियन होते थे, पर अबसे
 एक फौजी भी हो सकेगा। १८५३में मद्रास और बम्बई
 प्रेसिडेन्सियोंको कानून बनानेका अधिकार फिर मिल गया।
 १८५६ तक चौथा मेम्बर चारिस्टर होता था, पर इस वर्ष उसका
 पद रिक्त होनेपर धर्मव्यवस्थामें निपुण एक सज्जन उस पदपर
 बैठा दिने गये। प्राय दो वर्षतक भारतसरकारकी कौन्सिलमें
 कोई व्यवस्था सदस्य ही न रहा। इस लिये १८६१के कौन्सिल
 भाव इण्डिया ऐक्टमें चारके बदले पांच सदस्योंकी नियुक्तिकी
 व्यवस्था हुई। भारतसन्धिमें अधिकार दिया गया कि वे
 प्रधान सेनापतिको गवर्नर जनरलकी कौन्सिलका असाधारण
 सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। इस समयसे प्रधान सेनापति
 बराबर असाधारण सदस्य नियुक्त होते आते हैं। इस ऐक्टमें
 मेम्बरोंकी योग्यता भी लिखी गयी। तीन मेम्बर तो ऐसे हो
 सकते हैं, जिन्होंने कमसे कम १० वर्षतक कम्पनी या महारानी-

की नौकरी की हो । चारिस्टर या स्काटलैंडके पेडवोस्केटोंकी फैकल्टीका पांच वर्षतक मेम्बर रहा हुआ मनुष्य चौथा मेम्बर या व्यवस्था सदस्य नियुक्त हो सकता है । पाचवें मेम्बरकी योग्यताका कुछ भी उल्लेख न होनेसे अर्थसदस्य ही पाचवा मेम्बर हुआ । १६७४ के ऐक्टमें रेल, नहरों, डाक, तार आदिके लिये छठा या पब्लिक वर्क्स मेम्बर रखनेकी व्यवस्था हुई थी, पर ३० वर्षतक इसका उपयोग न हुआ और १६०४ में जो ऐक्ट बना उसमें कहा गया कि महारानी छठा मेम्बर नियुक्त कर सकेंगी, पर “वह पब्लिक वर्क्सके लिये ही होगा” यह अश निकाल डाला गया । सन् १६०२ में भारतसरकारके पांच ही मेम्बर थे । एक व्यवस्था सम्वन्धीय, दूसरा सेना विषयक, तीसरा पब्लिक वर्क्सका, चौथा अर्थ तथा व्यापार वाणिज्यका और पाचवा होम, और रेवेन्यू ऐण्ड ऐग्रीकल्चर विभागोंका काम देखता था । सन् १६०५ में इस व्यवस्थामें परिवर्तन हुए । पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटके दो टुकड़े हो गये । रेलोंके सम्बन्धका काम एक प्रेसिडेंट और दो मेम्बरोंके रेलवे बोर्डके अधीन कर दिया गया और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटका अवशिष्ट कार्य उमी नामके स्वतन्त्र विभागके अधीन रहा था, पर राजस्व और कृषि विभागके मेम्बर इसके कार्यकी भी देखभाल करने लगे । होम डिपार्टमेंटके लिये अलग मेम्बर हुआ । फाइनान्स और कमर्स डिपार्टमेंटके भी दो भाग हो गये, एक अर्थ सदस्यके और दूसरा नवनियुक्त शिल्पवाणिज्य सदस्यके

अधीन किया गया। इसी वर्ष मिलिटरी डिपार्टमेंट उठा दिया गया और इसके बदले आर्मी ऐण्ड मिलिटरी सप्लाई डिपार्टमेंटोंकी सृष्टि हुई। आर्मी डिपार्टमेंट प्रधान सेनापतिके और मिलिटरी सप्लाई डिपार्टमेंट एक स्वतन्त्र मेम्बरके अधीन किया गया। इस प्रकार छ मेम्बरोंका कार्यविभाग हुआ। १९०६ में मिलिटरी सप्लाई डिपार्टमेंट उठा दिया गया और सेना सम्वन्धीय सब प्रबन्ध प्रधान सेनापतिके अधीन किया गया। इन प्रकार फिर पाच ही मेम्बर रह गये, पर १९१० के नवम्बरमें शिक्षा विभागकी सृष्टि हुई और इसके लिये छठा मेम्बर नियुक्त कर छकी सख्या पूरी कर दी गयी। वायस-रायकी कौन्सिलमें अर्डिनरी या साधारण मेम्बर तो अब भी छ ही हैं, परन्तु मेम्बरोंके अग्रीन विभागों और कार्यों में वायस-राय लार्ड रेडिगने ११ अप्रैल १९२३ से परिवर्तन किया है।

१८३३ के चार्टर ऐक्टके अनुसार ब्रिटिश भारतके शासन तथा सेनाप्रबन्धके “निरीक्षण, निदेश भारत सरकारके और नियन्त्रणका” अधिकार भारत-
अधिकार । सरकारको है। इस लिये भारत

सरकार समस्त भारत तथा उसके भिन्न भिन्न प्रदेशोंके शासनके लिये उत्तरदाता है। देशी रजवाड़ोंपर उसका प्रभुत्व है और देशरक्षाके लिये सेना उसके अधीन है। एशियाई राज्योंसे वह सन्धि कर सकती है। विदेशी राज्योंके अन्तर्गत प्रदेशमें वह अपनी सत्ता और अधिकारोंका उपयोग कर सकती है तथा

अपने अधीन भूभाग किसी राज्यको देने और उसके अपने भूभाग लेनेका भी उसे अधिकार है। साराश, सम्राट् की प्रतिलिपि होनेके कारण उसे सम्राट् की ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त हैं, जो भारतीय व्यवस्थाके विरुद्ध न हों। पर भारतसचिवकी इच्छाके विरुद्ध भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। १७७३ के रेगुलेशन ऐक्टमें व्यवस्था की गयी थी कि गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिल कोर्ट आफ डाइरेक्टर्सकी आज्ञा मानें और इसमें किसी प्रकारका संशोधन या परिवर्तन न होनेके कारण १८५८ के ऐक्टसे उक्त कोर्टके अधिकार भारत सचिवको मिल गये हैं, इस लिये भारतसरकार भारतसचिवकी आज्ञा माननेको बाध्य है। प्रायः वनस्पत आर्थिक विषयोंमें भारतसरकारको भारतसचिवकी इच्छानुसार कार्य करना पड़ना है, पर भारतसरकारको इन विषयोंमें भारतसचिवकी स्वीकृति पहले लेना पड़ती है :—

(१) टैक्सोंका घटाना या बढ़ाना जयवा दूसरे प्रकार करना जिनसे भारतीय आयका सम्बन्ध हो।

(२) आर्थिक नीतिमें नवीन परिवर्तन करनेकी कार्यवाही या कार्य।

(३) नाधारणत जिनसे पूर्ण प्रजन उत्पन्न हों अथवा अन्य कार्य।

अर्थात्, उत्तर

तो कोई कानून बना सकते हैं, न किसी नये पदकी सृष्टि कर सकती है और न ऐसा कोई सुधार ही कर सकती है जिससे सरकारका व्यय बढ़े। भारतसचिवकी स्वीकृति बिना क्रेन्सीके नियमोंमें परिवर्तन करना वा मृण लेना उसकी शक्तिके बाहर है। भारतसरकारके लिये यद्यपि किसी ऐक्टसे यह आवश्यक नहीं है कि वह कोई कानून बनानेके पहले उसका मसविदा भारतसचिवसे स्वीकार करा ले तथापि १८७० में बड़े लार्ड लार्ड मेयो और भारतसचिव ड्यूक ऑव थर्जिलमे इस विषयपर बड़ी लिखापट्टी हुई थी और अन्ततः ड्यूकने २४ नवम्बर १८७० के पत्रमें लार्ड मेयोको लिखा था कि भारतसचिवके अधिकारोंकी सीमा भारतमें बने हुए कानूनको रद्द कर देनेतक ही नहीं है, बल्कि "भारत सरकार ब्रिटिश सरकारकी शासनकारिणी सत्ता मात्र है, जिसे अधिकार है कि गवर्नर-जनरलसे कहे कि फला कानून पेश करो और सब सरकारी मेम्बरोंसे कहे कि इसके पक्षमें वोट दो।" इस सिद्धान्तके कारण पञ्जाब कैनाल ऐक्ट रद्द हुआ और दुबारा बनाया गया। १८७३में गवर्नर-जनरल लार्ड नर्थब्रुकको भारतसचिव लार्ड सैलिसरीने लिखा कि बहुत मामूली या जरूरी कानूनको छोड़कर सब कानूनोंके मसविदे हमारे पास भेज दिये जायें, जिसमें हम पहले ही उनपर सम्मति प्रकट कर सकें। इसपर कुछ लिखापट्टी हुई, पर मामला निपटा नहीं। १८७५ में भारतसरकारने विलायती कपडेपर ५) सैकडे आगत

कर बठा दिया । इसपर लार्ड नार्थमुक और लार्ड सैलिस गरीमें भगडा हो गया । लार्ड सैलिसगरीने कहा कि हमें खयर दिये बिना ही आपने क्यों कर बठा दिया । उन्होंने यह भी आशा दी कि भविष्यमें यदि कोई कानून पास करनेकी बड़ी आवश्यकता हो, तो हमें बिना विलम्ब पहले ही तारसे खयर दिया कीजिये । इसपर लार्ड नार्थमुकने इस्तीफा दे दिया । इस समयसे हर कानूनके लिये भारतसचिवकी आज्ञा पहले ले लेनी पडती है ।

यद्यपि भारतसरकारके लिये नीति निर्धारण करना भारत सचिवका काम है, तथापि भारत सरकार कार्य । शासन सम्बन्धीय सब कार्य भारत सरकारको ही करने पडते हैं । शासन शकट चलानेके लिये भारतसरकार पञ्जाल तथा उन प्रदेशोंमें जहा भूकरका स्थायी प्रगन्ध (लगानका दवामी यन्दोवस्त) नहीं है, उसका कुछ भाग लेती है । पड़े बड़े जमीन्दार अपनी रैयत पर ज्यादा मालगुजारी न बढ़ावें इसके लिये वह समय समय पर हस्तक्षेप करती है । मध्य प्रदेशमें तो वह जमीन्दारकी मालगुजारी भी ठीक करती है । पञ्जाबमें उसने यह व्यवस्था की है कि किसान किसानके सिवा किसी दूसरेको जमीन न उंच सके । जमीन्दारियोंके मालिकके अयोग्य या नावालिग होनेपर वह उनका प्रगन्ध करती है । अकालके समय वह अकाली काम खोलकर तथा अन्य प्रकारसे लोगोंके कष्ट दूर करती है । वह

जानूँका धन्दोयस्त करती और नमक तथा अफीम बनाती है। देशकी प्राय सब रेलें भारत सरकारकी ही हैं और वह स्वयं उनमें बहुतोंका प्रबन्ध करती है। उसने नहरें बनायी हैं और उनका प्रबन्ध करती है। डाक और तार विभाग उसीके हैं। नोट प्रचार करनेका अधिकार उसीको है और वही टकसालोंमें सिक्के ढाल सकती है। कभी कभी रुपयेको कमी होनेपर पैकोंको प्रण देती है। वह यहासे व्यापार मध्ये रुपये विलायत भेजती है और भारतसचिव वहा भारतसरकारपर हुडिया लिखकर ये रुपये बसूठ करते हैं। वह म्यूनिसिपैलिटियों, ग्राम पौलों, किसानों और कभी कभी कभी ऐतिहासिक भूसम्पत्तियोंके अधिकारियोंको प्रण देती है। वह शराब या मादक पदार्थोंको बिक्रीका नियन्त्रण करती है। यह काम बिना लाइसेन्सकी बिक्री रोकनेसे ही नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिये थोड़ी मुद्दतके लिये लोगोंको ठेके दिये जाते हैं और ये ठेके कुछ प्रकमोपर नीलाम होते हैं। पुलिस, शिक्षा, डाकूरी और स्वास्थ्य नियमक कार्य तथा और भी सड़को और सरकारी इमारतोंके सम्बन्धके बहुतसे कार्य भारत-सरकारको करने पड़ते हैं। इनके सिवा उसका बहुतेरे राज-घाड़ोंसे बड़ा प्रणिष्ट सम्बन्ध है। *

७ अधिकार विभाजक कमिशनने तोटके आधारपर ।

कमांडर-इन-चीफ तथा छ आर्डिनरी मेम्बरोंसे गवर्नर-

जेनरल भारत शासनशक्ति चलाते हैं।

विभागोंकी व्यवस्था पहले शासन सम्बन्धीय प्रत्येक

विषय कौन्सिलमें उपस्थित किया जाता

था और जैसा निश्चय होता था, उसके अनुसार कार्य किया जाता था। पर १७८६ में लार्ड कार्नवालिसको अधिकार

दिया गया था कि यहमत अस्वीकार कर अपने इच्छानुसार कार्य करें और मेम्बर और गवर्नर जेनरल अपने अपने पक्षकी बातें ठिप दिवा करे। इस समयसे बहुत बड़ी होने लगा।

लार्ड वेलेस्लेने इस निगमका अच्छा उपयोग किया। वे जो कुछ करते थे, उसमें कौन्सिलकी सम्मति प्राय नहीं लेते थे।

लार्ड कैनिंगके समयतक जो गवर्नर-जेनरल जिस विषयपर कौन्सिलकी सम्मति आवश्यक समझता था, लेता था, और जन चाहता था कौन्सिलकी उपेक्षा कर जाता था। १८६१ के

कौन्सिल आप इण्डिया ऐक्टकी ८ वी धाराने गवर्नर जेनरलको सरलता तथा शीघ्रतापूर्वक अपनी कौन्सिलके कार्यपरिचालनके लिये नियम बनाने तथा आदेश देनेका अधिकार दिया और

नियम किया कि इसके अनुसार प्रचारित आज्ञा या नियम कौन्सिल सहित गवर्नर-जेनरलके बनाये या प्रचारित समझे जायेंगे। इसके अनुसार लार्ड कैनिंगने अपनी कौन्सिलके चार

मेम्बरोंके अधीन चार विभाग कर दिये और फारेन डिपार्टमेंट या परगज्योंसे सम्बन्ध रखनेवाला विभाग अपने अधीन रखा।

इससे विशेष लाभ न हुआ, क्योंकि महत्वके प्रश्न गवर्नर-जेनरलके विचारार्थ भेजने पड़ते थे और काममें बड़ा झमेला होता था। गवर्नर-जेनरलके कहीं जानेपर सरकारी काममें बड़ी देर होती थी। लार्ड मेयोके समयमें इस व्यवस्थामें कुछ और सुधार हुए। परन्तु फिर भी जैसी चाहिये वैसी सरलता न हुई। आजकल भारतसरकारका कार्य इन आठ बड़े विभागोंमें बंटा है,—होम (स्वदेश) फारेन (परराज्य), फाइनान्स (अर्थ), लेजिस्लेटिव (व्यवस्था), एजुकेशन, हेल्थ ऐण्ड लैड्स (शिक्षा, स्वास्थ्य और जमीन), रेलवेज ऐंड कमर्स (रेलवे और वाणिज्य), आर्मी (सेना) और इण्डस्ट्रीज ऐंड लेबर (उद्योगधन्धे और मजूर)। फारेन डिपार्टमेंट गवर्नर-जेनरलके अधीन है और आर्मीपर कमांडर-इन-चीफका प्रभुत्व है। होम, फाइनान्स, लेजिस्लेटिव, रेलवेज ऐंड कमर्स, इण्डस्ट्रीज ऐण्ड लेबर इन ६ विभागोंका काम देखनेके लिये ६ “आर्डिनरी” मेम्बर नियुक्त हैं।

भारत सरकारका सब कार्य उक्त विभागोंद्वारा ही होता है यह बताया जा चुका है। अब यही विभागोंके काम। कहना है कि किस विभागको कौन काम करने पड़ते हैं। फारेन डिपार्टमेंट अथवा परराज्य विभाग परराजनीतिसे सम्बन्ध रखता है। विदेशी राज्यों तथा भारतान्तर्गत, देशी रजवाड़ों आर करद राज्योंसे सम्बन्ध, सीमान्तके जिलोंके शासनका नियन्त्रण और

सोमान्तकी तथा पहाड़ी जानियोंसे सम्बन्ध, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ेका शासन, राजनीतिक कैदी, राजनीतिक पेंशन, एमर्जेंडिशन और ब्रिटिश भारतके बाहर भारत सरकारके अधिकार, सिनारे हिन्द आदि पदविया, परराष्ट्रोंके वाणिज्यदूतोंको स्वीकार करना, इम्पीरियल सर्विस सेना और इम्पीरियल क्रेडिट कोर फारेन डिपार्टमेंट सम्बन्धीय कार्य हैं। ब्रिटिश भारतके बाहरकी राजनीतिका निर्णय जैसे फारेन डिपार्टमेंटके अधीन है, वैसे ही भीतरी राजनीतिका नियन्त्रण होम डिपार्टमेंट करता है। इण्डियन सिविल सर्विस, आगारा यूरोपियनका (१८७४) ऐक्ट, कानून और न्याय, लावारिस बेतसीधती जायदादें, जेल और कालागानी, पुलिस, निवार और शासन सम्बन्धीय कर्मचारियोंका मन्त्रानिर्धारण, इण्डियन आर्म्स ऐक्ट तथा मनुष्यगणना परदेशियोंको स्वदेशियोंके अधिकार देकर स्वदेशी बना लेना, होम डिपार्टमेंटका काम है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, ब्रिटिश बलूचिस्तान और अजमेरमेरवाड़ेपर होम डिपार्टमेंटकी सत्ता नहीं है। रेलवेज और वाणिज्य विभाग वा रेलवेज ऐंड कमर्स डिपार्टमेंटका सम्बन्ध (१) रेलवे, (२) व्यापार वाणिज्य तथा उसके अन्तर्गत व्यापारी मालके मार्के, आगत और निर्गत करके नियम, स्टेटिस्मिक्स (स्थिति), जान बीमा और अडिटिंगका काम (हिसाब किताबकी जांच) (३) व्यापारी जहाज, बन्दर, बन्दरका फर और कर्णिक वेतन (जहाजको

राह यतानेवालेका वेतन), (४) स्थलमार्गका व्यापार, (५) व्यापारिक प्रदर्शन, (६) बटखरों और पैमानोंसे है । उद्योगधन्धे और मजूर विभाग चा इण्डस्ट्रीज ऐंड लेबर डिपार्टमेंटका सम्यन्ध (१) इण्डियन फैक्ट्रीज ऐक्ट (२) भूगर्भविद्या और खनिज पदार्थ, (३) कोयलेकी सरकारी खानें और लोहेके कारखाने (४) तार और टेलिफोन, (५) पोस्ट आफिस (६) इण्डियन एक्सप्रोसिज्ज ऐक्ट, (७) इण्डियन पीट्रोलियम ऐक्ट (८) स्टेशनरी (कागज कलम दावात आदि) और छपाई, (९) सामान जुटाने (१०) अन्त-राष्ट्रीय मजूर सघटन (११) पेटेंट, डिजाइन, (१२) कापीराइट (१३) स्टीम वायलर और पलिक्लिड्रिसिटी (गिजलीके) कानून (१४) असैनिक आकाश यात्रा (१५) अन्तरिक्ष विद्या, (१६) उद्योगधन्धोंकी प्रगति, (१७) पब्लिक वर्क्स (सरकारी इमारतें) और (१८) आगपाशीसे है । फाइनान्स डिपार्टमेंट चा अर्थ विभाग भारत सरकारका हिसाय कितान रखता है, बजेट बनाता, आय व्ययका अनुमान लगाता, बैंकोंसे सम्बन्ध रखता, आय छोडता, सरकारी परच ठीक करता, आयका ढङ्ग बँटाता, ऋण लेता, टकमाल, पेपरकरेन्सी, सरकारी अफसरोंकी छुट्टी, वेतन, भत्ते और पुरस्कारकी व्यवस्था करता, टैक्स लगाता और अपने अधीन बोर्ड आच रेवेन्यूद्वारा कस्टस्, अफीम, एक्साइज और स्टाम्पकी आयकी व्यवस्था कराता हैं । मिलिटरी फाइनान्स प्राच सैनिक अर्थ व्यवस्था करनेके लिये इसकी शाखा

है। एजुकेशन, हेल्थ ऐंड लेइस डिपार्टमेंट वा शिक्षा स्वास्थ्य और भूमि विभाग शिक्षा, सरकारी मालगुजारी, जमीनकी पैमाइश, खेतीबाड़ी, जङ्गल, पेंड पौधे लगानेकी विद्या, असैनिक पशुचिकित्सा व्यवस्था, अकाल, रुपि सम्बन्धीय दशा तथा खाद्यपदार्थ, देशान्तरवास, नकशे, डाक्टरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशुशास्त्र, स्थानिक स्वराज्य, पुस्तकालय और कौतुकागारो वा अजायबघानों आदिसे सम्बन्ध रखता है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट या व्यवस्थापक विभाग सभाओंके अधिवेशनोंकी कार्यविवरणी लिखता तथा कानूनोंके मसविदे और कानून छापता और व्यवस्थापिका पण्डित और राज्य सभा सम्बन्धीय सब सूचनाएँ प्रकाशित तथा अन्यान्य कार्य करता है। आर्मी डिपार्टमेंट वा सेना विभाग सेना सम्बन्धीय सब कार्य करता है। इन विभागोंके अतिरिक्त कई छोटे विभाग हैं, जिनमें एक्ज़िसिव्ह डिपार्टमेंट वा ईसाई धर्म विभाग सबसे महत्वका है। खेतीबाड़ी, जङ्गल, आयपाशी, मेडिकल सर्विस आदि कितने ही विषयोंके डाइरेक्टर तथा सैनिटरी कमिशनर और ऐडमिनिस्ट्रेटर-जेनरल नियुक्त हैं, जो प्रादेशिक सरकारों और भारत सरकारको उक्त विषयोंमें परामर्श देते हैं। भारत सरकारकी शासनव्यवस्थाका जो वर्णन अधिकार

सरकारकी विभाजक कमिशनने किया है, उसका साराश यहा अप्रार्सगिक न होगा।

शासनव्यवस्था । प्रति सप्ताह कौन्सिलका अधिवेशन होता है। इसमें उन विषयोंपर विचार होता है, जिनपर

घायसराय विचार कराना चाहते हैं अथवा घायसरायसे अस्वीकृत जिस विषयपर कोई मेम्बर कौन्सिलका निर्णय चाहता है। जिस विभागसे सम्बन्ध रखनेवाले विषयपर विचार होता है, उसका सेफ्टरी बगलके कमरेमें बैठा रहता है और आवश्यकता पड़नेपर मेम्बरको सहायता देता है। यदि किसी विषयपर मतभेद होता है, तो साधारणतः बहुमत ही मान्य होता है, पर घायसरायकी समझसे यदि कोई विषय विशेष महत्वका हो, तो वे बहुमत अस्वीकार कर सकते हैं।

प्रत्येक मेम्बरको अपने विभागके साधारण कार्य करनेका अधिकार है। पर विशेष महत्वके तथा प्रादेशिक सरकारोंके मत अस्वीकार करनेके प्रश्नोंपर घायसरायकी आज्ञा ली जाती है। यद्यपि इससे घायसरायका कार्यभार बढ़ता है, तथापि प्रादेशिक सरकारोंके कार्यमें अनुचित हस्तक्षेप नहीं होने पाता। १९०७ ८ में होम डिपार्टमेंटने फी सैकडे २१७ मामलोंमें घायसरायकी आज्ञा ली थी। यदि किसी विभागके किसी प्रश्नसे दूसरे विभागका सम्बन्ध होता है और दोनों आपसमें उसकी मीमांसा नहीं कर सकते, तो वह घायसरायके यहाँ पेश किया जाता है।

प्रत्येक विभागका आफिस एक सेफ्टरीके अधीन होता है। यह साधारणतः तीन वर्षके लिये नियुक्त होता है। जैसा ऊपर कहा गया है, यह कौन्सिलके अधिवेशनोंमें उपस्थित रहता है और साधारणतः प्रति सप्ताह घायसरायको अपने

विभागकी बातें बताता और उनपर आज्ञा लेता है। अपने विभागका मेम्बर जिस कार्यको करना चाहता है, उसमें यदि उसे वायसरायके सहमत होनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है, तो वायसरायका विशेष रूपसे उसपर ध्यान आकृष्ट करनेका उसे अधिकार है। सेक्रेटरीके नीचे डिप्टी, अण्डर, और ऐसिस्टेंट सेक्रेटरी तथा बहुतसे क्लर्क होते हैं। ऐसिस्टेंट सेक्रेटरी प्रायः स्थायी रूपसे उस विभागमें रहता है।

भारत सरकारका सबसे महत्वपूर्ण अङ्ग गवर्नर-जेनरल गवर्नर-जेनरलके या वायसराय है। सम्राट् के प्रति-निधि होनेके कारण गवर्नर-जेनरल वायसराय कहाते हैं, पर पार्लमेंटके ऐक्टोंसे उन्हें यह नाम नहीं मिला है। अपने प्रधान मन्त्रीकी सम्मतिपर सम्राट् किसी योग्य व्यक्तिको भारतका गवर्नर-जेनरल नियुक्त करते हैं। यह पद प्रायः लार्ड और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ वा अनुभवी शासकको मिलता है। यदि नियुक्तिके समय गवर्नर-जेनरल लार्ड नहीं होते, तो भारत पहुँचनेके पहले ही लार्ड बना दिये जाते हैं। गवर्नर-जेनरलका वार्षिक वेतन २,५०,८००) है। श्रीमान् सम्राट् के हस्तारगुक्त चार्ट वा आज्ञापत्रसे गवर्नर-जेनरल ५ वर्षके लिये नियुक्त होते हैं। कौन्सिलके "आर्डिनरी" मेम्बर भी इसी प्रकार राजकीय आज्ञासे नियुक्त होते हैं। गवर्नर-जेनरल या किसी मेम्बरपर हाई-कोर्टमें भी किसी तरहका मामला नहीं चल सकता और न वे

गिरफ्तार या कद ही किये जा सकते हैं। गवर्नर-जेनरल यदि इस्तीफा देना चाहें, तो नियमानुसार उन्हें "डीड" या वस्तायेज लिफा देना पड़ता है। १७७६ में वारेन हेस्टिग्सने अपने पनेटकी मार्फत इस्तीफा दिया था, क्योंकि कौन्सिलके जो तीन मेम्बर विलायतसे आये थे, वे हर काममें उसे बाधा देते थे और बहुमत विरुद्ध होनेसे वह छटपटाकर रह जाता था। कोर्ट आय डाइरेक्टर्सने इस्तीफा रद्दीकार भी कर लिया था। परन्तु जब एक विरोधी मर गया और दूसरा बीमार होकर विलायत चला गया, तब वारेन हेस्टिग्सने इस्तीफा लौटा लिया और सुप्रीम कोर्टसे अपने पक्षमें यह सम्मति भी ले ली कि इस्तीफा देना नाजायज था। इस लिये १७६३ और १८३३ के ऐक्टोंमें यह स्पष्ट लिख दिया गया कि बिना नियमित "डीड" गवर्नर-जेनरलका इस्तीफा नाजायज समझा जायगा। गवर्नर-जेनरलकी ३१ तोपोंकी सलामी होती है। कौन्सिलके अन्य सदस्योंकी अपेक्षा गवर्नर-जेनरलको विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। वे अधिकार ये हैं,—

- (१) कौन्सिलके अग्जिप्रेशनमें अध्यक्षका आसन ग्रहण करना ।
- (२) दीरेपर जानेके पहले कौन्सिलका उपाध्यक्ष नियुक्त करना ।
- (३) कार्यनिर्वरणपर हस्ताक्षर कर उसे रद्दीकार करना ।
- (४) भारत सरकारकी आज्ञा प्राप्त कर दीरेपर भारत सरकारके अधिकारोंका उपभोग करना ।

- (५) कौन्सिलके केवल एक सदस्यकी सम्मति लेकर भारत सरकारके अधिकारोंका उपयोग करना ।
- (६) शीघ्रता और सुगमतापूर्वक कौन्सिलके कार्य सञ्चालनके लिये नियम बनाना तथा आज्ञा प्रचारित करना ।
- (७) अपनी व्यवस्थापिका सभाके गैरसरकारी मेम्बर मनोनीत करना ।
- (८) निम्नलिखित विषयोंके कानूनोंके मसौवदे पेश करने या न करनेकी आज्ञा देना -
- (अ) भारतके ऋण या राजस्व सम्वन्धी अथवा जिनसे छर्च बढे ।
 - (आ) भारतके किसी सम्प्रदायके धर्म, अधिकार या आचरण सम्वन्धी ।
 - (इ) राजकीय जल वा स्थल सेनाके किसी भागके विनयानुशासन वा स्थिति सम्वन्धी ।
 - (ई) विदेशी राजाओं या राज्योंने सरकारके सम्वन्ध विषयक ।
- (९) पास हुए कानूनको मजूर या नामंजूर करना ।
- (१०) आर्डिनैन्स जारी करना जो छ महीनेतक कानून माने जाते हैं ।
- (११) प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओंके बनाये हुए कानूनोंको स्वीकार अथवा

अस्वीकार करनेके कारण उक्त सरकारोंको लिख भेजना ।

(१२) नये प्रदेश बनाना और लेफ्टिनेण्ट गवर्नर नियुक्त करना ।

(१३) ब्रिटिश भारतकी शान्ति, सुरक्षा अथवा स्वार्थोंमें बाधा पड़ती दिखे, तो अपनी कौन्सिलके बहुमतको उपेक्षा कर स्वेच्छानुसार कार्य करना ।

(१४) किसी मनुष्यको फासीकी आज्ञा हो चुकी हो और प्रादेशिक शासकने उसकी फासी काटना अस्वीकार किया हो, तो उसकी फासी काट देना ।



चतुर्थ अध्याय



प्रादेशिक सरकारें ।

ब्रिटिश भारतके सुशासनका उत्तरदायित्व भारत सरकारपर ही है, परन्तु इतने बड़े देशका शासन प्रादेशिक सरकारें भारत सरकार जैसी सस्थासे असम्भव और उनका नियंत्रण है, इस लिये समस्त ब्रिटिश भारत छोटे बड़े १५ प्रदेशोंमें बटा है। प्रत्येक प्रदेशके शासनकी स्वतन्त्र व्यवस्था है। जो सरथा प्रदेशका शासन करती है, वह प्रादेशिक सरकार कहाती है। प्रादेशिक सरकारें भारत सरकारके अधीन हैं और यह निम्न प्रकारसे उनका नियन्त्रण करती है,—

(१) आर्थिक नियमों और जांचोंसे जिनमें इम्पीरियल डिपार्टमेंटल कोडोंके नियम भी हैं ।

(२) शासन सम्बन्धी साधारण वा विशेष हस्तक्षेपसे, जिसके लिये (अ) कानून हो या कानून जैसे ही नियम हों, वा (आ) बहुत दिनोंके व्यवहारसे जो नियमसा ही बन गया हो ।

(३) प्रदेशोंके कानूनोंके मसविदोंकी जाच और प्रादेशिक

व्यवस्थापिका सभाओंके पास किये काननोंकी मंजूरीसे ।

(४) प्रादेशिक सरकारोंके सूचनार्थ नीति सम्बन्धी मन्तव्य प्रकाशनसे । जिन विभागोंसे प्रादेशिक सरकारोंका विशेष सम्बन्ध है, उनकी कार्यपद्धतिकी जाचके लिये भारत सरकार समय समयपर कमिशन या कमिटिया नियुक्त करती है और इनकी रिपोर्टों पर मन्तव्य प्रकाशित करती है ।

(५) प्रादेशिक सरकारोंकी कार्यविवरणी वा विभागोंकी सामयिक रिपोर्टों से जिन विषयोंकी ओर भारत सरकारका ध्यान आकृष्ट हुआ हो, उनके विषयमें किसी विशेष प्रादेशिक सरकारको आज्ञाप देकर ।

(६) इम्पीरियल इन्स्पेक्टर जनरलोंका ध्यान निज विषयोंकी ओर आकृष्ट किया गया हो, उनपर फावरवाई करनेसे ।

(७) प्रादेशिक सरकारकी आज्ञाओं वा कार्यों से असन्तुष्ट लोगोंकी अपीलोंपर विचार करके ।

ब्रिटिश भारतके भिन्न भिन्न प्रदेशोंकी कुछ बातें पिछले अध्यायमें आ गयी हैं । इस लिये

प्रदेशोंका इतिहास । यहाँ उनके विषयमें कुछ विशेष बातें ही लिखी जायगी । पहले ईस्ट इण्डिया

कम्पनीकी बंगाल चम्पई और मद्रास ये तीन प्रेसिडेन्सिया थीं

और जो नये प्रदेश उसके हाथ आते जाते थे, उन्हें निकटताके अनुसार वह इनमें मिलाती जाती थी। १८३३ के चार्टर ऐक्टसे आगरा प्रेसिडेन्सी बनाना निश्चय हुआ था, पर १८३५में कोर्ट आफ डाइरेक्टर्सके प्रस्तावानुसार पश्चिमोत्तर प्रदेशकी लेफ्टेनेंट गवर्नरीकी सृष्टि हुई। फोर्ट विलियम प्रेसिडेन्सीका शासन गवर्नर जनरल स्वयं करने लगे और इसके लिये दफ्तर तथा कर्मचारी स्वतन्त्र रखे गये। १८४३में सिन्ध बम्बई प्रेसिडेन्सीमें मिलाया गया। पहले सिक्ख युद्धके बाद पञ्जाबको कम्पनीने अपने अधीन कर लिया और कौन्सिल आफ रिजेन्सी बनाकर वहाँ अपना रेजिडेंट रख दिया, जो नाबालिग महाराज दलीपसिंहके नामपर पञ्जाबका शासन करने लगा। दूसरे सिक्ख युद्धके बाद समस्त पञ्जाब अङ्गरेजी राज्यमें मिला लिया गया और कौन्सिल सहित गवर्नर-जनरल पहले बोर्ड आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन और फिर चीफ कमिशनर द्वारा इसका शासन करने लगे। १८५४ में बङ्गाल लेफ्टेनेण्ट गवर्नरके शासनाधीन किया गया। इसी वर्ष नागपुरके राजा राधोजी भोंसला मर गये और उनका राज्य अङ्गरेजी राज्यमें मिला लिया गया। दो वर्ष बाद अन्ध भी कम्पनीने ले लिया और एक चीफ कमिशनरके अधीन किया और १८७७ में वह पश्चिमोत्तर प्रदेशमें मिला दिया गया तथा १९०१ में दोनोंका नाम बदलकर आगरा और अवधका संयुक्त प्रदेश कर दिया गया, क्योंकि इसी वर्ष पञ्जाबके कई जिले और सीमाप्रदेश लेकर पश्चिमोत्तर

सामाप्रदेश घना था और दोनो प्रदेशोंके नाम एकसे होनेसे भ्रमकी सम्भावना थी । गद्दरके बाद दिल्ली प्रान्त पश्चिमोत्तर प्रदेशसे लेकर पञ्जाबमें मिला दिया गया और १८५६ में पञ्जाबका शासनभार एक लेफ्टिनेण्ट गवर्नरको दिया गया । १८६१ में सागर और नर्मदा प्रान्त पश्चिमोत्तर प्रदेशसे लेकर नागपुरमें मिला दिये गये और इस प्रकार मध्यप्रदेशकी चीफ कमिशनरी घनी । आया दरबारने १८२५ और १८५३ में बर्माके जो प्रदेश कम्पनीको दिये थे, वे भारत सरकारके कमिशनरोंके शासनाधीन किये गये । १८६२ में सबको मिलाकर ब्रिटिश बर्मा प्रदेश बना दिया गया और उसका शासनभार एक चीफ कमिशनरको मिला । अन्तिम बर्मा युद्धके बाद १८८६ में अपर बर्मा भी ले लिया गया और १८६७ में अपर और लोअर बर्मा दोनोके शासनके लिये लेफ्टिनेण्ट गवर्नर नियुक्त हुआ । हैदराबाद राज्यमें ब्रिटिश अफसरोंके अग्रीन हैदराबाद कंटिजेन्ट नामकी जो सेना है, उसके खर्चके लिये १८५३ में निजामने अङ्गरेज सरकारको वरार दे दिया था । सन्धि यह थी कि खर्च देकर जो रकम बचेगी, वह हैदराबाद दरबारको मिलेगी । इस प्रदेशका शासन हैदराबादके रेजिडेण्टके अधीन एक कमिशनर करता था । पर वरारमें निजामके अधिकारोंके विषयमें निजाम और भारत सरकारमें मतभेद होनेके कारण १९०७ में लार्ड कर्जनने निजामसे यह सन्धि कर ली कि नाममात्रके लिये वरार आपका रहेगा, पर आपका उससे कोई सम्बन्ध न

रहेगा, केवल भारत सरकार आपको २५ लाख रुपये प्रति वर्ष दिया करेगी । १८२४ में बर्मों लोगोंसे आसाम लेकर बङ्गालमें मिलाया गया, पर १८७४ में चीफ कमिशनरके अग्रीन किया गया । १९०५ में वह पूर्व बर्गमें मिलाया गया, पर १९१२ में फिर खनल्व चीफ कमिशनरी बना दिया गया । इसी वर्ष बङ्गालके दोनो टुकड़े जुड़े और उससे बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर अलग करके लेफ्टिनेण्ट गवर्नर और कौन्सिलके शासनाधीन किये गये । १८३४ में दक्षिण भारतका कुर्ग राज्य ब्रिटिश भारतमें मिलाया गया और उसके चीफ कमिशनर मैसूरके रेजिडेण्ट हैं । १८१८ से अजमेर-मेरवाड़ेका जिला अङ्गरेजोंके हाथ आया था और तबसे गवर्नर-जेनरलके राजपूताना एजेण्ट उसके चीफ कमिशनर हैं । १८७६ में खैलानके पाससे प्येटा और अफगानिस्तानसे उसके पासका प्रदेश खरीदा गया तथा त्रिना धनीधोरीका कुछ प्रदेश लेकर १८८९ में ब्रिटिश उल्खिस्तानकी चीफ कमिशनरीकी सृष्टि हुई । अण्डमन और निकोबार टापुओंके चीफ कमिशनर पोर्ट ब्लेयरके सुपरिण्डेण्डेंट हैं । १९१२ की १ली अक्टूबरको पञ्जाबसे ५५७ वर्ष मील भूमि लेकर दिल्लीकी चीफ कमिशनरी बनायी गयी । इसमें ३,९१,८२८ मनुष्य रहते हैं । सन् १९१४ में कुछ गांव और मिलाये गये हैं, इससे वर्तमान दिल्ली प्रदेशका क्षेत्रफल और जनसंख्या पहलेसे कुछ बढ़ गयी है ।

१६०१ के इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्ट बननेके पहले ब्रिटिश

भारतान्तर्गत प्रदेशोंकी शासनपद्धति

शासनपद्धतियोंमें भेद । तीन प्रकारकी थी, परन्तु इनके बाद

ही एक चौथी पद्धति भी प्रचलित हो

गयी और आजकल दो ही पद्धतियाँ हैं । पहले तीन प्रकारकी

पद्धतियाँ थीं, (१) प्रेसिडेन्सी, (२) लेफ्टेनेण्ट गवर्नरी और (३)

चीफ कमिशनरी । प्रेसिडेन्सी पद्धतिमें प्रदेशका शासन गवर्नर

(प्रेसिडेंट) और कौन्सिल द्वारा होता था । लेफ्टेनेण्ट

गवर्नरीका शासन लेफ्टेनेण्ट गवर्नर और चीफ कमिशनरीका

चीफ कमिशनर करते थे । लेफ्टेनेण्ट गवर्नरी और चीफ

कमिशनरीमें शासकोके वेतनादिके सिवा उड़ा भारी अन्तर यह

था कि लेफ्टेनेण्ट गवर्नरके अधीन प्रदेशमें व्यवस्थापिका सभा

थी, पर चीफ कमिशनरीके लिये भारत सरकार ही कानून

बनाती थी । १६०६ के ऐक्टसे उद्दालके लेफ्टेनेण्ट गवर्नरके

सहायतार्थ शासनकारिणी सभा म्पटिन की गयी और १६१२

के गवर्नमेंट थाय इण्डिया ऐक्टसे उद्दाल प्रेसिडेन्सी बन गया

और उससे बिहार उड़ीसा लेकर लेफ्टेनेण्ट गवर्नरके अधीन

किये गये और इस प्रकार एक नयी लेफ्टेनेण्ट गवर्नरी बनी ।

लेफ्टेनेण्ट गवर्नरके सहायतार्थ शासनकारिणी सभा स्थापित

हुई । इसी ऐक्टमें भारत सरकारको चीफ कमिशनरियोंमें

व्यवस्थापिका सभा स्थापन करनेका अधिकार दिया गया ।

इस प्रकार गवर्नरी, कौन्सिल सहित लेफ्टेनेण्ट गवर्नरी

लेफ्टिनेंट गवर्नरी, व्यवस्थापिका सभायुक्त चीफ कमिशनरी और चीफ कमिशनरी ये पांच पद्धतियां थीं। १९१६ के ऐक्ट से सारे देशमें दो ही प्रकारकी पद्धतियां हैं, एक गवर्नरी और दूसरी चीफ कमिशनरी। गवर्नरी भी दो प्रकारकी है एक प्रोसिडेन्सी गवर्नरी, जिसमें गवर्नरका वेतन १२००००) वार्षिक है, शासनकारिणी सभाके चार चार मेम्बर और तीन तीन मिनिस्टर या मंत्री हैं और दूसरी लेफ्टिनेंट गवर्नरी या चीफ कमिशनरीसे बनी हुई गवर्नरी, जिसमें कोन्सिलके दो दो मेम्बर और दो दो मिनिस्टर हैं। दूसरा महत्वका अन्तर यह है कि इनके गवर्नर सिविलियन ही होते हैं। युक्तप्रदेशको छोड़ किसी प्रदेशके गवर्नरका वेतन १०००००) से अधिक नहीं है। नीचे प्रदेश और उनकी पद्धतियां दी जाती हैं,—

प्रदेश।

पद्धतियां।

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| (१) बङ्गाल, बम्बई और मद्रास | गवर्नर और शासनकारिणी व्यवस्थापिका सभाएं और मंत्री। |
| (२) बिहार और उड़ीसा, युक्तप्रदेश, | " " |
| पंजाब, चम्पा, आसम और | " " |
| मध्यप्रदेश | " " |
| (३) ब्रिटिश बलूचिस्तान, | केवल चीफ कमिशनर। |
| पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, दिल्ली, | " " |
| फुर्ग, ऐहमन निकोबार द्वीप | " " |
| और अजमेर मेरवाडा। | " " |

योंतो, सभी प्रदेशोंपर भारत सरकारकी प्रभुता है, पर प्रेसिडेन्सियोंकी विशेषता । प्रेसिडेन्सियोंका दर्जा अन्य प्रदेशोंसे ऊँचा है, क्योंकि धर्म्य और मद्रास प्रेसिडेन्सिया अन्य प्रदेशोंकी तरह

बंगाल प्रेसिडेन्सीने न तो उत्पन्न हुई हैं और न कभी चीफ कमिशनरोंकी अधीन रही हैं ; यदिक १७७३ के पहले वे परम स्वतन्त्र थीं और उस स्वतन्त्रताके कुछ चिह्न उनमें अब भी वर्तमान हैं । १७८४ के पिट्स ऐक्टसे उक्त प्रेसिडेन्सियोंकी कौन्सिलोंके सदस्यतामें यह सुधार हुआ था कि उनमें ३/३ मेम्बर रहेंगे, जिनमें कमांडर इन चीफ भी होगा । * १८३३ के ऐक्टमें यह संख्या घटाकर दो कर दी गयी । कमांडर इन-चीफके असाधारण सदस्य नियुक्त करनेकी व्यवस्था हुई और इसके अनुसार १८६३ तक कार्य होता रहा । इस समयसे १९०६ तक दो सिविलियन मेम्बर ही रह गये । १२ वर्ष पर्यन्त सम्राट्की सेवा करने बाद सिविलियन इस मेम्बरीका अधिकारी होता है, पर १९०६ के इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्टमें यह व्यवस्था हुई कि प्रेसिडेन्सी कौन्सिलोंमें अधिकसे अधिक चार मेम्बर रखे जा सकते हैं और आजकल इन कौन्सिलोंमें

७ सन् १८६३ तक भारतीय सेना तीन भागोंमें विभक्त थी, एक बंगाल आर्मी, दूसरी बाम्बे आर्मी और तीसरी मद्रास आर्मी और तीनोंके ब्रिगेड बसग कमांडर-इन-चीफ नियुक्त हुआ करते थे । पर इस वर्ष तीनों सेनाएं मिला दी गयीं और सबका एक ही कमांडर-इन-चीफ हुआ ।

दो दो सिविलियन और दो दो भारतवासी मेम्बर हैं। १९१२ से बङ्गाल प्रदेश प्रेसिडेन्सीमें परिणत हो गया है और उसे अन्य प्रेसिडेन्सियोंके समान ही अधिकार मिल गये हैं तथा उसमें भी शासन-सम्बन्धीय, यही व्यवस्था है। प्रेसिडेन्सियोंकी ये विशेषताएँ हैं,—

(१) इनका शासन कौन्सिल सहित गवर्नर करते हैं जिनका वार्षिक वेतन कमांडर इन चीफसे अधिक अर्थात् १,२०,०००) है। भारतसचिवके कहनेपर श्रीमान् सम्राट् कौन्सिलके मेम्बर नियुक्त करते हैं और गवर्नर-जेनरलकी तरह गवर्नर भी अनुभवी शासनको और उच्च श्रेणीके लोगोंसे चुने जाते तथा श्रीमान् सम्राट् द्वारा नियुक्त होते हैं। गवर्नरकी कौन्सिलका कार्य भी गवर्नर-जेनरलकी कौन्सिलके समान ही मेम्बरोंमें बँटा हुआ है, पर विभागोंका भेद उतना स्पष्ट नहीं है। बहुमतसे ही इस कौन्सिलमें भी कार्य होता है, पर गवर्नरको भी अपनी कौन्सिलका बहुमत अस्वीकार कर स्वेच्छानुसार कार्य करनेका अधिकार है। गवर्नरकी १४ तोपोंकी सलामी होती है।

(२) ऐसे विषय छोड़कर जिनसे आर्थिक प्रश्न उत्पन्न हो सकें, प्रेसिडेन्सी सरकारोंको सब विषयोंमें भारत-सचिवसे सीधे पत्रव्यवहार करनेका अधिकार है।

वे भारत सरकारकी आज्ञाके विरुद्ध भारतसचिवसे अपील कर सकती हैं, पर यह अपील भारत-सरकारकी मार्फत भेजी जाती या इसकी सूचना उसे दे दी जाती है।

(१३) कई पदोंके लिये कर्मचारी निर्वाचित करनेका उसे पूर्ण अधिकार है, यथा रेवेन्यू बोर्ड और प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओंके लिये मेम्बर मनोनीत करना तथा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटमें चीफ और सुपरिण्टेण्डिंग एंजिनियर तथा जङ्गलोंके कंजर्वेटर नियुक्त करना।

(१४) जिलोंमें मालगुजारीका बन्दोबस्त प्रेसिडेन्सी सरकार जैसा चाहे कर सकती है। पर अन्य प्रदेशोंमें भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है। जङ्गलोंके प्रबन्धमें भारत-सरकार प्रेसिडेन्सी सरकारसे उतनी कड़ाई नहीं करती।

(१५) गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिलके मेम्बरोंकी तरह गवर्नर और उनकी कौन्सिलके मेम्बरोंपर भी हाईकोर्टतकमें किसी तरहका मामला नहीं चल सकता और ये भी कैद या गिरफ्तार नहीं किये जा सकते।

परन्तु आर्थिक विषयोंमें प्रेसिडेन्सी सरकारें भी सर्वथा पराधीन नहीं और अन्य विषयोंमें भी पराधीनता कुछ कुछ बढ़ रही है। अधिकार विभाजक कमिशनको जो नोट बर्खास्त

सरकारने दिया था, उससे जान पड़ता है कि सत्र धान बाईस पसेरी हो रहे हैं। यम्यई सरकारने अपने नोटमें लिखा था, “जिस सरकारको यह निश्चय करनेका अधिकार नहीं है, कि मेरा कोई नौकर पब्लिक सर्वेण्टस् रूल तोड़े बिना किसी काममें रुपये लगा सकता है अथवा अपने अधिकारमें किसी देशी राज्यमें खनिज पदार्थ निकालनेका अधिकार दिया जा सकता है, जो १०) महीनेका चौकीदार नहीं रख सकती, लेडी डॉक्टरकी खर्च की हुई ८) की रकम मंजूर नहीं कर सकती, अपने पुलिस स्कूलमें कितने पुलिस अर्दली रखे जायं इसका अन्तिम निर्णय करनेसे वञ्चित की जाती है और सरकारी बगलेमें सीढ़ी बनानेके स्थान तथा उसके किरायेके विषयमें जिसकी बात अमान्य हो सकती है, वह भारत शासन पद्धतिपर वास्तवमें व्ययसाध्य और निरर्थक ग्रन्थि है। या तो उसे अधिक अधिकार मिलने चाहिये या उसे उठा देना और उसके बदले सीमाबद्ध अधिकारयुक्त एक अफसर रखना चाहिये। प्रेसिडेन्सीके गवर्नरकी दयङ्गी या दम्बूपनपर उसकी स्वतन्त्रता वा परतन्त्रता बहुत कुछ निर्भर है।

प्रेसिडेन्सी सरकारोंपर तो भारत सरकारका उतना ही प्रादेशिक सरकारोंकी प्राधान्य है, जितना पार्लमेंटके ऐक्युनि उसे दिया है, पर प्रादेशिक सरकारों पर अवस्था । उसकी प्रभुता पूर्ण है और वह घट बढ़ भी सकती है। इसका कारण यह है कि प्रेसिडेन्सियोंको

तो पार्लमेण्टने ऐकृ बनाकर अधिकार दिये हैं, पर प्रादेशिक सरकारोंके शासनाधीन प्रदेश गवर्नर-जेनरलके अधीन प्रदेशसे बने हैं और उनको गवर्नर-जेनरलने ही अधिकार दिये हैं । इसके सिवा १८५४ के ऐकृकी ४ थी धारामें स्पष्ट लिखा है कि "भारत सरकारको अधिकार होगा कि समय समयपर कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स और बोर्ड आफ कंट्रोलसे आज्ञा लेकर और उनकी स्वीकृतिसे बङ्गाल, आगरे या पश्चिमोत्तर प्रदेशके कौन्सिल सहित गवर्नर, गवर्नर या लेफ्टनेनंट गवर्नरके, जो अभी नियुक्त हों या पीछे नियुक्त किये जाय, अधिकार प्रसिद्ध वा सीमावद्ध करे ।" यद्यपि यह नियम बङ्गाल और युक्तप्रदेशके लिये ही था तथापि अब बंगालको छोड़ भारत सरकार सब प्रादेशिक सरकारोंके अधिकार सीमावद्ध कर सकती है । प्रेसिडेन्सी गवर्नरकी तरह प्रादेशिक गवर्नर चिलायतसे नहीं आते, बल्कि हिन्दुस्थानी सिविलियन होते हैं । इससे स्पष्ट है कि प्रेसिडेन्सियोंके गवर्नरकी अपेक्षा प्रादेशिक गवर्नर अधिक पराधीन हैं तथा वेतन भी उनका केवल १,००,०००) वार्षिक और सलामी १५ तोपोंकी ही है ।

प्रादेशिक शासकोंमें चीफ कमिशनरका दर्जा सबसे छोटा है । इसका कारण यह है कि जो चीफ कमिशनर । प्रदेश चीफ कमिशनरीमें परिणत किया जाता है, वह वास्तवमें भारत सरकारके शासनाधीन होता है और उसके शासनके

भारत सरकार ही आवश्यक आज्ञाएँ और निर्देश देती है और चीफ कमिशनर केवल उनके अनुसार कार्य करता है। चीफ कमिशनर भारत सरकारका प्रतिनिधि मात्र होता है। जो प्रदेश चीफ कमिशनरी में परिणत होता है, वह या तो पहले गवर्नर-जेनरलके शासनाधीन होता है या चीफ कमिशनरी बननेपर उसके अधीन हो जाता है। भारत सरकारको प्रदेशोंकी सीमा बदलनेका जो अधिकार है, उसका उपयोग वह गवर्नरके अधीन प्रदेशका कोई भाग लेकर चीफ कमिशनरी बनानेमें नहीं कर सकती। चीफ कमिशनरी बना देनेसे भी भारत सरकारके अधिकार उस प्रदेशपर ज्योंके त्यों बने रहते हैं। जो प्रदेश भारत सरकारके शासनोंधीन होता है, उसे चीफ कमिशनरी बनानेमें सरकारको पहले केवल मन्तव्य और फिर घोषणापत्र प्रकाशित करना पड़ता है। प्रादेशिक गवर्नरोंको यह अधिकार है कि रेवेन्यू बोर्डकी मेम्बरी छोड़कर अपने अधीन प्रदेशके पदोंपर जिनको चाहें प्रतिष्ठित करें, पर चीफ कमिशनर यह नहीं कर सकते। सबसे बड़े चीफ कमिशनरोंका वार्षिक वेतन ४८००० है और यद्यपि शासकोंमें ले गवर्नरके बाद इनका दर्जा है, तथापि अधिकारों और वेतन तथा तोपोंकी सलामीकी दृष्टिसे भारत सरकारकी कौन्सिलके मेम्बरका दर्जा इससे उंचा है। चीफ कमिशनरकी १३ तोपोंकी सलामी होती है। गवर्नरिया तो “लोकल गवर्न-

मेण्ट" और चीफ कमिशनरिया "लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन" कहाती हैं ।

कभी कभी रेगुलेशन और नानरेगुलेशन प्रदेशोंकी चर्चा भी सुन पड़ती है, इस लिये यहा उनके रेगुलेशन और नानरेगुलेशन प्रदेश । सम्यन्धमें कुछ लिख देना अनुचित न न होगा । १७७३ और १७८१ के ऐक्टोंसे बङ्गालके गवर्नर-जेनरल और कौन्सिलको अपने अधीन देशके सुशासनके लिये "रूल" और "रेगुलेशन" बनानेका अधिकार मिला था । बाद अग्रशिष्ट दोनों प्रेसिडेन्सियोंकी सरकारोंको भी मिल गया जो अपने रेगुलेशन जारी करने लगीं । १८३३ में प्रेसिडेन्सियोंका यह अधिकार छिा गया, क्योंकि बङ्गाल सरकार भारत सरकार बना दी गयी और उसे सारे हिन्दुस्थानके लिये कानून बनानेका अधिकार दिया गया । १८५३ में भारतीय व्यवस्थापिका सभा स्थापित होनेसे इस पद्धतिका अन्त हुआ । भारत सरकारके रेगुलेशनोंमें विशेषकर न्यायालय स्थापन और न्यायालयोंकी कार्य पद्धतिकी व्यवस्था है । मद्रास, बम्बई (सिन्धको छोड़कर) बङ्गाल और आगरा प्रदेश ही रेगुलेशन और अग्रशिष्ट सब प्रदेश नानरेगुलेशन प्रदेश थे । आगरा प्रदेश बङ्गाल प्रेसिडेन्सीके अन्तर्गत था और बङ्गाल प्रेसिडेन्सीको रेगुलेशन बनानेका अधिकार था तथा उसके बनावे रेगुलेशनोंका उक्त प्रदेशमें उपयोग होता था, इस लिये वह भी रेगुलेशन प्रदेश था ।

रेगुलेशन प्रदेश और नानरेगुलेशन प्रदेशमें सबसे बड़ा भन्तर यह है कि नानरेगुलेशन प्रदेश प्रारम्भमें चीफ कमिशनरोंके शासनाधीन थे अथवा अब भी हैं। उनके जिला अफसर आदि कर्मचारी सिविलियनोंके सिवा सैनिक वा अन्य कर्मचारी भी होते थे। उनके शासनके नियम भी कड़े थे और गवर्नर जनरल जैसे चाहते थे, वैसे नियम भी बना देते थे। नान रेगुलेशन प्रदेशोंके जिला अफसर डिप्टी कमिशनर, ऐसिस्टेंट कमिशनर और एक्सट्रा ऐसिस्टेंट कमिशनर कहाते हैं। रेगुलेशन प्रदेशोंमें इन्हें कलेक्टर, ऐसिस्टेंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। आसाम, यर्मा और पञ्जाबमें शासन कार्यमें अब भी कई सैनिक कर्मचारी नियुक्त हैं और इनके कलेक्टर डिप्टी कमिशनर अब भी कहाते हैं। दोनों प्रकारके प्रदेशोंमें दूसरा बड़ा भेद यह है कि रेगुलेशन प्रदेशोंमें प्रधान न्यायालय चार्टर्ड वा अन्य प्रकारका हाईकोर्ट है, पर नानरेगुलेशनमें जुडीशल कमिशनरी है। १८६१ के इण्डियन कौन्सिल ऐक्टसे वे कानून भी ठीक ठहराये गये, जो भारत सरकार या गवर्नर-जनरलने नानरेगुलेशन प्रदेशोंके लिये समय समयपर बनाये थे।

कुछ विभागोंको छोड़कर आन्तरिक शासनका कार्य प्रादेशिक सरकारोंके प्रादेशिक सरकारको दे दिया गया है। अब १९१६ के ऐक्टके अनुसार प्रादेशिक सरकारों और भारत सरकारके अधिकारोंका विभाग इतना स्पष्ट हो गया कि यह सहज ही

बताया जा सकता है कि भारत सरकारके कार्यका कहां अन्त होता है और कहांसे प्रादेशिक सरकारोंका कार्य प्रारम्भ होता है । पर साधारण व्यवस्था यह है कि परराज्य, देशरक्षा (सेना) कर, करेन्सी, ऋण, आगत कर, अफीम, डाक और तार, रेलवे, हिसाब किताब और उसकी जाचके काम पब्लिक सर्विस समस्त भारतके दीधानी और फौजदारी कानून और दो प्रदेशों के सम्बन्धके कानून तथा वे सब काम जिनका उल्लेख भारत सरकारके विभागोंके सम्बन्धमें किया गया है भारत सरकार करती है और आन्तरिक शासन, पुलिस, दीधानी और 'फौजदारी मामलोंका विचार, जेल, मालगुजारी बाधना और वसूल करना शिक्षा, डाक्टरी और स्वास्थ्यप्रबन्ध, आयपाशी, इमारतों और सड़कों और जङ्गलोंका प्रबन्ध तथा म्युनिसिपल और ग्राम-बोर्डोंका नियन्त्रण प्रादेशिक सरकारें करती हैं । भारत सरकार नीति निर्धारित करती है और रिपोर्टों और स्थितिसम्बन्धी अंकोंसे निश्चय करती है कि कहातक उसके अनुसार कार्य हुआ है । नीति वा विशेष महत्वके प्रश्नोंपर प्रादेशिक सरकारें भारत सरकारसे आज्ञा मंगा लेती हैं । कई विभागोंके निरीक्षण और परामर्शके लिये भारत सरकारने कई इन्स्पेक्टर जनरल और डाइरेक्टर-जनरल नियुक्त कर रखे हैं । महत्वके किसी नये पदकी सृष्टि और बहुसंख्यक निम्न कर्मचागी बढानेके लिये भारत सरकारकी स्वीकृति लेनी पडती है । बड़े प्रदेशोंमें सरकारी

काम भिन्न भिन्न विभागोंमें बंटा रहता है, यथा रेवेन्यू (राजस्व), जुडीशल (विचार सम्बन्धी), और पब्लिस, लोकल और म्यूनिसिपल, फाइनानशल, (अर्थ-सम्बन्धी) पब्लिक वर्क्स और पब्लिकेशन (शिक्षा) । पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेण्टके चीफ एग्जिनियर प्रादेशिक सरकारके सेक्रेटरी या ज्वायंट सेक्रेटरी भी होते हैं। अर्थ विभागके मुखिया सिविलियन होते हैं। प्रत्येक प्रदेशमें तीन (पञ्जाबमें दो ही) सिविलियन सेक्रेटरी होते हैं और प्रत्येकके अधीन सुविधानुसार दो दो तीन तीन विभाग कर दिये जाते हैं। सोनियर (बड़ा) सिविलियन सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी कहाता है और अन्य सेक्रेटरियोंके नाम उनके अधीन प्रधान विभागके नामानुसार होते हैं। इनके सहायतार्थ अप्पंडर और पेसिस्टेंट सेक्रेटरी भी होते हैं तथा प्रत्येक विभागका आफिस एक मजिस्ट्राटके अधीन रहता है, जिसके नीचे कई सुपरिन्टेंडेंट और क्लर्क काम करने हैं। प्रादेशिक सेक्रेटेरियट में भी इम्पीरियल सेक्रेटेरियटके समान ही काम होता है।



पंचम अध्याय



‘जिलेकी शासन-व्यवस्था ।

अतः जिन शासकोंका वर्णन किया गया है, जनसाधारण उनके विषयमें बहुत ही कम, अथवा कलेक्टरका महत्व । कुछ नहीं, जानते । बहुतोंने तो भागत सचिव वा सेक्रेटरी आथ स्टेट फार

इण्डिया अथवा गवर्नर-जनरल इन-कौन्सिल सुना ही न होगा, अर्थ जानना तो दूरकी बात है । बड़े लाट और छोटे लाटके नाम कितने ही लोगोंने सुने होंगे, पर उनके दर्शनोंका सीमाग्य बहुत कम लोगोंको प्राप्त हुआ होगा और उनके अधिकार तो बिरले हो किन्नीकी मालूम होंगे, क्योंकि उनसे लोगोंका कोई घास्ता नहीं है, इनका काम “साहेब कलक्टरसे” हो पड़ता है और इस कारण ये जिला कलेक्टरको ही अङ्गरेज सरकार समझते हैं । इस लिये यहा अङ्गरेज सरकारके इस महत्वपूर्ण प्रतिनिधिका कुछ परिचय दिया जायगा ।

ब्रिटिश भारतमें कुल २६७ जिले हैं और प्रत्येक जिला कलेक्टरके (नारायणदेशन प्रदेशोंमें डिप्टी कमिशनरके) अधीन है । एन

जिलेमें औसत ४,४३ वर्ग मील जमीन औसत ६,३१,००० आवासी है । पर मद्रास और बम्बेके जिले

अन्य प्रदेशोंके जिलोंसे बड़े और युक्तप्रदेशके छोटे हैं। मद्रास प्रदेशके विजयापट्टम जिलेमें जमीन १७,२३३ वर्ग मील और जनसंख्या २० लाखसे अधिक है और चर्माके अपर चिन्दविन जिलेमें जमीन तो २० हजार वर्ग मीलसे भी अधिक है, पर आबादी १,७०,००० ही है। इसके विपरीत बङ्गालके मैमनसिंह जिलेकी आबादी तो ४८ लाख है, पर उसमें जमीन ६,३४७ वर्ग मील ही है। जिलेमें सुप्रबन्ध रखना कलेक्टरका काम है। वही जिलेका हाकिम है। कलेक्टर अपने दो पदोंके कारण दो नामोंसे पुकारा जाता है, एक कलेक्टर, दूसरा मैजिस्ट्रेट। मालगुजारी वसूल करनेके कारण कलेक्टर और फौजदारी मामले फैसल करनेके कारण मैजिस्ट्रेट कहाता है। कलेक्टर को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है जो एक मनुष्यकी शक्तिसे बाहर है।

कलेक्टरकी हैसियतसे वह मालगुजारी वसूल करनेका कलेक्टर और जिम्मेदार है। गवर्नमेंट और किसानों मैजिस्ट्रेट का सम्यन्ध ठीक रखना उसीका काम है। जो लोग सीधे सरकारको माल

गुजारी देते हैं, उनकी जमीनकी रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, जमीन छुड़ाना या बटवारा करना उसीका काम है। भारतके जिन भागोंमें छोटे छोटे किसान ही जमीन्दार हैं, उनके सम्यन्ध के उक्त कार्य भी उसे ही करने पड़ते हैं। कई प्रदेशोंमें वह जमीन्दार और किसानोंके झगड़े निपटाता है और कोर्टे आग

वाईसके अधीन जमीन्दारियोंके प्रबन्धसे उसका सम्बन्ध है। किसानोंको तकावी देना और कृषि अथवा अन्य प्रकारकी दशा दिखानेवाले अंकोंका विधिपूर्वक संग्रह करना कलेक्टरका ही काम है। अपने जिलेकी दशापर उसे विशेष ध्यान रखना पड़ता है और अकाल या किसानोंके महत्कष्टोंके समय कृषिनिवारणके उपाय करना और अकाली काम खोलना उसीके काम हैं। प्रजाके आर्थिक या अन्य प्रकारके कामोंका जङ्गल विभागसे जितना सम्बन्ध है, अपने जिलेमें जङ्गल विभागके उतने कार्यका नियन्त्रण कलेक्टर ही करता है। कहीं कहीं म्यूनिसिपलटियोंके कार्यका नियन्त्रण और उन्हें मार्ग धताना भी कलेक्टरका कर्त्तव्य है और वहाँ यह प्राय म्यूनिसिपलटीका चेयरमैन या सभापति भी होता है। वैसे स्थानोंमें वह साधारणतः जिला बोर्डका प्रेसिडेंट या अध्यक्ष भी होता है। यह बोर्ड अपने अधीन ग्राम बोर्डों की सहायतासे गावोंमें सड़कोंकी मरम्मत कराता, स्कूल और शफाखाने चलाता तथा चेचकके टीके और स्वास्थ्योन्नतिका प्रबन्ध करता है। अपने जिलेकी मुख्य घटनाओंके सम्बन्धमें बड़े अधिकारियोंको सूचना देना कलेक्टरका काम है और जिलेके सम्बन्धकी प्राय सब स्कीमोंपर उसकी सम्मति मागी जाती है। जिला मैजिस्ट्रेटकी हस्तियतसे कलेक्टर प्रथम

७ बम्बई और मध्य प्रदेशमें द्विजनोंके कमिशनर "कोर्ट ऑव वार्ड्स" है। बर्मामें वहाँ "कोर्ट ऑव वार्ड्स" नहीं है, पर अन्य बड़े प्रदेशोंमें रेवेन्यू बोर्ड या फाइनांसियल कमिशनर ही कोर्ट है।

ध्रेणीका मैजिस्ट्रेट है। उसे अपराधीको २ वर्षकी जेल और १,००० जुमानेकी सजा देनेका अधिकार है, यद्यपि साधारणतः वह मुकद्दमे नहीं फैसल करता और केवल अपने अधीन मैजिस्ट्रेटोंके कार्यका निरीक्षण करता है। उसे अपने अधीन मैजिस्ट्रेटोंके फैसल किये हुए मुकद्दमोंकी अपील सुननेका भी अधिकार है। जिलेकी शान्तिका उत्तरदायित्व उसपर है और पुलिस उसके अधीन है।

हर जिला कई सबडिवीजनोंमें घटा होता है, जो सिविल सब-डिवीजन और सर्चिंसके जूनियर-अफसर या प्राविण-शल सर्चिंसके अफसर, यथा- डिप्टी कलेक्टरों या एसस्टा-प्रेसिस्टेंट कमि-

शनरोंके अधीन रहते हैं। ये सबडिविजनल अफसर कहलाते हैं। ये भी मैजिस्ट्रेटकी तरह फौजदारी और माली काम करते हैं। यद्वाल और बिहार प्रदेशोंको छोड़ अन्य प्रदेशोंके जिले ताल्लुकों या तहसीलोंमें भी बटे हैं। आसाममें इन्हें "सर्कल" और यमांमें "टाउनशिप" कहते हैं। आसाममें ये सब-डिप्टी कलेक्टरों, यमांमें माइडको, बर्मामें मामलतदारों, युक्तप्रदेशमें तहसीलदारों और सिन्धमें मुख्तियारकारोंके अधीन हैं। मद्रास-प्रदेशका हर जिला सबडिवीजनोंमें घटा है और वहा सब-डिविजनल अफसर बराबर रहते हैं। माली मामलोंमें ये कलेक्टरोंके अधिकारोंका उपयोग करते हैं, कलेक्टर केवल इनके कार्यका निरीक्षण करता और इनके निर्णयोंके

विवाद लोगोंकी अपीलें सुनता है । फौजदारी मामलोंमें भी ये मैजिस्ट्रेटकी हस्तियनने काम करते हैं और दूसरे और तोसरे इज्जके मैजिस्ट्रेटोंके फैसल किये मामलोंकी अपीलें सुनते हैं । सारास, मय डिवीजन छोटामा जिला बन गया है । यद्वाल्में भी यही व्यवस्था है और मय डिवीजल अफसर अपने सय डिवीजनमें रहते हैं । सदर मय डिवीजल कलेक्टरके अधीन होता है । यथा तहसीलें या ताल्लुके नहीं हैं । मद्रास और बम्बईमें ताल्लुके और युक्तप्रदेश और पञ्जाबमें तहसीलें भी हैं । तहसीलदारका प्रजासे यडा सरोकार रहता है और प्रजा तथा कलेक्टर और मय डिवीजनल अफसर इससे सब प्रकारके समाचार पानेकी भाशा करते हैं । तहसीलदार निर्फ माली या फौजदारी 'हार्किम' हो नहीं है ; उसे ग्राम योडों और म्युनिनिपलटियोंका भी काम देखना पडता है । जहां सब डिवीजनल अफसर होता है, तहसीलदार, मय डिवीजनल अफसरके मातहत होता है । इसके मातहत नायब तहसीलदार या पेशकार कानूनगो, रेवेन्यू इन्स्पेक्टर आदि हैं । गांवके अफसरोंमें सबसे महत्वका मनुष्य मुखिया या पञ्च हैं जो मालगुजारी, घसूल करता है और मद्रास तथा बर्मामें जितने छोटे मैजिस्ट्रेट या दीवानी जजके अधिकार दिये गये हैं । दूसरा पटवारी है, जो गांवका हिसाब किताब और रजिष्टर रकता है । चौकीदार या गांवका कान्सटेबल सबसे छोटा नौकर है । पटवारीको बम्बईकी तरफ कारखुन कहते हैं ।

मद्रासको छोड़ सब बड़े प्रदेश द्विवीजनमें बटे हैं। प्रत्येक द्विवीजनमें ४ से ६ जिलेतक होते हैं। कमिशनर और द्विवीजनका अफसर कमिशनर कहलाता रेवेन्यू बोर्ड है। यह माली मामलोंकी अपीलें भी सुनता है। मालगुजारीके बन्दोबस्तमें इसका काम सलाह देनाभर है, पर मालगुजारीकी वसूली रोकनेका इसे अधिकार है। कुछ प्रदेशोंमें ऊँचे दर्जेके मालगुजारी अफसर भी यह नियुक्त कर सकता है और प्रादेशिक नियमों और शर्तों पर किसानों और जमीन्दारोंको तकावी दे सकता और आवश्यक होनेपर मालगुजारी छोड़ सकता है तथा कोर्ट आव चार्जस्के अधीन भूसम्पत्तियोंके प्रबन्धमें इसे बहुत काम करना पड़ता है। युक्तप्रदेश, बिहार, बङ्गाल, और मद्रासमें रेवेन्यू बोर्ड था तथा पंजाब, बर्मा, और मध्यप्रदेशमें इसके बदले फाइनानशल कमिशनर था। यह प्रादेशिक सरकारके अधीन होता है और इसका काम माली मामलोंमें कलेक्ट्रों और कमिशनरोंके कार्योंका नियन्त्रण करना है। माली मामलोंमें कमिशनरके निर्णयके विरुद्ध अपील सुनता है। अब कहीं बोर्ड नहीं है और मद्रासमें कमिशनर भी नहीं हैं। मद्रासके रेवेन्यू बोर्डमें ४ मेम्बर थे, जिनमें दो तो भूकरसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले मामलोंका विचार करते, तीसरा जमीनके बन्दोबस्त, खेती और लैंड रेकार्ड्स और चौथा नमक, आबकारी, कस्टम्स, इनकम टैक्स और स्टाम्पोंके कार्यसे

रखता था । युक्त प्रदेशमें दो और बंगाल और बिहारके बोर्डोंमें एक ही एक मेम्बर था । अब शासनकारिणों समाका एक मेम्बर रेवेन्यू बोर्डका काम करता है । पंजाबमें दो फाइनेंसल कमिशनर है ।

पहले कमिशनरों और रेवेन्यू बोर्डकी अधीनतामें कलेक्टर और उसके अधीन कर्मचारी अपने जिलेका कार्यविभाग । जिलोंका शासनसम्बन्धीय सब कार्य किया करते थे । परन्तु गत ५० वर्षोंमें धीरे धीरे अनेक स्वतन्त्र विभाग बन गये हैं, जिनमें जिलेका काम भी बंट गया है । इनमें पब्लिक वर्क्स, शिक्षा, पुलिस, जङ्गल, डाक्टरी, स्वास्थ्य और जेल विभाग मुख्य हैं । मालगुजारीके सिवा सरकारी आमदनीकी और महोंका काम भी कमिशनर देखता है । शिक्षा, पुलिस और पब्लिक वर्क्स विभागोंसे उसका विशेष सम्बन्ध नहीं है, पर जिला बोर्डों और म्युनिसिपलिटियोंसे उसका बहुत कुछ सम्बन्ध अब भी है । प्रत्येक प्रदेशमें ये विभाग अलग अलग अफसरोंके अधीन हैं, जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटके चीफ एंजिनियर, शिक्षा विभागके डायरेक्टर, पुलिस विभागके इन्स्पेक्टर-जेनरल और जङ्गल विभागके कजरवेटर या चीफ कजरवेटर, सिविल अस्पतालोंके इन्स्पेक्टर-जेनरल (मैट्रस और घम्पईमें सर्जन जेनरल कहते हैं), स्वास्थ्य विभागके सैनिटरी कमिशनर और जेलोंके इन्स्पेक्टर जेनरल । इनके सिवा एक्साइज कमि-

मद्रासको छोड़ सब बड़े प्रदेश द्विवीजनमें बटे हैं । प्रत्येक

कमिशनर और द्विवीजनमें ४ से ६ जिलेतक होते हैं ।
द्विवीजनका अफसर कमिशनर कहा जाता है । यह माली मामलोंकी अपीलें भी

सुनता है । मालगुजारीके बन्दोबस्तमें इसका काम सलाह देनाभर है, पर मालगुजारीकी वसूली रोकनेका इसे अधिकार है । कुछ प्रदेशोंमें ऊँचे दर्जेके मालगुजारी अफसर भी यह नियुक्त कर सकता है और प्रादेशिक नियमों और शर्तों पर किसानों और जमीन्दारोंको तकावी दे सकता और आवश्यक होनेपर मालगुजारी छोड़ सकता है तथा कोर्ट आब चार्जस्के अधीन भूसम्पत्तियोंके प्रबन्धमें इसे बहुत काम करना पड़ता है । युक्तप्रदेश, बिहार, पंजाब, और मद्रासमें रेवेन्यू बोर्ड था तथा पंजाब, धर्मा, और मध्यप्रदेशमें इसके बदले फाइनानशल कमिशनर था । यह प्रादेशिक सरकारके अधीन होता है और इसका काम माली मामलोंमें कलेक्टरों और कमिशनरोंके कार्योंका नियन्त्रण करना है । माली मामलोंमें कमिशनरके निर्णयके विरुद्ध अपील सुनता है । अब कहीं बोर्ड नहीं है और मद्रासमें कमिशनर भी नहीं हैं । मद्रासके रेवेन्यू बोर्डमें ४ मेम्बर थे, जिनमें दो तो भूकरसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले मामलोंका विचार करते, तीसरा जमीनके बन्दोबस्त, खेती और लैंड रेकार्ड्स और चौथा नमक, आबकारी, फस्ट्रम्स, इनकम टैक्स और स्टाम्पोंके कार्यसे सम्बन्ध

लिखे पडा था, कि कम्पनीके उच्च कर्मचारियोंको इस माशयका प्रतिज्ञापत्र लिखना पडना था कि "मैं व्यापार न करूंगा और नजर न लूंगा" आदि । प्रतिज्ञापत्र अब भी लिखना पडता है, पर अब यह सर्विस इण्डियन सिविल सर्विस कहाती है । पहले कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स इस सर्विसमें लोगोंको नियुक्त करते थे । १८३३ के चार्टर ऐक्टने भारत वागियोंको इसमें प्रवेश करनेका अधिकार दिया । इस ऐक्टमें कहा गया कि महारानी विक्टोरियाका प्रत्येक प्रजाजन, चाहे वह किसी धर्म वा जातिका क्यों न हो, अपने योग्यतानुसार उच्चानि उच्च पद पा सकेगा । पर २० वर्षतक किमी भारतवासीको इस सर्विसमें स्थान न मिला । १८५३ तक इस सर्विसमें प्रवेश करनेके लिये कोई नियम न था, अधिकारी जिसे चाहते थे, इसमें मर्ती करने थे । पर इस वर्षसे प्रतियोगी परीक्षा होने लगी और महारानीकी प्रजामात्रको परीक्षा देनेका अधिकार मिला । तयसे १९२० तक लण्डनमें सिविल सर्विसकी परीक्षा होती था और जो प्रतियोगितामें समर्थ होता था, उसे इसमें स्थान मिलता था । १८६१ के इण्डिया सिविल सर्विस ऐक्टसे रेगुलेशन प्रदेशोंके प्राय सब उच्च पद सिविलियनोंको मिलने लगे और बाहरी लोगोंको नियुक्त करनेका अधिकार भी दिया गया । सरकारी नौकरियोंका पडा भारी इतिहास है और उससे भारतीय राजनीतिका घनिष्ठ सम्बन्ध है, इस लिये उसका वर्णन स्वतन्त्र अध्याय बिना सम्भव है ।

शतर, पेट्रिकलचर और लैंड रेकार्ड्सके डाइरेक्टर और कुछ प्रदेशोंमें मालगुजारीके चन्दोस्तके कमिशनर हैं । जिलोंमें इन विभागोंके अधीन जो आफिस हैं, उनसे कलेक्टरका सम्यन्ध बहुत कम रहता है । छोटे जेलों, स्वास्थ्य, डाक्टरों, और प्राथमिक शिक्षासे उसका घनिष्ठ सम्यन्ध है । जिलेमें कलेक्टरके सिवा दो अफसर और होते हैं, एक पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट और दूसरा सिविल सर्जन । पुलिसका मुख्या जिलेका पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट होता है । जिलेमें तो यह जिला मैजिस्ट्रेटके मातहत है, पर पुलिसके संघटन आदिके विषयमें इसका अफसरइन्स्पेक्टर-जेनरल है । सिविल सर्जनका दूसरा नाम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर है । जिला जेल इसके चार्जमें है और यह अस्पतालों और शफाखानोंकी देखभाल करना है तथा जिलेका स्वास्थ्य ठीक रखना इसका काम है ।

पिछले अध्यायोंमें निम्निल सर्विस और सिविलियनोंका सिविल सविन और सिविलियन । उल्लेख हुआ है, इस लिये यहां उनके विषयमें कुछ लिख देना उचित जान पड़ता है । जिसे आज “इण्डियन निम्निल सर्विस” कहते हैं, पंद्रह पछले “कवेनेंटेड सिविल सर्विस” कहाती थी । कौन्सिलकी मेम्बरीसे नीचे देश शासक कर्मचारियोंके जो पद होते थे, वे “कवेनेंटेड” सिविल सर्विसके लोगोंको मिलते थे । “कवेनेंटेड” इसका नाम इस

पष्ठ अध्याय ।

— ❦ —

न्यायालयोंके कार्य और अधिकार ।

पिछले अध्यायोंमें शासनसंस्थाओंका वर्णन किया गया है, परन्तु देशके सुशासनके लिये वे ही मेयर्स कोर्ट । पर्याप्त नहीं हैं । ऐसी संस्थाओंका भी प्रयोजन है, जो परस्परके झगड़े फसादका निपटारा किया करें और दुष्टोंको दण्ड देकर उनसे शिष्टोंकी रक्षा किया करें । इन संस्थाओंको न्यायालय, निचारालय या अदालत कहते हैं । जिस प्रकार संस्थाओंका इतिहास है, उसी प्रकार इनका भी इतिहास है, क्योंकि जब पहले पहल अङ्गरेज इस देशमें आये थे, तब उन्हें यहाँकी सन बातें नहीं मालूम थीं और वे अपने अनुभव और बुद्धिके अनुसार यहाँ शासन और विचार कार्योंकी व्यवस्था करते थे । सन् १६६१ में भारतमें न्यायालय स्थापन करनेका सुत्रपात हुआ था । महाराज दूसरे चार्ल्सने ईस्ट इण्डिया कम्पनीको जो फार्मान दिया था, उसमें कम्पनीके अधीन स्थानोंके गवर्नरों और कौन्सिलोंको अपने कर्मचारियों और प्रजाके झगड़े निपटानेका अधिकार दे दिया था । कौन्सिल

यहा केवल इतना ही यत्ना देना बस होगा कि सिविल सर्विस तीन भागोंमें बंटी हुई है और इण्डियन सिविल सर्विसका मेम्बर गवर्नर तक हो सकता है। सिविल सर्विसके तीन विभाग ये हैं ;—इण्डियन सिविल सर्विस, प्राविनशल सिविल सर्विस और सवार्डिनेट सिविल सर्विस। इण्डियन सिविल सर्विसके लिये लण्डनमें प्रतियोगी परीक्षा होती थी और अब १९२१ से हिन्दुस्थानमें भी होने लगी है। परीक्षाके सिवा इस सर्विसमें भर्ती होनेके लिये लोग मनोनीत किये जाते और प्रादेशिक सर्विससे उन्नत होकर भी इसमें भेजे जाते हैं। वकील बैरिस्टर भी नियुक्त किये जा सकते हैं। अन्तिम दोनों सर्विसोंमें प्रदेश विशेषके लोग ही नियुक्त किये जाते हैं। प्राविनशल सर्विसमें भर्ती होनेवालोंको कभी परीक्षा देनी पड़ती है, कभी वे मनोनीत होते और कभी सवार्डिनेट सर्विससे उसमें बदल दिये जाते हैं।



गये और उन्हें सब दीवानी मामलोंका विचार करनेका अधिकार मिला । पर प्लासोकी लड़ाईके कुछ पहले और पोछे बङ्गालकी ऐसी वशा थी कि कम्पनीके राज्यमें विचारकी व्यवस्था नहींके बराबर थी । जब कम्पनीने दीवानी ली, तब भी शेरानों और फौजदारी मामले नयायके दरबारसे ही फैसल होते थे । वारेन हेस्टिंग्सके समय कम्पनीने दीवानी और फौजदारी मामले फैसल करना शुरू कर दिया और इस तरह दीवानी और फौजदारी अदालतें बनीं ।

रेगुलेटिंग ऐक्टसे जैसे वर्त्तमान भारत सरकारकी नींव पड़ी थी, वैसे ही वर्त्तमान हार्दकोर्टके सुप्रीम कोर्ट । पूर्व न्यायालय सुप्रीम कोर्टकी स्थापना हुई थी । उस ऐक्टमें इङ्ग्लैण्डके महाराजको अधिकार दिया गया कि अपने फर्मान या लेटर्स पेटेंटसे कोर्ट त्रिलियममें एक चीफ जस्टिस और तीन जजोंका सुप्रीम कोर्ट स्थापित करें । इस प्रकारके स्वतन्त्र न्यायालयकी व्यवस्था इस लिये हुई थी, जिसमें यह गवर्नर-जेनरल और कौन्सिलसे न द्ये । सुप्रीम कोर्टके जज घूस ऊस न लें इसके लिये उक्त रेगुलेटिंग ऐक्टमें यह व्यवस्था की गयी कि यदि उनपर ऐसा अभियोग लगाया जाय, तो गवर्नर-जेनरल और कौन्सिल इस पारकी गवाहियां लेकर इङ्ग्लैण्डमें कोर्ट आव किज वेंचको भेज दें और वह उसका विचार करेगा । पर दोनो स्वतन्त्र संस्थाओंमें बराबर घटपट हुआ करती थी । सुप्रीम कोर्ट प्राय

सहित गवर्नर विलायती कानूनसे दीवानी और फौजदारी सब तरहके मामले मुकद्दमें फैसल करते थे । पर १७२६ में लेटर्स पेटेण्टसे * इङ्ग्लैंडके महाराजने बम्बई, मद्रास और फोर्ट विलियममें “मेयर्स कोर्ट” स्थापित किये । इनमें एक मेयर और ६ * ऐलडरमैन थे, जिनमें ७ ऐलडरमैनों और मेयरका ब्रिटिश प्रजा होना आवश्यक था । ये “कोर्ट्स आफ रेकार्ड्स” बनाये

लेटर्स पेटेण्ट वे पत्र हैं, जो इङ्ग्लैंडके महाराज उन लोगोंके नाम जारी करते हैं जिनका उनसे सम्बन्ध होता है और जिनमें किसीको कोई पद अधिकार, स्वत्य आदि देने या कोई मस्था स्थापित करनेकी बातें लिखी रहती हैं । इन पत्रोंपर मुहर नहीं लगायी जाती और ये खुले छोड़ दिये जाते हैं, जिसमें राज्यकी सब प्रजा इन्हें पढ़कर इनसे बन्धी रहे । लेटर्स पेटेण्ट जारी करनेके लिये पहले वारण्ट या आज्ञापत्र लिखा जाता है और उसपर लार्ड चान्सेलरके हस्ताक्षर होते हैं । फिर यह महाराजके कानूनी अफसरोंके पास जाता है और ये इसपर हस्ताक्षर करते हैं । अन्तको इसपर श्रीमान् महाराजके हस्ताक्षर होते हैं । इसके बाद फाउण्डाफिसमें यह भेज दिया जाता है और वहासे लेटर्स पेपेट जारी होकर यह वाकिल दफ्तर हो जाता है ।

लेटर्स पेपेट उस अफसरको सहते हैं जो शासन और विचार सम्बन्धी कार्य करता है । आजकल इङ्ग्लैंडमें म्यूनिसिपैलिटीका प्रधान “मेयर” कहा जाता है । ऐलडरमैनको इङ्ग्लैंडमें ह्वावरपमे लिये म्यूनिसिपल कॉन्सिलर चुनते हैं । इसे विचारके भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं । वास्तवमें मेयर और ऐलडरमैनको म्यूनिसिपल प्रबन्धका अधिकार दिया गया था, पर वहां इन्हें विचारका कार्य भी सौंप दिया गया ।

हाईकोर्ट है। १८६१ में पार्लमेण्टने कानून बनाकर इंग्लैंडकी महारानीको अधिकार दे दिया था कि अपने लेटर्स पेटेण्टसे कलकत्ते, बम्बई, मद्रास और आगरा प्रेशोंमें हाईकोर्ट स्थापित करें। इन हाईकोर्टोंके लिये जज नियुक्त करनेका अधिकार भी उन्हें ही रहा और हाईकोर्टके जजोंका कार्यकाल भी महारानीकी प्रसन्नतापर निर्भर रहा। पर नियम हुआ कि कमसे कम तिहाई जज बैरिस्टर या स्कॉटलैंडके पेडवोक्टेडोंकी फैकल्टीके मेम्बर और कमसे कम तिहाई सिविलियन होंगे, अवशिष्ट स्थान भारतीय वकीलोंको दिये जायेंगे। इन हाईकोर्टोंमें ही सुप्रीम कोर्ट, सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें विलीन हो गयीं। दीवानी, फौजदारी, वसीयत या बेवसीयतकी जायदादों, विधालियों, ब्याह पारिज करने या तलाकके मामले हाईकोर्टसे फैसल होते हैं। युद्ध छिड़नेपर शत्रुके व्यापारी जहाजोंके चारोंमें भी हाईकोर्टको अपना मत प्रकाश करना पड़ता है और उस समय उसका प्रेसिडेंटकोर्ट होता है। हाईकोर्टके प्रधान दो विभाग हैं एक ओरिजिनल और दूसरा अपीलेट। इनमें प्रत्येकके दो भेद हैं एक आर्डिनरी वा साधारण और दूसरा एक्सट्रा-आर्डिनरी वा असाधारण। ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन प्रेसिडेन्सी नगरकी सीमाके बाहर नहीं है। अर्थात् प्रेसिडेन्सी नगरके मय दीवानी मामले, जो स्माल काज कोर्ट या छोटी अदालतमें नहीं जा सकते, हाईकोर्टमें दायर होते हैं और जिन

गवर्नर-जेनरल इन-कौन्सिलके विरुद्ध निर्णय किया करता था। इस लिये १७८१ में एक कानून बनाया गया, जिससे सुप्रीम कोर्टका कार्यक्षेत्र संकुचित किया गया। पहले उसे बङ्गाल विहार और उड़ीसेमें होनेवाले सब तरहके मामलों मुकद्दमोंका विचार करनेका अधिकार था, पर १७८१ के ऐक्टसे कलकत्ता शहरके दीवानी मामलोंके विचार करनेका ही अधिकार रह गया। पहले अङ्गरेजी कानूनसे मुकद्दमे फैसल होते थे, पर इस समयसे यह नियम हुआ कि मुसलमानोंके मुकद्दमे मुसलमानी शरह और जेंदुओंके (हिन्दुओंके) मुकद्दमे जेंदू (हिन्दू) शास्त्रानुसार फैसल हों और जहा चाही प्रतिवादी भिन्न भिन्न धर्मावलम्बी हों वहा प्रतिवादीके धर्मशास्त्रानुसार निर्णय किया जाय। कलकत्तेमें तो यह परिवर्तन हुआ, पर बम्बई और मद्रासमें १७६७ तक मेयर्स कोर्ट ही रहे और इस वर्ष इनके बदले रेकार्डर्स कोर्ट स्थापित हुए और अन्तमें बङ्गालके ढङ्गपर १८०० में मद्रासमें और १८२३ में बम्बईमें सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुए। १८०१ में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतोंका पुनः स्रष्टन हुआ। गवर्नर जेनरल और कौन्सिलके बदले इनमें कवेनैटेड सर्विसके ३ या अधिक जज बैठने लगे। अन्तको १८६२ में ये अदालतें हाईकोर्टमें मिल गयीं।

भारत सरकारकी तरह भारतभरपर किसी न्यायालयकी

हाईकोर्ट ।

प्रभुता नहीं है, यद्यपि इस समय कलकत्तेका हाईकोर्ट सबसे बड़ा है और बङ्गाल और आन्ध्र प्रदेशोंके

न्यायालयोंपर उसका प्राधान्य है। भारतमें सर्वोच्च न्यायालय

मामलोंमें घे गिरपतार किये या जेल भेजे नहीं जा सकते ।
 पार्लमेंटका कोई ऐक्ट या मामूली कानून न माननेके कारण
 उनपर फौजदारी मामला भी नहीं चल सकता । १८६१ के
 ऐक्टसे प्रत्येक हाईकोर्टमें एक चीफ जस्टिस और १५ जज
 नियुक्त हो सकने थे । परन्तु कलकत्ता हाईकोर्टका काम
 बेतरह बढ़ जानेके कारण १६११में पार्लमेंटने इण्डियन हाई-
 कोर्ट्स एक्ट पास कर दिया, जिससे जजोंकी संख्या २० तक
 हो सकती है और जहां हाईकोर्ट न हो, वहां स्थापित किया
 जा सकता है । इलाहाबाद प्रेसिडेंसी नगर नहीं है, इस
 लिये वहांके हाईकोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यूरोपियन
 ब्रिटिश प्रजाजनोका दौरेमें विचार करनेतक ही समाप्त हो
 जाता है ।

जिन चार हाईकोर्टों का ऊपर वर्णन हुआ है, महाराणीके
 चीफ कोर्ट और लेटर्स पेटेंटसे स्थापित होनेके कारण वे
 चार्टर्ड हाईकोर्ट कहते हैं । वे राज-
 पुर्बीशल कमिशनर । कीय न्यायालय हैं, परन्तु अन्य प्रदेशोंमें
 हाईकोर्ट चार्टर्ड नहीं हैं । कहीं ग्रीक कोर्ट और कहीं जुजरीशल
 कमिशनर्स कोर्ट हैं । १८६६ में पटनाके लाहोर नगरमें और
 १९०० में लोअर न्यायके २० नगरमें चीफ कोर्ट स्थापित हुए
 अब लाहोर और पटनामें नये हाईकोर्ट स्थापित हो गये
 अथवा, मध्यप्रदेश, पश्चिमोत्तर सोमा प्रदेश, अपर चर्मा,
 मिशनर्स कोर्ट हैं । यद्यपि

अभियुक्तों को प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द करते हैं, उनके विचारके लिये हाईकोर्ट का एक जज द्वारा जज नियुक्त होता है। परन्तु अपने एकसद्व्यवहार अर्द्धितरी ओरिजिनल और अपीलेट जुरिस्टिकशनसे हाईकोर्ट अपने लेटर्स पेटेंटमें निर्धारित सीमाके अन्तर्गत सब दीवानों और फौजदारी अदालतोंका नियंत्रण करते हैं। यदि भारत सरकार कोई कानून बना दे, तो हाईकोर्ट मालगुजारीके किसी मामले या देशकी प्रचलित रीति वा प्रचलित नियमके अनुसार मालगुजारी वसूल करनेके लिये दी हुई आज्ञा वा किये हुए कामका अपने ओरिजिनल जुरिस्टिकशनके अनुसार विचार नहीं कर सकते। अपने अपीलेट जुरिस्टिकशनसे हाईकोर्ट सब न्यायालयोंका नियंत्रण और निरीक्षण करते हैं। वे रिटर्न (गोणवारा) भगा सकते, किसी अदालतमें दायर किसी मामले या अपील को दूसरी वैसी ही या उससे बड़ी अदालतमें भेज सकते हैं। ऐसी अदालतोंकी रीतरवाज और कामका ढंग ठीक करनेके लिये नियम बनाने वा जारी कर सकते हैं और उन अदालतोंके शरीफों, पेढारियों और सब क्लर्कों और अफसरोंकी फौसका निर्णय मुफरर करते हैं। उन सबके लिये पहले प्रादेशिक सरकारोंकी स्वीकृति ले लेनी पड़ती है। यदि गवर्नर-जेनरल और गवर्नरों तथा उनकी कौन्सिलोंके मेम्बरोंने अपने पदके कारण कोई परामर्श दिया हो या कार्य किया हो, तो हाईकोर्टके ओरिजिनल जुरिस्टिकशनकी सत्ता उनपर नहीं चल सकती। दीवानी

दर्जा है। मुन्सिफकी अदालतमें १,०००) से ५,०००) तकका मामला दायर हो सकता है, पर सवार्डिनेट जजकी अदालतमें बड़ेसे बड़ा मामला दायर हो सकता है। यद्यपि जिला जजका दर्जा इससे बड़ा है, तथापि उसकी अदालतमें १०,०००) से अधिकका मुकद्दमा नहीं दायर हो सकता। जिला जजके यहाँ मुन्सिफों और सबजजोंके फैसल किये हुए छोटे मुकद्दमोंकी अपीलें हो सकती हैं। सब-जजों और जिला जजोंके फैसल किये हुए १०,०००) से बड़े मुकद्दमोंकी अपील हाईकोर्टमें होती है। थोड़े थोड़े रूपोंके मुकद्दमोंके लिये प्रेसिडेन्सी शहरों और बड़े शहरोंमें “कोर्ट आफ स्माल कालेज” या छोटी अदालत या अदालत एफोफा है।

जिस तरह दीवानी मुकद्दमे फैसल करनेके लिये जिलेमें सबसे बड़ा अफसर जिला जज है, फौजदारी अदालतें। वसी तरह फौजदारी मामलोंके लिये दीरा जज है। कहीं कहीं तो हर जिलेके लिये दीरा जज है और कहीं कहीं कई जिलोंके लिये एक ही दीरा जज होता है। जब जिला जज, फौजदारी मामले सुनता है, तब वह दीरा जज कहाता है। कहीं कहीं उसके सहायतार्थ पेडिशनल, ज्वायंट या ऐसिस्टेंट सेशनस जज भी नियुक्त हैं। दीरा जजोंके नीचे मैजिस्ट्रेट होते हैं। ये मैजिस्ट्रेट तीन तरहके हैं, प्रथम श्रेणीके, द्वितीय श्रेणीके और तृतीय श्रेणीके। जिला मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणीका मैजिस्ट्रेट होता है।

६. शहरमें राज्य

दोनों प्रकारके न्यायालयोंके अधिकार और काम हाईकोर्टसे ही हैं, तथापि इनकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं है और दोनोंमें चीफ कोर्टकी मर्यादा अधिक है। पुराने हाईकोर्टोंके न्यायपर लोगोंकी श्रद्धा है और वे समझते हैं कि वहा दूधका दूध और पानीका पानी हो जाता है। यह उनके राजकीय न्यायालय होनेका प्रताप है। मध्य प्रदेशके लोगोंकी ओरसे बड़ी व्यवस्थापिका सभामें प्रस्ताव किया गया था कि वहा जुडीशल कमिशनरीके बदले चीफ कोर्ट स्थापित किया जाय। कलकत्ता हाईकोर्टको छोड़ सब हाईकोर्टोंका प्रादेशिक सरकारोंसे सम्बन्ध है और इसी कारण ये उतने स्वतन्त्र नहीं समझे जाते। कुछ समयसे इस आशयका आन्दोलन होता है कि कलकत्ता हाईकोर्टके समान सब हाईकोर्टोंका भारत सरकारसे साक्षात् सम्बन्ध रखा जाय। हाईकोर्ट और उनके समान न्यायालय सब प्रकारका दण्ड दे सकते हैं।

हाईकोर्टके नीचे कई दीवानी और फौजदारी अदालतें हैं।

हर जिलेमें एक डिस्ट्रिक्ट या जिला दीवानी अदालतें। जज होता है, जो जिलेभरके न्याया-

लयोंका नियन्त्रण करता है। उसकी बदालत जिलेमें सबसे बड़ी दीवानी अदालत है, जिसमें नीचेकी अदालतोंके फैसलोंकी अपील हो सकती है। जिला जजके नीचे सर्जिस्ट्रेट जज या सब-जज होते हैं। सब जजको सदरथाला भी कहते हैं। इनके नीचे मुग्लिफोंका

दर्जा है। मुन्सिफकी अदालतमें १,०००) से ५,०००) तकका मामला दायर हो सकता है, पर सवार्डिनेट जजकी अदालतमें बड़ेसे बड़ा मामला दायर हो सकता है। यद्यपि जिला जजका दर्जा इससे बड़ा है, तथापि उसकी अदालतमें १०,०००) से अधिकका मुकद्दमा नहीं दायर हो सकता। जिला जजके यहां मुन्सिफों और सचजजोंके फैसल किये हुए छोटे मुकद्दमोंकी अपीलें हो सकती हैं। सब जजों ओर जिला जजोंके फैसल किये हुए १०,०००) से बड़े मुकद्दमोंकी अपील हाईकोर्टमें होती है। थोड़े थोड़े रुपयेके मुकद्दमोंके लिये प्रेसिडेन्सी शहरों और बड़े शहरोंमें “कोर्ट आफ स्माल कालेज” या छोटी अदालत या अदालत एफोफा है।

जिस तरह दीवानी मुकद्दमे फैसल करनेके लिये जिलेमें फौजदारी अदालतें। सबसे बड़ा अफसर जिला जज है, उसी तरह फौजदारी मामलोंके लिये दीरा जज है। कहीं कहीं तो हर जिलेके लिये दीरा जज है और कहीं कहीं कई जिलोंके लिये एक ही दीरा जज होता है। जब जिला जज, फौजदारी मामले सुनता है, तब वह दीरा जज कहाता है। कहीं कहीं उसके सहायतार्थ ऐडिशनाल, उपायट या ऐसिस्टेंट सेशनस जज भी नियुक्त हैं। दीरा जजोंके नीचे मैजिस्ट्रेट होते हैं। ये मैजिस्ट्रेट तीन तरहके हैं, प्रथम श्रेणीके, द्वितीय श्रेणीके और तृतीय श्रेणीके। जिला मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणीका मैजिस्ट्रेट होता है। प्रेसिडेन्सी शहरमें पास

दोनों प्रकारके न्यायालयोंके अधिकार और काम हाईकोर्टसे ही हैं, तथापि इनकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं है और दोनोंमें चीफ कोर्टकी मर्यादा अधिक है। पुराने हाईकोर्टोंके न्यायपर लोगोंकी श्रद्धा है और वे समझते हैं कि वहां दूधका दूध और पानीका पानी हो जाता है। यह उनके राजकीय न्यायालय होनेका प्रताप है। मध्य प्रदेशके लोगोंकी ओरसे बड़ी व्यवस्थापिका सभामें प्रस्ताव किया गया था कि वहां जुडीशल कमिशनरीके बदले चीफ कोर्ट स्थापित किया जाय। कलकत्ता हाईकोर्टको छोड़ सब हाईकोर्टों का प्रादेशिक सरकारोंसे सम्बन्ध है और इसी कारण ये उतने स्वतन्त्र नहीं समझे जाते। कुछ समयसे इस आशयका आन्दोलन होता है कि कलकत्ता हाईकोर्टके समान सब हाईकोर्टों का भारत सरकारसे साक्षात् सम्बन्ध रखा जाय। हाईकोर्ट और उनके समान न्यायालय सब प्रकारका दण्ड दे सकते हैं।

हाईकोर्टके नीचे कई दीवानी और फौजदारी अदालतें हैं।

हर जिलेमें एक डिस्ट्रिक्ट या जिला दीवानी अदालतें। जज होता है, जो जिलेभरके न्यायालयोंका नियन्त्रण करता है। उसकी

अदालत जिलेमें सबसे बड़ी दीवानी अदालत है, जिसमें नीचेकी अदालतोंके फैसलोंकी अपील हो सकती है। जिला जजके नीचे सैवार्डिनेट जज या सब जज होते हैं। सब जजको सदरमाला भी कहते हैं। इनके नीचे मुग्सिफोंका

सप्तम अध्याय



पुलिस और जेल ।

पहले कहा जा चुका है कि मैजिस्ट्रेटका काम अपने पुलिस और जेलका जिलेमें शान्ति रखना और अपराधियोंका दमन करना है। यह प्रयोजन । काम जिस दुलही सहायतासे किया जाता है, उसे पुलिस कहते हैं। यदि पुलिस न हो, तो दुष्टोंका दमन और शिष्टोंका संरक्षण सम्भव नहीं है, क्योंकि यद्यपि अपराधियोंको दण्ड देनेके लिये न्यायालय हैं, तथापि जबतक फौज उन्हें पकड़कर न्यायालयोंमें नहीं ले जाता, तब तक कुछ नहीं करते। न्यायालयोंका काम अभियुक्तोंका विचार कर अपराधियोंको दण्ड देना मात्र है, अपराधियोंका पकड़ना नहीं। अपराधियोंको पोजना और उनपर अभियोग लगाकर उन्हें न्यायालयमें ले जाता पुलिसका काम है। यदि पुलिस अपना कर्तव्य पालन न करे, तो देशमें असत्य न्यायालय स्थापित हो जानेसे भी शिष्टोंकी रक्षा नहीं हो सकती। पुलिसके साथ ही और एक संस्थाका प्रयोजन है। इसका समाजमें अशान्ति उत्पन्न करते हैं

कसका हक पहुचता है इसका फसला दीवानी अदालतें कर सकती हैं। इसके सिवा और सब तरहके माली मामले माल गुजारांके अफसर तय करते हैं।

भारत सरकारको कानूनी मामलोमे सलाह देनेवाले सबसे सरकारके कानूनी वडे अफसर व्यवस्था सदस्य हैं। कानूनोंके जो मसविदे कौन्सिलमें पेश सजाही। होते हैं, वे इनकी निरीक्षकतामें ही

नैयार किये जाते हैं और सिलेक्ट कमिटियोंमें ये अध्यक्षका आसन ग्रहण करते हैं। परन्तु कौन्सिलके बाहर सरकारको इन विषयोंका परामर्श देनेवाले बगालके ऐडवोकेट-जेनरल हैं। जजोंकी भांति इन्हें भी श्रीमान् सम्राट् ही नियुक्त करते हैं। कलकत्तेमें इनके सहायतार्थ एक "स्टैंडिंग कौन्सेल" और एक "गवर्नमेंट सालिसिटर" नियुक्त किया जाता है। बगाल सरकार भी इन तीनोंसे सम्मति लेती है, पर इनके सिवा उसने एक लीगल रिमेम्ब्रैन्सर और एक डिप्टी लीगल रिमेम्ब्रैन्सर भी नियुक्त कर रखा है। पहला सिविलियन और दूसरा चैरिस्टर है। मद्रास और बम्बईमें भी ऐडवोकेट-जेनरल और गवर्नमेंट सालिसिटर हैं, पर स्टैंडिंग कौन्सेल नहीं है। बम्बईमें बङ्गालकी तरह लीगल रिमेम्ब्रैन्सर है। ये दोनों सिविलियन हैं। युक्तप्रदेशमें एक सिविलियन लीगल रिमेम्ब्रैन्सरके सिवा गवर्नमेंट ऐडवोकेट और ऐसिस्टेंट ऐडवोकेट हैं। पञ्जाब और घर्मांमें भी गवर्नमेंट ऐडवोकेट है।

मुर्शिदाबादसे कलकत्ते ले आये, तब जमीन्दारोंके इरदले जिलोंमें यूरोपियन मैजिस्ट्रेट नियुक्त करके उनके नीचे कई दरोगा और चपरासी रख दिये । हर जिला धानोंमें बांट दिया गया और हर धाना एक दरोगाके अधीन हुआ, जिसे सरकारसे पर्वसे कुछ कान्सटेबल रखनेका अधिकार मिला । प्रत्येक धानेमें २० वर्ग मील भूमि होती थी । शहरोंमें कोतवाल और शहरके हर धानेके लिये दरोगा नियुक्त होते थे । पश्चिमोत्तर प्रदेशमें भी बङ्गालकी पुलिस पद्धतिका अनुकरण किया गया । १८०८ में बङ्गालके डिवाइजनोंमें एक पुलिस सुपरि-टेंडेंट नियुक्त हुआ । यह भेदियों और चरोके द्वारा भेद लेकर डाकूओंका दमन करता था । दरोगों और चपरासियोंके अधिकार कम कर दिये गये । पर बङ्गालमें पुलिसकी इस व्यवस्थासे भी डाके, लूटपाट और चूनखराबी बन्द न हुई । इस लिये १८१३ में फोर्ट आर्थर डार्रेकर्टने इस विफलताके कारणोंके अनुसन्धानके लिये कई डाइरेक्टरोकी एक कमिटी बनायी । हमारे चर्च बोर्डने आज्ञापत्र प्रचारित किया, जिसमें दरोगों और उनके सहकारियोंकी नियुक्तिकी निन्दा की और इनका बडा जोर दिया कि प्रत्येक गावमें गाव पुलिस रखी जाय, क्योंकि उसीसे आन्तरिक शान्ति हो सकती है । इनके समर्थनमें उनसे यह भी कहा कि गाव पुलिसको शान्ति स्थापन करनेमें गाववालोंसे सहायता मिलनी है, क्योंकि यह उनके लिये शान्ति है और जो

अथवा जिनके स्वतन्त्र रहनेसे शान्तिभङ्गकी सम्भावना है, उन्हें बन्दी करके जिस घरमें रखते हैं, वह जेल कहाता है। जेलको “बड़ा घर” या “विना किरायेका घर” भी कहते हैं। यदि जेल न हो, तो पुलिस और न्यायालय लाप चेष्टा करनेपर भी शिष्टोंकी रक्षा नहीं कर सकते। इस लिये लिये जैसे निरपेक्ष न्यायालयों और कार्यदक्ष आवश्यकता है, वैसे ही अपराधियोंको बन्दी रखने जेलोंका प्रयोजन है।

अङ्ग्रेजी राज्यमें जितनी सरथाएं हैं,

बंगाल पुलिसका क्योंकि जो स्वरूप
पहला सघटा। देखा रहे हैं, वह
दृष्टा है।

यात है। अङ्ग्रेजोंके इस देशका
पहले ग्राम पञ्चायतोंका काम देशमें
गावके मुखिया और चौकीदारसे यह
काम दे, वहा यह काम

चौकीदार ही
कोतवाल नियुक्त थे
रहते थे। ईन्ट
लेने बाद, जमीन्दारोंको
और उनपर कुल
लार्ड कार्नवालिस निजामत

मुर्शिदाबाद से कलकत्ते ले आये, तब जमीन्दारों के मदले जिलों में यूरोपियन मैजिस्ट्रेट नियुक्त करके उनके नीचे कई दरोगा और चपरासी रख दिये । हर जिला थानों में बांट दिया गया और हर थाना एक दरोगा के अधीन हुआ, जिसे सरकारी पद से कुछ कान्सटेबल रखने का अधिकार मिला । प्रत्येक थाने में २० वर्ग मील भूमि होती थी । शहरों में कोतवाल और शहर के हर थाने के लिये दरोगा नियुक्त होते थे । पश्चिमोत्तर प्रदेश में भी बङ्गाल की पुलिस पद्धति का अनुकरण किया गया । १८०८ में बङ्गाल के डिवीजनों में एक पुलिस सुपरि-टेंडेंट नियुक्त हुआ । यह भेदियों और चरों के द्वारा भेद लेकर डाकुओं का दमन करता था । दरोगों और चपरासियों के अधिकार कम कर दिये गये । पर बङ्गाल में पुलिस की इस व्यवस्था से भी डाके, लूटपाट और खूनखराबी बन्द न हुई । इस लिये १८१३ में कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स ने इस विफलता के कारणों के अनुसन्धान के लिये कई डाइरेक्टर्स की एक कमिटी बनायी । दूसरे वर्ष कोर्ट ने आश्वासन प्रचारित किया, जिसमें दरोगों और उनके सहकायियों की नियुक्ति की निन्दा की और इसपर बड़ा जोर दिया कि प्रत्येक गांव में गांव पुलिस रखी जाय, क्योंकि उसी से आन्तरिक शान्ति हो सकती है । इसके समर्थन में उसने यह भी कहा कि गांव पुलिस को शान्ति रक्षार्थ कार्य में गांववालों से सहायता मिलती है, क्योंकि उनके आचार व्यवहार के अनुसार संघटित होती है और

अथवा जिनके खतन्त्र रहनेसे शान्तिभङ्गकी सम्भावना है उन्हें बन्दी करके जिस घरमे रखते हैं, वह जेल कहाता है। जेलको "पडा घर" या "विना किरायेका घर" भी कहते हैं। यदि जेल न हो, तो पुलिस और न्यायालय लाप चेष्टा करनेपर भी शिष्टोंकी रक्षा नहीं कर सकते। इस लिये शान्तिरक्षाके लिये जैसे निरपेक्ष न्यायालयों और कार्यदक्ष पुलिसकी आवश्यकता है, वैसे ही अपराधियोंको बन्दी रखनेके लिये जेलोका प्रयोजन है।

अङ्गरेजी राज्यमे जितनी सरथाए हैं, सबका इतिहास है, बंगाल पुलिसका क्योंकि जो स्वरूप उनका हम आज देख रहे हैं, वह एक शताब्दीके घाट पहला सघटन। हुआ है। पुलिसके विषयमें भी यही

वात है। अङ्गरेजोंके इस देशका शासनदण्ड ग्रहण करनेके पहले ग्राम पञ्चायतोंका काम देशमे शान्ति रखना था और वे गांवके मुखिया और चौकीदारसे यह काम लेती थीं। जहां बड़े जमीन्दार थे, वहां यह काम पट्टीदारोंके सुपुर्द था। इस प्रकार गांवका चौकीदार ही पुलिसका काम करता था। बड़े बड़े शहरोंमें कोतवाल नियुक्त थे और इनके अधीन बहुतसे कान्सटेबल रहते थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनीने बंगालकी दीवानी लेने बाद जमीन्दारोंको शान्तिरक्षाके उत्तरदायित्वसे मुक्त किया और उनपर कुछ मालगुजारी बढ़ा ली। १७६० में जय लार्ड कार्नवालिस निजामत (फौजदारी) अदालत

कर तहसिलदारोंके पास भेज दिया करो । यूरोपियन मैजिस्ट्रेटोंके निरीक्षणमें ये अपने जिलेकी पुलिसके मुगिये नियुक्त होते थे । १८२७ में मद्रासका अनुकरण किया, पर शासकोंके अधीन न करके यहा पुलिस सदर फौजदारी अदालतके निरीक्षणमें रखी गयी । १८४२ के बाद जब सिन्धके शासनप्रबन्धका भार सर चार्ल्स नेपियरको दिया गया, तब उन्होंने तबे ढङ्गसे वहा पुलिसका सघटन किया । उन्होंने सरकारका एक पुलिस विभाग बना डाला, और उससे न्यायालयोंका कई सम्बन्ध न रखा । १८५७ में बम्बई सरकारने भी यही किया । इस पद्धतिमें पुलिसके कामोंके लिये जिला एक सुपरिटेंडेंटके अधीन किया गया, जो जिलेकी पुलिसका अफसर बनाया गया और साधारणतः जिला मैजिस्ट्रेटके अधीन रहा । इसी प्रकार हर ताल्लुकेके लिये एक पुलिस अफसर नियुक्त हुआ और उसका मामलतदारसे वही सम्बन्ध रखा गया, जो सुपरिटेंडेंटसे मैजिस्ट्रेटका था । पुलिस विभाग फौजदारी अदालतकी अधीनतासे अलग कर सरकारका विभाग बनाया गया । बाद इसमें कुछ दोष देख पड़े, इससे पुलिसका प्रबन्ध पुलिस कमिशनरको सौंपा गया, जो जेलोंका इन्स्पेक्टर भी था । मद्रासमें लोगोंपर पुलिसके बड़े अत्याचार होने लगे और उनकी जाचके लिये एक कमीशन बैठा, जो पीछे “टार्चर कमीशन” प्रसिद्ध हुआ । इस लिये १८५६ में बम्बईके अनुकरणपर मद्रासमें भी सुधार हुए । अन्य

पुलिस इस तत्वपर संघटित न होगी, उसमें त्रुटियाँ रहेंगी ही तथा बड़े भारी प्रान्तमें स्थित कुछ दरोगों और चपरासियों द्वारा सामाजिक शान्तिरक्षा असम्भव है, जिनका न लोगोंपर प्रभाव है और न उनसे सम्यन्ध ही है और जो मैजिस्ट्रेटकी दृष्टि और नियन्त्रणसे बहुत दूर रहते हैं, तथा उपयुक्त वेतन न पानेके कारण प्रतिष्ठित पुरुष यह कार्य नहीं करते और उन्त कर्मचारियोंके लिये बहुतसे प्रलोभन रहते हैं जिनसे वे कर्त्तव्य च्युत हो जाते हैं। बङ्गालमें इसके अनुसार कोई विशेष कार्य न हुआ। १८२६ में सुपरिटेण्डेंट हटाये गये और डिवीजनोके कमिशनर नियुक्त हुए और कलेक्टर-मैजिस्ट्रेट पुलिसका मुखिया बना दिया गया और डिवीजनल कमिशनर सुपरिटेण्डेंटोका काम करने लगे, पर पुलिसमें सन्तोषजनक सुधार न हुए। कोर्ट आव डाइरेक्टर्सका ध्यान इस ओर फिर आकृष्ट हुआ। फिर कमिटिया बनीं। कमिटियोंकी सूचनाओंपर कई वर्ष कोई काररवाई न हुई। उस समय अवस्था यह थी कि पुलिसका सघटन अपूर्ण था और मैजिस्ट्रेटोंपर कार्यभार इतना अधिक था कि वे पुलिसके कामोंका निरोक्षण नहीं कर सकते थे। पहले पहल प्रेसिडेन्सी नगरोंमें पुलिस सुपरिटेण्डेंट और मैजिस्ट्रेटके कामोंका विभाग हुआ।

१८६१ तक बङ्गाल पुलिसके सघटनमें परिचर्त्तन न हुआ। अन्य प्रदेशोंकी परन्तु मद्रास प्रेसिडेन्सीने कोर्टकी पुलिसका सघटन। धात मान ली, दरोगोंको अलग किया और ग्राम पञ्चायतों पुनर्जीवित कीं। गावके मुखियोंको आज्ञा हुई कि अपराधियोंको पकड़ पकड़-

कर तहसिलदारके पास भेज दिया करे । यूरोपियन मैजिस्ट्रेटोंके निरीक्षणमें ये अपने जिलेकी पुलिसके मुखिये नियुक्त होते थे । सम्यन्त्र १८०७ में मद्रासका अनुकरण किया, पर शासकोंके अधीन न करके यहा पुलिस सदर फौजदारी अदालतके निरीक्षणमें रखी गयी । १८४२ के बाद जब सिन्धके शासनप्रबन्धका भार सर चार्ल्स नेपियरको दिया गया, तब उन्होंने नये ढङ्गसे यहा पुलिसका संघटन किया । उन्होंने सरकारका एक पुलिस विभाग बना डाला, और उससे न्यायालयोंका फार्ड सम्यन्ध न रखा । १८५५ में यन्त्रई सरकारने भी यही किया । इस पद्धतिमें पुलिसके कामोंके लिये जिला एक सुपरिटेंडेंटके अधीन किया गया, जो जिलेकी पुलिसका अफसर बताया गया और साधारणतः जिला मैजिस्ट्रेटके अधीन रहा । इसी प्रकार हर ताल्लुकेके लिये एक पुलिस अफसर नियुक्त हुआ और उसका मामलतदारसे घटी सम्यन्ध रखा गया, जो सुपरिटेंडेंटसे मैजिस्ट्रेटका था । पुलिस विभाग फौजदारी अदालतकी अधीनतासे अलग कर सरकारका विभाग बनाया गया । बाद इसमें कुछ दोष देख पड़े, इससे पुलिसका प्रबन्ध पुलिस कमिशनरको सौंपा गया, जो जेलोंका इन्स्पेक्टर भी था । मद्रासमें लोगोंपर अत्याचार होने लगे और उनकी जाचके लिये बैठा, जो पीछे "ट्रार्चर कमीशन" प्रसिद्ध हुआ

पुलिस इस तत्त्वपर सघटित न होगी, उसमें झुटिया रहेंगी ही तथा बड़े भारी प्रान्तमें स्थित कुछ दरोगों और चपरासियों द्वारा सामाजिक शान्तिरक्षा असम्भव है, जिनका न लोगोंपर प्रभाव है और न उनसे सम्बन्ध ही है और जो मैजिस्ट्रेटकी दृष्टि और नियन्त्रणसे बहुत दूर रहते हैं, तथा उपयुक्त वेतन न पानेके कारण प्रतिष्ठित पुरुष यह कार्य नहीं करते और उन्त कर्मचारियोंके लिये बहुतसे प्रलोभन रहते हैं जिनसे वे कर्त्तव्य च्युत हो जाते हैं। बङ्गालमें इसके अनुसार कोई विशेष कार्य न हुआ। १८२६ में सुपरिटेण्डेंट हटाये गये और डिवीजनोके कमिशनर नियुक्त हुए और कलेक्टर मैजिस्ट्रेट पुलिसका मुखिया बना दिया गया और डिवीजनल कमिशनर सुपरिटेण्डेंटोंका काम करने लगे, पर पुलिसमें सन्तोषजनक सुधार न हुए। फोर्ट आब डाइरेक्टर्सका ध्यान इस ओर फिर आकृष्ट हुआ। फिर कमिटिया बनीं। कमिटियोंकी सूचनाओंपर कई वर्ष कोई काररवाई न हुई। उस समय अवस्था यह थी कि पुलिसका सघटन अपूर्ण था और मैजिस्ट्रेटोंपर कार्यभार इतना अधिक था कि वे पुलिसके कामोंका निरीक्षण नहीं कर सकने थे। पहले पहल प्रेसिडेन्सी नगरोंमें पुलिस सुपरिटेण्डेंट और मैजिस्ट्रेटके कामोंका विभाग हुआ।

१८६१ तक बङ्गाल पुलिसके सघटनमें परिवर्तन न हुआ।

अन्य प्रदेशोंकी परन्तु मद्रास प्रेसिडेन्सीने फोर्टकी पुलिसका सघटन। बात मान ली, दरोगोंको अलग किया और ग्राम पञ्चायतों पुनर्जीवित कीं। गांवके मुखियोंको आज्ञा हुई कि अपराधियोंको पकड़ पकड़-

जिल्लोका एक रेंज होता है। डिपटी इन्स्पेक्टर जनरल सुपरिटेंडेंटोंसे चुना जाता है। उसका मासिक वेतन १,५०० से १,८०० तक है। हर जिलेमें जिला सुपरिटेंडेंट होता है, जो पुलिसके भीतरी प्रबन्ध और विनयानुशासनका उत्तरदाता है तथा शान्तिरक्षा और अपराधियोंका पता लगाने तथा उनका दमन करनेमें जिला मैजिस्ट्रेटके अधीन है। इसे प्रतिमास ७०० से १,२०० तक वेतन मिलता है। इसके एक या अधिक सहायक होते हैं, जो ऐसिस्टेंट और डिपटी सुपरिटेंडेंट कहाते हैं। १८६३ के पहले सुपरिटेंडेंट और ऐसिस्टेंट पलटनिये अफसर होते थे, पर इस वर्षसे ऐसिस्टेंट सुपरिटेंडेंटकी भी प्रतियोगी परीक्षा लण्डनमें होने लगी। हिन्दुस्थान आनेपर इन्हें देशभाषा, कानून, जीन सचारी और कथायदकी परीक्षाएं पास करनी पडती हैं और पास होनेपर ये स्थायी रूपसे नियुक्त होते हैं। इनका मासिक वेतन ३०० से ५०० तक है। १६०६ से पुलिस अफसरोंकी शिक्षाके लिये ट्रेनिंग स्कूल स्थापित हैं। डिपटी सुपरिटेंडेंट हिन्दुस्थानी मैजिस्ट्रेट अफसर होता है। यह पुलिस कमीशनके प्रस्तावसे नियुक्त हुया है। यह यातो इन्स्पेक्टरोंसे चुना जाता है या मेट्रल पुलिस स्कूलमें शिक्षा प्राप्तकर मनोनीत होता है। इसका मासिक २५० से ५०० तक है। सब जिले तीन तीन, चार चार चार एक्कोंमें और बड़े जिले दो दो होते हैं। एक सब डिवीजन ऐसिस्टेंट

उन्नत कर उनसे पुलिसका काम लेनेकी आवश्यकता और पुलिसको शीघ्र ऐसा उन्नत करनेका प्रयोजन बताया जिससे लोगोंको उसपर विश्वास हो । १९०५ में भारत सरकारने कमीशनकी सूचनाओंपर जो मन्तव्य प्रकाशित किया, उसमें उसकी बहुतसी बातें तो मान लीं, पर कहा कि पुलिसकी अयोग्यता और घूस लेनेकी बातें अतिरञ्जित हैं ।

कमीशनकी जो सूचनाएँ सरकारने स्वीकार कर लीं,

उनसे पुलिसका खर्च १॥ करोड़ और

पुलिसका सघटन । बढ़ गया । इनके बादसे भी पुलिसका

खर्च और बढ़ा है । परन्तु प्रजाका

विश्वास पुलिसपर अब भी नहीं है और इससे उसकी सहानुभूति भी नहीं है । इनका कारण यह है कि पुलिस अपनेको प्रजासेवक नहीं, प्रत्युत प्रजारवामों समझती है और इस अधिकारमदमें बहुतसे अनुचित कार्य कर डालती है । कमीशनने इसको जित आदतोकी शिक्षा दी थी, उनमें भी बहुतोंने इसका पीछा नहीं छोड़ा है । खर्चके दृष्टिसे पुलिसकी योग्यता और कार्यक्षमतामें उन्नति नहीं हुई है । सब प्रदेशोंकी पुलिस प्रादेशिक सरकारोंके अधीन है । पुलिस विभागका मुखिया इन्स्पेक्टर जेनरल करता है । उसे २,००० से ३,००० मासिक वेतन मिलता है । यह या तो पुलिस अफसर या सिविलियन होता है । समस्त प्रदेश "रेंजोंमें" बंटा होता है, जो डिप्टी इन्स्पेक्टर-जेनरलके अधीन होते हैं । ८१२

जिल्लाका एक रेंज होता है। डिपटी इन्स्पेक्टर जनरल सुपरिटेंडेंटोंसे चुना जाता है। उसका मासिक वेतन १,५०० से १,८०० तक है। हर जिलेमें जिला सुपरिटेंडेंट होता है, जो पुलिसके भीतरी प्रबन्ध और चिनयानुशासनका उत्तरदाता है तथा शान्तिरक्षा और अपराधियोंका पता लगाने तथा उनका दमन करनेमें जिन्ना मैजिस्ट्रेटके अधीन है। इसे प्रतिमास ७०० से १,२०० तक वेतन मिलता है। इनके एक या अधिक सहायक होते हैं, जो पेसिस्टेंट और डिपटी सुपरिटेंडेंट कहाते हैं। १८६३ के पहले सुपरिटेंडेंट और पेसिस्टेंट पलटनिये अफसर होते थे, पर इस वर्षसे पेसिस्टेंट सुपरिटेंडेंटकी भी प्रतियोगी परीक्षा लण्डनमें होने लगी। हिन्दुस्थान आनेपर इन्हें देशभाषा, कानून, जीन सवारी और कवायदकी परीक्षाएँ पास करनी पडती हैं और पास होनेपर ये स्थायी रूपसे नियुक्त होते हैं। इनका मासिक वेतन ३०० से ५०० तक है। १६०६ से पुलिस अफसरोंकी शिक्षाके लिये ट्रेनिंग स्कूल स्थापित हैं। डिपटी सुपरिटेंडेंट हिन्दुस्थानी गैजेटेड अफसर होता है। यह पुलिस कमीशनके प्रस्तावसे नियुक्त हुमा है। यह यातो इन्स्पेक्टरोंसे चुना जाता है या सेंट्रल पुलिस स्कूलमें शिक्षा प्राप्तकर मनोनीत होता है। इसका मासिक २५० से ५०० तक है। सब जिले तीन तीन चार चार चार हक्कोंमें और बड़े जिले दो दो डिवीजनोंमें बटे होते हैं। एक सब डिवीजना पेसिस्टेंट

सुपरिटेण्डेंटको सौंपा जाता है । हर हल्केमें ४।५ थाने होते हैं । यह इन्सपेक्टरके और थाना सब इन्सपेक्टरके अधीन होता है । इन्सपेक्टरका मासिक वेतन १५०) से २१०) तक और सब इन्सपेक्टरका ५०) से १००) तक है । सब इन्सपेक्टर पुलिस स्टेशन या थानेका अरुसर कहाता है । जिन अपराधोंके अपराधियोंको पकड़नेके लिये मैजिस्ट्रेटके वारंटका प्रयोजन नहीं होता, उनकी जांच करना, शान्ति रखना और अपराध रोकना सब इन्सपेक्टर काम है । १९०६ तक सब इन्सपेक्टर हेड कान्सटेबलोंसे चुना जाता था, पर कमोशनकी सूचनाके अनुसार अब अच्छे घरानेके भाग्यवासी सब-इन्सपेक्टरमें भर्ती किये जाते हैं । फी सैगडे ८० सब इन्सपेक्टर मनोनीत होते हैं । ये साल डेढ़ नाल ट्रेनिंग स्कूलमें काम सीखते हैं और फिर थानेका काम सीखने भेजे जाते हैं । इन्सपेक्टर सब इन्सपेक्टरोंसे चुना जाता है । सब इन्सपेक्टरके नीचे एक हेड कान्सटेबल और कई कान्सटेबल होते हैं । कान्सटेबलोंसे ही हेड कान्सटेबल चुना जाता है । कान्सटेबल और हेड कान्सटेबलका मासिक वेतन क्रमशः १०) से १२) और १५) से २०) है । कई जातियोंके लोगोंको कान्सटेबलोंमें भर्ती करनेका नियम नहीं है और जाति विशेष, अपनी ही जातिके आदमी पुलिसमें नहीं भर सकती । सी० आई० डी० के जवान भी इसी तरह भर्ती होते हैं । यह विभाग डिप्टी इन्सपेक्टर जनरलके दर्जेके यूरोपियन अरुसरके अधीन होता है । यह राजनीतिक

मामलों और राजद्रोहके मुकद्दमोंकी जाच करता और ऐसे अपराधोंपर दृष्टि रखता है जिनका दो तीन जिलोंसे सरोकार होता है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास शहरोंमें खास पुलिस है और उसका प्रादेशिक इन्स्पेक्टर-जनरलसे कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रेसिडेन्सी नगरोंकी यह पुलिस एक कमिशनरके अधीन होती है, जो 'पुलिस कमिशनर' कहा जाता है। इसके अधीन कई डिप्टी कमिशनर होते हैं। ये अनुभवी सुरांगि टैडेंटोंसे चुने जाते हैं। सारा शहर डिवीजनोंमें बंटा रहता है। और हर डिवीजन एक सुपरिटेंडेंटके, पर कलकत्तेमें प्सेसिस्ट्रेंट या डिप्टी कमिशनरके अधीन होता है और उसमें कई गांगे होते हैं। इन गानोंका प्रबन्ध इन्स्पेक्टर या सत्र इन्स्पेक्टरोंको सौंपा जाता है। सड़कोंकी भीड़का प्रबन्ध करनेके लिये गोरी पलटनोंके जवान नियुक्त हैं। ये सजंएट कहाते हैं। इन्हें मामलोंकी जाच करनेका अभिन्ना नहीं हैं। रगूनमें भी पुलिस कमिशनर है। भारत सरकारने पुलिस विभागसे सम्बन्ध रखनेके लिये क्रिमिनल इंटेलिजेन्सका एक डाइरेक्टर नियुक्त कर रखा है। डाइरेक्टर अपने अग्रीन कर्मचारियों समेत प्रादेशिक पुलिससे सम्बन्ध रखता है। यह प्रादेशिक पुलिसके कार्यमें हस्तक्षेप नहीं करता, पर अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों, अन्तरप्रादेशिक अपराधों और राजनीतिक अनुसन्धानोंके समाचार प्रकाशनसे ही सम्बन्ध है।

जिला पुलिस दो भागोंमें विभक्त है, एक आर्म्ड वा सशस्त्र,

सशस्त्र और दूसरा अन-आर्म्ड अशस्त्र । सशस्त्र

अशस्त्र पुलिस । पुलिसका काम खजानोंकी खबरदारी
रखना, खजानों और कैदियोंके साथ

जाना और डाकुओंके दलपर चढ़ाई करना है । इसलिये उसे
अस्त्र दिये जाते हैं और फौजी ढंगपर कवायद करना और
गोली चलाना सिखाया जाता है । अशस्त्र पुलिसका काम
जुर्माना वसूल करना, सम्मन या वारंट तामील कराना,
सड़कोंकी भीड़का वन्दोबस्त करना, आचारा कुत्तोंको मार
डालना, आग बुझाना और जिन अपराधोंके अपराधियोंको
बिना वायंट वह गिरफ्तार नहीं कर सकती, उनकी जांच
करना । निम्न श्रेणीकी पुलिसको वर्दी और रहनेकी जगह
मुफ्त मिलती है । छुट्टीकी व्यवस्था ठीक है, पर पेनशन बिना
बीमारीका सर्टिफिकेट दिये ३० वर्षसे पहले नहीं मिलती ।
कहीं कहीं घुटसवार पुलिस भी होती है । बंगाल, आसाम,
बर्माकी सीमा और पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेशमें फौजी पुलिस
भी रखी जाती है । सप्त प्रदेशोंके गावोंमें चौकीदार रहते हैं ।
बंगालको छोड़ ये सर्वत्र मुखियोंके और युक्त प्रदेशमें लग्न
दारोंके अधीन रहते हैं । भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें गावोंके चौकी
दारोंको भिन्न भिन्न प्रकारसे वेतन मिलता है । कहीं इन
जमीन माफ़ीमें मिली है और कहीं सेमोंसे (करोंसे), इनका
वेतन दिया जाता है । इनका निरीक्षण और नियन्त्रण निय

मित पुलिस नहीं करती, बल्कि यह काम जिलेके कलेक्टर या डेपटी कमिशनरका है । रेलवे पुलिसका भी जिला पुलिससे कोई सम्बन्ध नहीं है, पर दोनोंको परस्परकी सहायता मिलती है । रेलवे पुलिसका व्यय रेलवे देती है और उसका काम स्टेशनोंपर शान्ति रगना तथा रेलवेकी सम्पत्तिकी रक्षा करना मात्र है ।

अपराध दो प्रकारके कहे गये हैं, एक कागनिजेवल और पुलिसके अधिकार दूसरा नान कागनिजेवल । कागनिजेवल अपराधमें पुलिस अभियुक्तको और व्यय । विना वारण्ट गिरफ्तार कर सकती है, पर नानकागनिजेवल अपराधोंमें अभियुक्तको पकड़नेके लिये उसे मैजिस्ट्रेटसे वारंट लेना पड़ता है । कागनिजेवल अपराधमें जाच करनेवाले अफसरका कर्तव्य है कि वह अभियुक्तको मैजिस्ट्रेटके पास ले जाय और यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार करे, तो मैजिस्ट्रेट उसे लिख ले । पर मैजिस्ट्रेटको उचित है कि वह भली भाँति इसे निश्चय कर ले कि अभियुक्त अपनी दृच्छासे अपराध स्वीकार करता है । किसी अभियुक्तको विना मैजिस्ट्रेटकी विशेष आज्ञा २४ घण्टेसे अधिक पुलिस नहीं रोके रखा सकती । मामूली मामलोंमें इन्स्पेक्टर या सभ इन्स्पेक्टर मामला चलाता है, पर बड़े मामलेमें वकील किया जाता है । जो मामले दौरा सुपुर्द होते हैं, वे सरकारी वकील चलाते हैं । अपराधियोंको पकड़नेके सिवा पुलिसका

काम अपराध रोकना भी है, इस लिये उसे पुराने अपराधियों और सन्देहजनक पुरुषों पर सदा दृष्टि रखनी पड़ती है। डाका डालना या चोरी करना जिनकी आजीविका है, उनपर विशेष दृष्टि रखकर उन्हें दण्ड दिलाना पुलिस का कर्त्तव्य है। बरमाओं या डाकुओंके दलको गिरफ्तार कर सजा दिलाना पहले ठगी और डकैती विभागका काम था, पर १९०४ में उक्त विभाग उठ जानेसे अब यह काम सी० आई० डी० को सौंपा गया है। सन् १९२१-२२ में २०३००० आदमी मुक्तो पुलिसमें थे। इनके सिवा फौजी पुलिसमें ३०,००० जवान थे, इनमें आधेसे अधिक बर्गामें थे। १९०५ से पुलिसका खर्च बहुत बढ़ गया है। १९०१-२ में ४,०३,७०,१६०) पुलिसका व्यय था, पर १९११-१२ में ६,६०,४४,६०५) हो गया और तबसे बढ़ ही रहा है।

प्राचीन समयमें सत्तारभरमें अपराधियोंको बड़ा कठोर दण्ड दिया जाता था। भारतवर्षमें जेलोंकी व्यवस्था भी दण्ड देनेमें कम कठोरता नहीं होती थी। अब भी अनेक स्थानोंमें कठमें पात्र दे देनेकी चाल है। अफगानिस्तानमें कैदियोंको गुफाओंमें बन्द कर देनेका नियम कई वर्ष पहलेतक था। इन गुफाओंके ऊपर सिडकीसे उन्हें भोजन दिया जाता था। परन्तु अब ब्रिटिश राजमें इस तत्त्वपर दण्ड दिया जाता है, कि जिसे दण्ड दिया जाय, वह फिर वैसे काम न करे और और

लोग उसकी दुर्दशा देख डरकर घैसा करनेका साहस न कर । इसी तत्पर जेलके नियमोंमें सुधार भी हुए हैं । पहले मद्रास, बम्बई और बङ्गालमें जेलोंके कानून बने थे । इनके अनुसार उक्त प्रदेशोंमें और १८७० में भारत सरकारके बनावे कानूनके अनुसार अवशिष्ट ब्रिटिश भारतमें जेलोंकी व्यवस्था थी । पर सत्र प्रदेशोंके नियमोंमें विभिन्नता बहुत थी, इस लिये १८६४ में भारत सरकारने एक कानून बनाया जिसके अनुसार आजकल जेलोंका प्रबन्ध होता है और इससे विभिन्नता सर्वथा दूर हो गयी है । अब समस्त भारतमें जेलके नियम समान हो गये हैं और जेलके कैदा जो अपराध करते हैं, उनके लिये समस्त भारतकी जेलोंमें दण्डकी एकसी व्यवस्था भी है । १८६६ में भारत सरकारने जेलोंके नियन्त्रणके लिये कुछ नियम जारी किये जिनमें जेलके अपराधोंकी परिभाषा, दण्डके भेदों, मार्क देने और दण्ड घटाने आदिकी बातें थीं । इण्डियन पीनल कोडके अनुसार अपराधियोंको काले पानी, बड़ा गुलामी, सख्त कैद (जिसमें कालकोठरीमें रहनेका दण्ड भी है) और सादी कैदकी सजा मिलती है । दीवानी मामलोंके कैदियों और जिनपर मामला चल रहा है, ऐसे लोगोंको भी जेलमें रखनेकी व्यवस्था है ।

जेलोंके तीन भेद हैं, एक सेंट्रल जेल, दूसरा डिस्ट्रिक्ट जेल और तीसरा सर्जिसडियरी जेल या तीन प्रकारकी जेलें । लाक-अप । सेंट्रल जेलमें वे कैदी रखे जाते हैं जिन्हें एक वर्षसे अधिक कारावासका दण्ड दिया जाता है । डिस्ट्रिक्ट या जिलेकी जेलमें

१५ दिनसे एक वर्षतकके कैदी रखे जाते हैं और नवसिडियरी जेलों या हवालातोंमें १५ दिनसे कमकी सजा पाये कैदियोंके रखनेकी व्यवस्था है। प्रत्येक प्रदेशका जेल विभाग एक इन्स्पेक्टर जेनरलके अधीन होता है। यह इण्डियन मेडिकल सर्विसका डॉक्टर होता और जेलकी व्यवस्थासे परिचित रहता है। जेलमें चार अफसर होते हैं, एक सुपरिटेंडेंट एक मेडिकल अफसर (डॉक्टर), एक उसका सहकारी और एक जेलर। जेल सुपरिटेंडेंट भी प्रायः डॉक्टर ही होता है। इस लिये बहुधा पहले दो पदोंके लिये एक ही व्यक्ति नियुक्त होता है। बहुतेरी डिस्ट्रिक्ट जेलें सिविल सर्जनके अधीन होती हैं और जयपुर जिला मैजिस्ट्रेट उनका निरीक्षण करता है। सेंट्रल जेलोंमें एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहता है, जो जेलमें बनी हुई सब चीजोंकी देखभाल करता है। जेलोंके सिवा वार्डर और कैदी अपास्तर भी पहले दो प्रकारकी जेलोंमें होते हैं। जिन कैदियोंका अच्छा चालचलन होता है, वे कैदी अफसर बनाये जाते हैं। हर कैदीके लिये अलग कोठरी होनी चाहिये यह सिद्धान्त १८६४ के ऐक्टमें रचीकार किया गया था, पर धनाभावके कारण सब प्रदेशोंमें अबतक पूर्ण रूपसे यह आचार्यक सुधार नहीं हुआ है। केवल मद्रासमें यह सुधार हो चुका है। स्त्रियों और लड़कोंको कैद रखनेकी व्यवस्था अलग है। लड़कों और युवकोंमें भी भेद माना गया है और दोनों प्रकारके कैदियोंके लिये स्वतन्त्र व्यवस्था है। कैदियोंके

स्कूलमें रखना भी है, पर ये १८ वर्षसे बड़े न हो जायें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके सिवा, अन्य व्यवस्थाएँ भी हैं, यथा डाट डपटकर छोड़ देना, बेंत मारना और माता पितासे यह प्रतिज्ञापत्र लिखाकर उनके सुपुर्द कर देना कि लड़केकी नेकचलनीके लिये हमें जिम्मेदार हैं। १८६६ से ये रिफार्मेंटरी स्कूल शिक्षा विभागके अधीन हैं। इनमें लड़के कैदियोंको औद्योगिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें यहासे निकलकर वे चार पैसे पैदा कर सकें और भलेमानस बनकर रहें। १६११ में सात प्रदेशोंमें एक एक रिफार्मेंटरी स्कूल था और सातों स्कूलोंमें १,३१७ लड़के थे। दस वर्ष पहले १६०१ में सात स्कूलोंमें १,२२७ थे। लड़कियोंकी संख्या बहुत कम है और मैजिस्ट्र टोंको आज्ञा दी गयी है कि जहातक हो सके, लड़कियोंको डाट डपटकर छोड़ दिया करो या उनके पितामाताको सौंप दिया करो। परन्तु अब १५ वर्षसे बड़े और १८ वर्षसे छोटे लड़के कैदियोंके लिये भी व्यवस्था हुई है। प्रिजन्स ऐक्टमें यह तो कहा गया था कि १८ वर्षसे कम उम्रके लड़के पुराने कैदियोंके साथ न रखे जाय, परन्तु जब प्रादेशिक सरकारोंने देखा कि ये तो रिफार्मेंटरीमें भी नहीं रह सकते, तब इनके लिये बोस्टलकीसी जेल बनानेका विचार किया गया। १६०५ में मद्रास प्रदेशके धारवाड जिलेमें चुने हुए लड़कों और युवकोंकी अलग श्रेणी बनायी गयी, १६०८ में फलकत्तेके पास अलीपुरमें स्पेशल जुविनाइल जेल

दो वर्षों तक उन्हें हल्का काम करना पड़ना है। पाच वर्ष बीत जानेपर वे कमा खा या व्याह कर सकतो हैं। कैदियोंसे जेलकी मरम्मत करायी या इमाग्न बनवायी जाती कमिस रियट, अस्पताल, जलसेना, जङ्गलविभाग, चाय बगीचों या खेतीबाड़ीका काम लिया जाता है। मामूली मर्द कैदीका, जिसे जन्मभरके कालेपानीकी सजा मिलती है, चालचलन अच्छा होता है, तो वह २० वर्ष याद छोड दिया जाता है, पर जो डाका डालने या बल राश्रकार अपराध करनेके दोषी होते हैं, वे २५ वर्ष याद छोडे जाते हैं। ठग और जरायमपेशे लोग कभी नहीं छोडे जाते। नेकचलन औरतें १५ वर्ष याद छोड दी जाती हैं। कमी तो रिना शर्तके कैदी छोडे जाते हैं और कभी विशेषकर डाकुओंसे उनके रहनेकी जगह आदिके रेंगें शर्त कग ली जानी हैं। कभी कभी कैदी स्वतन्त्र

भारत सरकारने १८६१ में ऐसी आशा दे भी दी। पर पीछे भारत सरकारने यह आशा रद्द कर दी, क्योंकि यहां काल कोठरीका बड़ा कड़ा पहरा रखना पड़ता है। ऐसे जिन कैदियोंको डाक्टर पास कर देता है, वे पोर्ट ब्लेयर भेज जाते हैं। स्त्रियोंको वहां भोजनेकी भी कुछ शक्त है। कालेपानीके कदीकी पांच अवस्थाएँ होती हैं। पहली अवस्था छ महीने कालकोठरीमें बीतती है। दूसरी अवस्थामें हिन्दुस्थानके समान ही जेलमें १८ महीने और कैदियोंके साथ काटने पड़ते हैं। तीसरी अवस्थामें तीन वर्षतक दिनको चड़ी कड़ी मिहगत कैदासे ली जाती है और रातको वह बारकोंमें बन्द किया जाता है। इन समय वह तीसरे दर्जेका कैदी कहाता है। उस प्रकार पांच वर्ष बीतनेपर वह दूसरे दर्जेका कैदी माना जा सकता है। इस अवस्थामें वह सरकारी नौकरी पा सकता है या किसी रईसका नौकर हो सकता है। जब इस प्रकार ५ वर्ष बीत चुकते हैं, तब जिस कैदीका चालचलन अच्छा होता है, वह अब्बल दर्जेका कैदी समझा जाने लगता है। इन अवस्थामें या तो उसकी मजूरीके नियम कड़े नहीं होते या उसे एक टिकट मिलता है, जिससे वह कुछ जमीन लेकर उसमें खेती करता और अपना जीविकानिर्वाह करता है। इस अवस्थामें वह अपने जोन वच्चे बुला सकता या किसी औरत कैदीसे व्याह कर सकता है। स्त्रियोंसे तीन वर्षतक जेलके नियमोंके अनुसार काम लिया जाता है। बाद

दो वर्षों तक उन्हें हल्का काम करना पड़ता है। पांच वर्ष बीत जानेपर वे काम खा या व्याह कर सकते हैं। कैदियोंसे जेलकी मरम्मत करायी या इमाग्न बनवायी जाती कमिस रियट, अस्पताल, जलसेना, जङ्गलविभाग, चाय बगीचों या खेतीबाड़ीका काम लिया जाता है। मामूली मर्द कैदीका, जिसे जन्मभरके कालेपानीकी सजा मिलती है, चालचलन अच्छा होता है, तो वह २० वर्ष बाद छोड़ दिया जाता है, पर जो डाका डालने या दल धाँवर अपराध करनेके दोषी होते हैं, वे २५ वर्ष बाद छोड़े जाते हैं। ठा, और जरूरीमपेशे लोग कभी नहीं छोड़े जाते। नैकचला औरतें १५ वर्ष बाद छोड़ दी जाती हैं। कभी तो मिना शर्तके कैदी छोड़े जाते हैं और कभी विशेषकर डाकुओंसे उनके रहनेकी जगह आदिके बारेमें शर्त करा ली जाती है। कभी कभी कैदी स्वतन्त्र होकर वहीं रहना पसन्द करते हैं। १९१० में पोर्टब्लेयरमें ११,२३५ कैदी थे, जिनमें १०,६३३ पुरुष और ६०२ स्त्रिया थी। इनमें १,५६६ पुरुष और २७० स्त्रिया खेती करके अपना गुजर करती थीं। कुल जनसंख्या १५,६१३ थी। पोर्टब्लेयर एक युरोपियन सुपरिटेण्डेंटके अधीन है जिसके नीचे कई युरोपियन और भारतवासी काम करते हैं। १९२१ में जेल कमिटीने कालापानी बन्द कर देने की सम्मति दी थी और सरकारने इसे स्वीकार भी कर लिया था। परन्तु अद्यतक वहाँ कदी भेजे

भारत सरकारने १८६१ में ऐसी आज्ञा दे भी दी । पर पीछे भारत सरकारने यह आज्ञा रद्द कर दी, क्योंकि यहाँ काल कोठरीका बड़ा कड़ा पहरा रखना पड़ता है । ऐसे जिन कैदियोंको डाक्टर पास कर देता है, वे पोर्ट ब्लेयर भेजे जाते हैं । स्त्रियोंको वहाँ भोजनेको भी कुछ शक्ते हैं । कालेधानीके कदीकी पाच अवस्थाएँ होती हैं । पहली अवस्था छ महीने कालकोठरीमें बीतती है । दूसरी अवस्थामें हिन्दुस्थानके समान ही जेलमें १८ महीने और कैदियोंके साथ काटने पड़ते हैं । तीसरी अवस्थामें तीन वर्षतक दिनको 'बड़ी कड़ी' मिहनत कैदासे ली जाती है और रातको वह बारकोंमें बन्द किया जाता है । इन समय वह तीसरे दर्जेका कैदी कहाता है । उस प्रकार पाच वर्ष बीतनेपर वह दूसरे दर्जेका कैदी माना जा सकता है । इस अवस्थामें वह सरकारी नौकरी पा सकता है या किसी खासका नौकर हो सकता है । जब इस प्रकार ५ वर्ष बीत चुकते हैं, तब जिस कैदीका चारबलन अच्छा होता है, वह अठारह दर्जेका कैदी समझा जाने लगता है । इन अवस्थामें या तो उसकी मजूरीके नियम कहे नहीं होते या उसे एक टिकट मिलता है, जिससे वह कुछ जमीन लेकर उसमें खेती करना और अपना जीविकानिर्वाह करता है । इस अवस्थामें वह अपने जोरू बच्चे बुला सकता या किन्नी औरत कैदीसे ब्याह कर सकता है । स्त्रियोंसे तीन वर्षतक जेलके नियमोंके अनुसार काम लिया जाता है । याद

